



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 13

6 चैत्र 1941 (श०)

पटना, बुधवार, —

27 मार्च 2019 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-93
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4-बिहार अधिनियम	---

भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
---	-----

भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
---	-----

भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
--	-----

भाग-9-विज्ञापन	---
----------------	-----

भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
---	-----

भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	94-94
---	-------

पुरक	---
------	-----

पुरक-क	95-112
--------	--------

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

7 मार्च 2019

सं० ई2-4/2004-11 — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार निर्वाचन सेवा नियमावली, 2006 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:- (1) यह नियमावली बिहार निर्वाचन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019 कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. बिहार निर्वाचन सेवा नियमावली, 2006 के नियम 5 के उप नियम (1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है—
“(1) बिहार निर्वाचन सेवा का मूल पद अवर निर्वाचन पदाधिकारी का पद होगा। किसी वर्ष में विद्यमान इस पद की सभी रिक्तियाँ सीधी भर्ती द्वारा भरी जायेंगी।
नोट— सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भरी जाने वाली पूर्व की रिक्तियाँ भी सीधी भर्ती द्वारा भरी जायेंगी।”
3. बिहार निर्वाचन सेवा नियमावली, 2006 के नियम 7 के उप नियम (1) में प्रयुक्त शब्द “एवं सीमित” तथा नियम 7 का उप नियम (3) पूर्ण रूप से एतद् द्वारा विलोपित किये जाते हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रत्नेश झा, संयुक्त सचिव।

The 7th March 2019

No. E2-4/2004- 11---In exercise of the powers conferred under the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Election Service Rules, 2006.

1. Short title, extent and commencement –
(1) This Rule shall be called The Bihar Election Service (Amendment) Rule, 2019.
(2) It shall extend to whole of the State of Bihar.
(3) It shall come into force immediately.
2. The sub Rule (1) of Rule 5 of the Bihar Election Service Rule - 2006 shall be substituted by the following :-
“(1) The basic post of the Bihar Election Service shall be the post of Sub Election Officer.
All the existing vacancies of any existing year shall be filled up by direct recruitment.
Note:- All Previous vacancies to be filled up by limited competitive examination shall also be filled by direct recruitment”.
3. The words “and limited” used in the Sub Rule (1) of Rule 7 and entire Sub Rule 3 of Rule 7 of the Bihar Election Service Rules 2006 are hereby deleted.

By order of the Governor of Bihar,
Ratnesh Jha, Joint Secretary.

वित्त विभाग

आदेश

18 मार्च 2019

सं० 01/स्था०(ले०से०)-07/2017-2710/वि०—श्रीमती रूपम, बिहार लेखा सेवा, उपायुक्त, लेखा, भविष्य निधि निदेशालय सम्प्रति प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग को उपायुक्त, लेखा के पद पर वित्त विभाग में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

श्रीमती रूपम, वित्त विभागीय प्रशाखा 3ए एवं 3बी के कार्यों का निर्वहन करेंगी।

2. श्री ब्रजेश, वरीय कोषागार पदाधिकारी, मसौदी को अपने कार्यों के अतिरिक्त वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग का प्रभार दिया जाता है।

प्रस्ताव में माननीय उप मुख्य(वित्त) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,

शिव शंकर मिश्र, संयुक्त सचिव।

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

12 मार्च 2019

सं० 874—निम्नलिखित कोयला मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना जो का०आ० संख्या—1795 तारीख 13 दिसम्बर, 2018 से भारत के राजपत्र भाग—II खण्ड—3 उप खंड (ii) में प्रकाशित हुई है, को सामान्य सूचना के लिए बिहार के राजपत्र में पुनः प्रकाशित किया जाता है।

भारत सरकार कोयला मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 13 दिसम्बर, 2018

का०आ० 1795 —केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित परिक्षेत्र की भूमि में से कोयला अभिप्राप्त किये जाने की संभावना है;

और उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के क्षेत्र में अंतर्विष्ट करने वाला रेखांक संख्या पीबीसीबी/राजस्व योजना/2018—19/01 ए, तारीख 15 नवम्बर, 2018 कर निरीक्षण, महाप्रबंधक (भू-सम्पदा), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद—826005 या महाप्रबंधक, विक्रमशिला क्षेत्र/निदेशक (तकनीकी) योजना और परियोजना के तकनीकी सचिव, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद—826005 या उपायुक्त जिला गोड्डा, झारखण्ड या जिला कलक्टर, भागलपुर, बिहार या महाप्रबंधक (गवेषण प्रभाग), आर० आई—II, केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान, कोयला भवन काम्पलेक्स, कोयला नगर धनबाद—826005 या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता—700001 के कार्यालय में किया जा सकता है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में कोयले का पूर्वक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है।

उपर्युक्त अनुसूची में उल्लिखित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति—

- (i) संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या उक्त भूमि में या उसके ऊपर किसी अधिकार के अर्जन पर आक्षेप कर सकेगा; या
- (ii) उसकी धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन की गयी किसी कार्यवाई से हुई या होने वाली संभावित किसी क्षति के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन प्रतिकर का दावा कर सकेगा; या
- (iii) उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति के प्रभावहीन होने के संबंध में या उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अधीन खनन पट्टे के प्रभावहीन होने के लिए प्रतिकर का दावा कर सकेगा और उसे उक्त अधिनियम की धारा—13 की उप-धारा (1) के खंड (i) से खंड (iv) में विनिर्दिष्ट मदों की बाबत उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिए पूर्वोक्त भूमि से संबंधित सभी मानचित्रों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को परिदत्त कर सकेगा।

इस अधिसूचना के राजपत्र के प्रकाशन के तारीख से नब्बे दिन के भीतर महाप्रबंधक, विक्रमशिला क्षेत्र/निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना के तकनीकी सचिव, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद—826005 अथवा महाप्रबंधक (भू-सम्पदा), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद—826005 (झारखंड) के कार्यालय को भेजेगें।

अनुसूची

पिरपैती—बाराहाट कोल खनन ब्लॉक

जिला—गोड्डा (झारखण्ड) और जिला—भागलपुर (बिहार)

(रेखांक संख्या पीबीसीबी/राजस्व योजना/2018—19/01ए, तारीख 15 नवम्बर, 2018)

1. जिला— गोड्डा, झारखंड

क्र०सं०	मौजा / ग्राम	थाना सं०	ग्राम / थाना सं०	जिला का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में लगभग)	क्षेत्रफल (एकड़ में लगभग)	टिप्पणियां
1	सिवनपुरा / सिमानपुर	महगामां	09	गोड्डा	91.104	225.118	भाग
2	खिरौंधी	महगामां	10	गोड्डा	99.117	244.918	भाग
3	खर्थी	महगामां	11	गोड्डा	79.606	196.706	संपूर्ण
4	परसा	महगामां	12	गोड्डा	185.175	457.567	संपूर्ण
5	अमौर	महगामां	13	गोड्डा	242.029	598.054	संपूर्ण
6	नदीवान	महगामां	14	गोड्डा	26.730	66.050	संपूर्ण
7	खिरौंधा	महगामां	15	गोड्डा	108.725	268.659	भाग
8	सुरनी	महगामां	16	गोड्डा	10.00	24.710	भाग
9	दोई	महगामां	321	गोड्डा	167.271	413.327	भाग
10	दरियाचक	महगामां	330	गोड्डा	23.747	58.680	भाग
11	घोरिचक	महगामां	331	गोड्डा	23.927	59.124	संपूर्ण
12	गौसी प्रतापपुर	महगामां	336	गोड्डा	26.00	64.246	भाग
13	कुमारडीहा	महगामां	338	गोड्डा	99.00	244.629	संपूर्ण
14	उदवाचक	महगामां	339	गोड्डा	19.00	46.949	संपूर्ण
15	चौरा	महगामां	340	गोड्डा	120.953	298.875	संपूर्ण
16	फुदलियाकिता	महगामां	341	गोड्डा	4.610	11.391	संपूर्ण
17	लकड़मारा	महगामां	342	गोड्डा	266.604	658.778	संपूर्ण
18	मजगैन	महगामां	343	गोड्डा	25.00	61.775	संपूर्ण
19	नीमा	महगामां	344	गोड्डा	51.00	126.021	संपूर्ण
20	उदयपुरा बेहरा	महगामां	345	गोड्डा	59.00	145.789	संपूर्ण
21	चितरसेन बेहरा	महगामां	346	गोड्डा	29.00	71.659	संपूर्ण
22	मसुदनपुर घोरिकिता	महगामां	347	गोड्डा	79.50	196.445	आंशिक
23	जिताचक्क	महगामां	348	गोड्डा	8.00	19.768	संपूर्ण
24	दरियापुर	महगामां	349	गोड्डा	86.985	214.940	संपूर्ण
25	धनकुरिया	महगामां	354	गोड्डा	143.648	354.955	भाग
26	सिंगापुर	महगामां	371	गोड्डा	73.581	181.819	भाग
कुल क्षेत्रफल =					2149.312	5310.952	

2. जिला— भागलपुर, बिहार:

क्र०सं०	मौजा / ग्राम	थाना सं०	ग्राम / थाना सं०	जिला का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में लगभग)	क्षेत्रफल (एकड़ में लगभग)	टिप्पणियां
1	कैरिया	कोलगंग	312	भागलपुर	140.594	347.408	भाग
2	महगावां	कोलगंग	313	भागलपुर	145.733	360.106	संपूर्ण
3	विशुनपूर महगावां मिलिक	कोलगंग	314	भागलपुर	17.00	42.007	संपूर्ण
4	करहरा बंसतपुर मिलिक	कोलगंग	315	भागलपुर	1.00	2.471	संपूर्ण
5	वाशुदेवपुर भलुआ अराजी	कोलगंग	316	भागलपुर	18.00	44.478	संपूर्ण
6	करहरा वाशुदेवपुर मिलिक	कोलगंग	317	भागलपुर	12.00	29.652	संपूर्ण
7	भलुआ	कोलगंग	318	भागलपुर	70.00	172.970	भाग
8	भलुआ सुजान	कोलगंग	319	भागलपुर	51.00	126.021	भाग
9	महगावां मिलिक	कोलगंग	332	भागलपुर	13.00	32.123	भाग
10	सेमारिया	कोलगंग	333	भागलपुर	140.00	345.940	भाग
11	कैरिया मिलिक	कोलगंग	334	भागलपुर	16.00	39.536	संपूर्ण
कुल क्षेत्रफल =					624.327	1542.712	

कुल क्षेत्रफल (2149.312 हेक्टेयर+624.327 हेक्टेयर) =27773.639 हेक्टेयर (लगभग)

या (5310.952 एकड़ +1542.712 एकड़) =6853-664 एकड़ (लगभग)

1. 1-2 कैरिया मौजा में बिंदु सं० '1' से रेखा शुरू होकर दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर कैरिया मौजा में बिंदु सं० 2 तक जाती है।
2. 2-3 कैरिया मौजा में बिंदु सं० '2' से रेखा शुरू होकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर कैरिया मौजा में बिंदु सं० 3 तक जाती है।
3. 3-4 कैरिया मौजा में बिंदु सं० '3' से रेखा शुरू होकर उत्तर-पूर्व दिशा में मौजा कैरिया में धुलिया नाला के बिंदु सं० 4 तक जाती है।
4. 4-24 मौजा कैरिया में धुलिया नाला के बिंदु सं० '4' से रेखा शुरू होती है। मौजा-कैरिया, खिरौंधी, शिवनपुर, खिरौंधा, अमौर, नदियावा एवं दोई होते हुए धुलिया नाला के साथ-साथ दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर दोई में राष्ट्रीय उच्च मार्ग (एनएच) -133 पर बिंदु सं० 24 तक जाती है।
5. 24-28 मौजा दोई में बिंदु सं० '24' से रेखा शुरू होती है और राष्ट्रीय राजमार्ग 133 के साथ-साथ दक्षिण दिशा की ओर मौजा दोई, कुमारडिहा, गौसी प्रतापपुर, घोड़ीचक और दरियाचक होते हुए दरियाचक मौजा में बिंदु सं० 28 तक जाती है।
6. 28-29 बिंदु सं०-28' से रेखा शुरू होती है और मौजा दरियाचक, सिंगारपुर, धनकुरिया से होते हुए दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर धनकुरिया मौजा में बिंदु सं० 29 तक जाती है।
7. 29-30 धनकुरिया मौजा में बिंदु सं० '29' से रेखा शुरू होती है और धनकुरिया, दरियापुर, मसुदनपुर घोरिकिता तथा भलुआसुजान मौजा से होते हुए उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर भलुआसुजान मौजा में बिंदु सं० 30 तक जाती है।
8. 30-31 भलुआसुजान मौजा में बिंदु सं० '30' से रेखा शुरू होती है तथा भलुआसुजान एवं भलुआ होते हुए उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर भलुआ मौजा में बिंदु सं०-31 तक जाती है।
9. 31-35 भलुआ मौजा में बिंदु सं०-31' से रेखा शुरू होती है तथा भलुआ और बासदेवपुर भलुआ अराजी मौजा होते हुए उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बासदेवपुर भलुआ अराजी मौजा में बिंदु सं० 35 तक जाती है।
10. 35-39 बासदेवपुर भलुआ अराजी मौजा में बिंदु सं० '35' से रेखा शुरू होती है तथा बासदेवपुर भलुआ अराजी, महागावां मिलिक तथा सिमरिया मौजा से होते हुए उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर मौजा सिमरिया में बिंदु सं० 39 तक जाती है।
11. 39-40 सिमरिया मौजा में बिंदु सं० '39' से रेखा शुरू होती है तथा सिमरिया मौजा से होते हुए उत्तर दिशा की ओर सिमरिया मौजा में बिंदु सं० '40' तक जाती है।
12. 40-1 सिमरिया मौजा में बिंदु सं० '40' से रेखा शुरू होती है तथा सिमरिया एवं कैरिया मौजा होते हुए उत्तर-पूर्व दिशा की ओर (सीमा के प्रारंभिक बिंदु से) कैरिया मौजा में बिंदु सं० 1 में जाकर मिलती है।

[फा०सं०-43015/17/2018-एलए एण्ड आईआर]

आदेश से,

आर० एस० सरोज, अवर सचिव, भारत सरकार ।

राज्यपाल के आदेश से

सुशील कुमार, अवर सचिव।

The 12th March 2019

No. 874 /M---Following Notification issued by Government of India in the Ministry of Coal vide S.O. No. 1795 dated the 13th December 2018 published in the Gazette of India Part- II -section- 3 -sub section (ii) is hereby republished in the official Gazette of Bihar for General information.

**Government of India
Ministry Of Coal
Notification**

New Delhi, the 13th December, 2018

S.O. 1795. - Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands in the locality described in the Schedule annexed to this notification;

And, whereas the plan bearing number PBCB/Revenue plan/2018-19/01A, dated the 15th November, 2018, containing details of the area of land described in the said Schedule may be inspected at the office of the Bharat Coking Coal Limited (Estate Department), Koyla Bhawan, Koyla Nagar, Dhanbad-826005 or at the office of the General Manager, Vikramshila Area/TS to D(T) P&P, Bharat Coking Coal Limited, Koyla Bhawan, Koyla Nagar, Dhanbad - 826005 or

Deputy Commissioner, District Godda (Jharkhand) and District Collector, District Bhagalpur (Bihar) or at the office of the General Manager (Exploration Division), Regional Institute(II), Central Mine Planning and Design Institute, Koyla Bhawan Complex, Koyla Nagar, Dhanbad - 826005 or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata-700001;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal from lands described in the said Schedule.

Any person interested in the land described in the above mentioned Schedule may –

- (i) object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over the said land; or
- (ii) claim compensation under section 6 of the said Act for any damage caused or likely to be caused by any action taken under sub-section (3) of section 4 thereof; or
- (iii) claim compensation under sub-section (1) of section 13 of the said Act in respect of prospecting license ceasing to have effect or under sub-section (4) of section 13 of the said Act, for mining lease ceasing to have effect and deliver all maps, charts and other documents relating to the aforesaid land to show the expenditure incurred in respect of items specified in clauses (i) to (iv) of sub-section (1) of section 13 thereof,

to the office of the General Manager, Vikramshila Area/TS to D(T)P&P, Bharat Coking Coal Limited, Koyla Bhawan, Koyla Nagar, Dhanbad-826005 (Jharkhand) or General Manager (Estate), Bharat Coking Coal Limited, Koyla Bhawan, Koyla Nagar, Dhanbad-826005 (Jharkhand) within a period of ninety days from the date of publication of this notification.

SCHEDULE

PIRPAINTI-BARAHAT COAL MINING BLOCK

DISTRICT GODDA (JHARKHAND) AND DISTRICT BHAGALPUR (BIHAR)

(Plan bearing number PBCB/Revenue Plan/2018-19/01A, dated the 15th November, 2018)

1. DISTRICT-GODDA, JHARKHAND:

Sl. No.	Mouza/Village	Thana number	Village/ Thana number	Name of District	Area (in hectares approximately)	Area (in acres approximately)	Remarks
1	Shiwanpur/ Shimanpur	Mahagama	9	Godda	91.104	225.118	PART
2	Khiroundhi	Mahagama	10	Godda	99.117	244.918	PART
3	Khatti	Mahagama	11	Godda	79.61	196.706	FULL
4	Parsa	Mahagama	12	Godda	185.18	457.567	FULL
5	Amour	Mahagama	13	Godda	242.03	598.054	FULL
6	Nadiwan	Mahagama	14	Godda	26.73	66.050	FULL
7	Khiroundha	Mahagama	15	Godda	108.73	268.659	PART
8	Sumi	Mahagama	16	Godda	10.00	24.710	PART
9	Doi	Mahagama	321	Godda	167.27	413.327	PART
10	Dariachak	Mahagama	330	Godda	23.75	58.680	PART
11	Ghorichak	Mahagama	331	Godda	23.93	59.124	FULL
12	Gousi Pratappur	Mahagama	336	Godda	26.00	64.246	PART
13	Kumardiha	Mahagama	338	Godda	99.000	244.629	FULL
14	Udwachak	Mahagama	339	Godda	19.00	46.949	FULL
15	Chaura	Mahagama	340	Godda	120.953	298.875	FULL
16	Fuduliakita	Mahagama	341	Godda	4.610	11.391	FULL
17	Lakarmara	Mahagama	342	Godda	266.604	658.778	FULL
18	Majagain	Mahagama	343	Godda	25.00	61.775	FULL
19	Nima	Mahagama	344	Godda	51.00	126.021	FULL
20	Udaypur Behra	Mahagama	345	Godda	59.00	145.789	FULL
21	Chitarsen Behra	Mahagama	346	Godda	29.000	71.659	FULL

22	Masudanpur Ghorikita	Mahagama	347	Godha	79.50	196.445	PART
23	Jitachak	Mahagama	348	Godha	8.000	19.768	FULL
24	Dariapur	Mahagama	349	Godha	86.985	214.940	FULL
25	Dhankuria	Mahagama	354	Godha	143.648	354.955	PART
26	Singarpur	Mahagama	371	Godha	73.581	181.819	PART
			Toral Area:		2149.312	5310.952	

2. DISTRICT-BHAGALPUR, BIHAR

Sl. No.	Mouza/Village	Thana number	Village/Thana number	Name of District	Area (in hectares approximately)	Area (in acres approximately)	Remarks
1	Kairia	Kolgang	312	Bhagalpur	140.594	347.408	PART
2	Mahagawa	Kolgang	313	Bhagalpur	145.733	360.106	FULL
3	Bishunpur Mahagawa Milik	Kolgang	314	Bhagalpur	17.00	42.007	FULL
4	Karhara Basantpur Milik	Kolgang	315	Bhagalpur	1.00	2.471	FULL
5	Basdeopur Bhalua Arazi	Kolgang	316	Bhagalpur	18.00	44.478	FULL
6	Karhara Basdepour Milik	Kolgang	317	Bhagalpur	12.00	29.652	FULL
7	Bhalua	Kolgang	318	Bhagalpur	70.00	172.97	PART
8	Bhalua Suzan	Kolgang	319	Bhagalpur	51.00	126.021	PART
9	Mahagawa Milik	Kolgang	332	Bhagalpur	13.00	32.123	PART
10	Semaria	Kolgang	333	Bhagalpur	140.00	345.94	PART
11	Kairia Milik	Kolgang	334	Bhagalpur	16.00	39.536	FULL
			Total Area:		624.327	1542.712	

Grand Total: (2149.312 hectares + 624.327 hectares)= 2773.639 hectares (approximately) or (5310.952 acres + 1542.712 acres) = 6853.664 acres (approximately)

Boundary Description:

- 1-2 Line starts from point no.-‘1’ in Mouza - Kairia towards South-East direction up to point no.- 2 in Mouza Kairia.
- 2-3 Line starts from point no.-‘2’ in Mouza Kairia towards North -East direction up to point no.-3 in Mouza Kairia.
- 3-4 Line starts from point no.-‘3’ in Mouza Kairia towards North -East direction up to point no.-4 at Dhulia Nala in Mouza Kairia.
- 4-24 Line starts from point no.-‘4’ at Dhulia Nala in Mouza Kairia and passing towards South-East direction along Dhulia Nala through Mouza-Kairia, Khiraundhi, Shiwanpur, Khiraundha, Amour, Nadiawa and Doi up to point no.-24 at National Highway – 133 in Mouza Doi.
- 24-28 Line starts from point no.-‘24’ in Mouza Doi and passes along National Highway - 133 towards Southward direction through Mouza- Doi, Kumardiha, Gousi Pratapur, Ghorichak and Dariachak up to point no.-28 in Mouza – Dariachak.
- 28-29 Line starts from point no.-‘28’ passing towards South West direction through Mouza-Dariachak, Singarpur, Dhankuria up to the point no. - 29 in Mouza – Dhankuria.
- 29-30 Line starts from point no.-‘29’ in Mouza –Dhankuria and passing towards North-West direction through Mauza- Dhankuria, Dariyapur, Masudanpur Ghorikita and Bhaluasujan up to point no.-30 in Mouza- Bhalua Sujan.

8. 30-31 Line starts from point no.-‘30’ in Mouza- Bhalua Sujan passing towards North-West direction through Mouza Bhalua Sujan & Bhalua upto point no. - 31 in Mouza-Bhalua.
9. 31-35 Line starts from point no.-‘31’ in Mouza-Bhalua and passes towards North-West direction through Mouza - Bhalua and Basdeopur Bhalua Arazi up to point no.-35 in Mouza Basdeopur Bhalua Arazi.
10. 35-39 Line starts from point no.-‘35’ in Mouza Basdeopur Bhalua Arazi and passes towards North-West direction through Mouza Basdeopur Bhalua Arazi ,Mahagama Milik and Semaria up to point no.- 39 in Mouza Semaria.
11. 39-40 Line starts from point no.-‘39’ in Mouza Semaria passing towards North direction through Mouza- Semaria up to point no.-‘40’ in Mouza Semaria.
12. 40-1 Line starts from point no.-‘40’ in Mouza Semaria and passes towards North-East direction through Mouza Semaria and Kairia and meets the point no.-1 in Mouza Kairia (Starting point of boundary).

[F. No. 43015/17/2018-LA&IR]

By Order,

R. S. SAROJ,

Under Secretary to the Government of India.

By order of the Governor,

Sushil Kumar, Under Secretary.

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचनाएं

7 मार्च 2019

सं० 1/एल1-10-13/2014-गृ०आ० 2235—श्री प्रणव कुमार प्रवीण, भा०पु०से० (2007), पुलिस अधीक्षक (बी), विशेष शाखा, बिहार, पटना को स्वयं की चिकित्सा हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम-12 एवं 13 के अन्तर्गत दिनांक 23.11.2018 से 05.01.2019 तक कुल 46 (छियालीस) दिनों के रूपान्तरित अवकाश (46 x 2 = 92 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के समतुल्य) की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव।

सं० 8/पी.3-10-08/2018 गृ०आ०-2461

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 14 मार्च 2019

विषय :- आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना में अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी (से०ग्रे०) एवं अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी के दो-दो पद सहित कुल 04 (चार) पद क्रमशः लेवल-12 एवं लेवल-11 में सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना की स्थापना सन् 2011 में की गई है। स्थापना से लेकर अभी तक यहाँ अभियोजन पदाधिकारी का पद सृजित नहीं हुआ है, जिससे कांडों के अनुसंधान एवं न्यायिक कार्यों में विधिक कानूनी मंतव्य प्राप्त करने में काफी कठिनाई हो रही है तथा कांड के अभियोजन प्रभावित हो रहा है।

2. आर्थिक अपराध इकाई का कार्य क्षेत्र पूरा बिहार है तथा यहाँ महत्वपूर्ण अधिनियमों जैसे— भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, उत्पाद अधिनियम, मादक द्रव्यों से संबंधित अधिनियम सहित कुल चालीस अधिनियमों से संबंधित वादों का अनुसंधान होता है। भारतीय दंड संहिता से संबंधित महत्वपूर्ण कांडों का भी यहाँ अनुसंधान होता है।

3. अपराधों के अनुसंधान एवं अभियोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कतिपय दिशा-निर्देश Criminal Appeal No- 169/2014 पेरूमल बनाम जानकी एवं Criminal Appeal No-1485/2008 गुजरात राज्य बनाम किशन भाई में जारी किये गये हैं, जिनके सम्यक् समीक्षोपरान्त राज्य सरकार द्वारा भी तदनु रूप अनुदेश दिये गये हैं।

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा यह भी अनुदेश दिया गया है कि किसी भी अपराधिक मामले में अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात संबंधित अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के क्रम में एकत्र किये गये साक्ष्यों एवं दस्तावेजों की छायाप्रति उक्त न्यायालय से संबद्ध अभियोजन को उपलब्ध करायेंगे, जिस न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया जाना हो, उसकी स्वतंत्र रूप से विवेचना अभियोजक द्वारा की जायेगी। अनुसंधान में किसी प्रकार की त्रुटि या कमी परिलक्षित होने पर तत्काल अभियोजक द्वारा संबंधित वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को प्रतिवेदित किया जायेगा, जिसके आलोक में संबंधित वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक मामले के निहित प्रावधानों के अनुरूप अनुसंधानकर्ता को अग्रतर अनुसंधान करने का निर्देश जारी करेंगे।

5. उक्त परिस्थितियों में कांडों के अनुसंधान तथा न्यायिक कार्यों में कानूनी मंतव्य प्राप्त करने हेतु आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना के लिये स्वतंत्र रूप से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी (से0ग्रे0) एवं अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी के दो-दो पदों के स्थायी रूप से सृजित करने के संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के पत्रांक-5005/स्था0, दिनांक 29.08.2018 द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

(i) अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी (से0ग्रे0) एवं अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, आर्थिक अपराध इकाई में अनुसंधान अंतर्गत कांडों एवं माननीय न्यायालय में चल रहे विचारित मामलों में विधिक मंतव्य देंगे, जिससे अनुसंधान एवं विचारण कार्यों में सुगमता होगी।

(ii) अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी (से0ग्रे0) एवं अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी स्तर के पदाधिकारी बिहार अभियोजन सेवा संवर्ग के पदाधिकारी होते हैं उन्हें इस इकाई में पदस्थापित किया जा सकता है।

6. अतः आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना में अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी (से0ग्रे0) एवं अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी के दो-दो पद सहित कुल 04 (चार) पद क्रमशः लेवल-12 एवं लेवल-11 में सृजन किया जाता है।

7. आर्थिक अपराध इकाई बिहार, पटना में अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी (से0ग्रे0) एवं अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी के दो-दो पदों के सृजन हेतु सातवें वेतनमान में अन्य भत्तों सहित अनुमानित वार्षिक व्यय रु0 46,50,072/- (छियालीस लाख पचास हजार बहत्तर रु0 मात्र) है।

(i) उक्त राशि की निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना होंगे और उक्त राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

(ii) उक्त राशि बजट शीर्ष-2055 पुलिस लघु शीर्ष-101 अपराधिक अन्वेषण एवं सतर्कता उप शीर्ष-0001 अपराधिक जाँच मांग सं0-22 विपत्र कोड - 22-20550010100001 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

7. उपर्युक्त में वित्त विभाग एवं मंत्रिपरिषद् की सहमति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

परिशिष्ट-II

व्यय विवरणी

आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना में अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी (से0ग्रे0) एवं अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी के दो-दो पद सृजित पर होने वाला वार्षिक व्यय विवरणी:-

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की कुल सं0	लेवल	मूल वेतन	सं0 भत्ता (9%)	चिकित्सा भत्ता	मकान किराया भत्ता	परिवहन भत्ता	कुल मासिक वेतन	कुल वार्षिक अनुमानित व्यय (12 माह)
1	अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी (से0ग्रे0)	02	12	78,800	7,092	1,000	12,608	4,280	1,03,780x2= 2,07,560	24,90,720
2	अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी	02	11	67,700	6,161	1,000	10,832	4,280	89,973x2= 1,79,946	21,59,352
कुल वार्षिक व्यय :- (छियालीस लाख पचास हजार बहत्तर रु0 मात्र)										46,50,072

गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

सं० 8/पी.3-10-09/2018 गृ०आ०-2526

**गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)**

प्रेषक,

गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 15 मार्च 2019

विषय :-

पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के कार्यालय हेतु आशु उपाधीक्षक के 05 पद एवं आशु निरीक्षक के 35 पद सहित कुल 40 (चालीस) पदों का सृजन क्रमशः लेवल-9 एवं लेवल-7 में स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक पूर्व में बिहार पुलिस हस्तक के परिशिष्ट-42 एवं नियम-749 के सुसंगत प्रावधानों के अधीन आशु संवर्ग में आशु स०अ०नि० एवं आशु अ०नि० की कोटि में भर्ती किया जाता था। इस संवर्ग में कितने पद प्रोन्नति से भरे जायेंगे एवं कितने पदों पर सीधी नियुक्ति की जायेगी, इससे संबंधित निर्णय पुलिस महानिदेशक, बिहार द्वारा लिया जाता था। इस संवर्ग के पदाधिकारियों को इस कोटि के मूल पद पर उनकी नियुक्ति के सामान्यतया पाँच वर्षों के पश्चात् विनिर्धारित शर्तों के अनुरूप सामान्य संवर्ग में प्रत्यावर्तित करने का प्रावधान था। बिहार पुलिस में मात्र आशु सहायक अवर निरीक्षक एवं आशु अवर निरीक्षक के पद सृजित थे। आशु सहायक अवर निरीक्षक में नियुक्त कर्मी पुलिस हस्तक में विनिर्धारित प्रावधानों के अनुरूप सामान्य संवर्ग के सहायक अवर निरीक्षक में प्रत्यावर्तित होकर उच्चतर पदों में प्रोन्नति पाते थे। इसमें प्रत्यावर्तन की इच्छा व्यक्त नहीं करने वाले कर्मी आशु संवर्ग में मात्र अवर निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति पाकर ही सेवानिवृत्त हो जाते थे। इस संवर्ग में प्रोन्नति के उच्चतर पदों में अवसर नहीं रहने के कारण इन कर्मियों की प्रोन्नति बाधित रहती थी। इस प्रकार आशु संवर्ग के पदाधिकारियों को सामान्य बल में उनका प्रत्यावर्तन, स्वेच्छा मांगने, उनकी सामान्य बल में वरीयता के निर्धारण, पी०टी०सी० ट्रेनिंग आदि के कारण पुलिस मुख्यालय को विभिन्न प्रकार की पेचीदगियों एवं वादों का सामना करना पड़ता था।

2. ऐसी स्थिति में गृह विभाग द्वारा बिहार पुलिस हस्तक के नियम-1287 (क) को विलोपित कर नियम-749 एवं परिशिष्ट-42 में निहित प्रावधान एवं तत्संबंधी पूर्व से निर्गत आदेश/परिपत्र/निदेश निरसित करते हुए अधिसूचना संख्या-6838 दिनांक- 23.08.2017 द्वारा बिहार पुलिस आशु संवर्ग नियमावली, 2017 प्रवृत्त की गई। इसमें विनिर्धारित मापदण्डों के अनुरूप आशु सहायक अवर निरीक्षक के पदों पर सीधी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इन पदों पर प्रोन्नति, वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर श्रृंखला निम्नानुसार तय की गई है:-

(क) आशु सहायक अवर निरीक्षक से आशु अवर निरीक्षक

(ख) आशु अवर निरीक्षक से आशु निरीक्षक

(ग) आशु निरीक्षक से आशु उपाधीक्षक

3. बिहार में वर्तमान में आशु सहायक अवर निरीक्षक एवं आशु अवर निरीक्षक के पद सृजित हैं। बिहार आशु लिपिक सेवा नियमावली 2017 प्रभावी होने के उपरान्त मात्र विशेष शाखा में आशु निरीक्षक के 04 पद एवं आशु उपाधीक्षक के 01 पद स्वीकृत हैं। उक्त संवर्ग में प्रभावकारी ढंग से कार्य करने एवं प्रोन्नति का अवसर प्रदान करने हेतु आशु निरीक्षक एवं आशु उपाधीक्षक के अन्य पदों का सृजन आवश्यक प्रतीत होता है, ताकि इस संवर्ग में विनिर्धारित उच्चतर पदों पर प्रोन्नति के अवसर प्राप्त हो सकें।

4. इस संवर्ग में आवश्यकता का आकलन करते हुए आवश्यकता आधारित आशु उपाधीक्षक के 05 पद एवं आशु निरीक्षक के 35 पदों के सृजन का प्रस्ताव पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) के पत्रांक-364/375005/एल-2, दिनांक 15.06.2018 के द्वारा प्राप्त है।

5. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के कार्यालय हेतु आशु उपाधीक्षक के 05 पद एवं आशु निरीक्षक के 35 पदों का कुल 40 (चालीस) सहित क्रमशः लेवल-9 एवं लेवल-7 में सृजन किया जाता है।

(i) उक्त पदों के पद सृजन पर होने वाली अनुमानित वार्षिक व्यय राशि 4,14,24,452/-रु० होगा।

6. विभिन्न कार्यालयों में उक्त पदों पर अनुमानित राशि के व्यय हेतु मांग संख्या, मुख्य शीर्ष, उप शीर्ष, लघुशीर्ष, विपत्र कोड, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा निकासी संबंधित कोषागार संलग्न विवरणी के अनुरूप होगा।

7. उपर्युक्त में वित्त विभाग एवं मंत्रिपरिषद् की सहमति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

परिशिष्ट-II

पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के कार्यालय हेतु आशु उपाधीक्षक के कुल 05 पद एवं आशु निरीक्षक के कुल 35 पदों के सृजन पर अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी।

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान (स्तर सारणी)	पदों की संख्या	मासिक वेतन (रुपये में दसवें प्रक्रम)	महंगाई भत्ता (9%)	मकान किराया	परिवहन भत्ता
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आशु उपाधीक्षक	Level-9	5	69200x5 =346000	69200x 5x9/100 =31140	55360	16350
2	आशु निरीक्षक	Level-7	35	59600x35 =2086000	59600x 35x9/ 100 =187740	271776	86110
क्र० सं०	चिकित्सा भत्ता	राशन मनी भत्ता	व्यय प्रति माह	वार्षिक व्यय (रुपये में)	अतिरिक्त तेहरवें माह का वेतन महंगाई भत्ता के साथ	वर्दी भत्ता प्रति वर्ष (रु० में)	वार्षिक परिलब्धि (रु० में)
1	9	10	11	12	13	14	(12+13+14)
1	1000x5= 5000	0	453850	5446200	0	12000x5 =60000	5506200
2	1000x35= 35000	3000x3= 105000	2771626	33259512	2272740	11000x35 =385000	35918252
कुल योग- 41424 (हजार के गुणांक में) चार करोड़ चौदह लाख चौबीस हजार रुपये मात्र।						41424452	

मकान किराय भत्ता						परिवहन भत्ता				
क्र० सं०	पदनाम	वर्गीकृत शहर	पदों की संख्या	मकान किराया भत्ता	अनुमानित व्यय प्रति माह (रु० में)	पदनाम	वर्गीकृत शहर	पदों की संख्या	परिवहन भत्ता	अनुमानित व्यय प्रति माह (रु० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	11
1	आशु उपाधीक्षक	Y (16%)	5	11072	55360	आशु उपाधीक्षक	पटना यू०ए०	5	3270	16350
2	आशु निरीक्षक	Y (16%)	22	9536	209792	आशु निरीक्षक	पटना यू०ए०	22	3270	71940
		Z (8%)	13	4768	61984		अन्य नगर निगम	13	1090	14170
	योग:—		40		327136		योग	40		102460

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

**गृह विभाग
(विशेष शाखा)**

**अधिसूचना
13 मार्च 2019**

सं० एल/एच०जी०-14-06/2018-2909—बिहार गृह रक्षा वाहिनी में जिला समादेष्टा के रूप में पदस्थापित निम्नांकित पदाधिकारी की सेवा बिहार पुलिस मैनुअल के नियम 648(क) के आलोक में जिला समादेष्टा (पुलिस उपाधीक्षक स्तर) कोटि में उनके नाम के सामने अंकित तिथि से सम्पुष्ट की जाती है:-

क्रम सं०	नाम/पदनाम	सम्पुष्टि की तिथि
1	श्रीमती रश्मि, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, रोहतास	29.09.2018

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विमलेश कुमार झा, अपर सचिव।

**गृह विभाग
(विशेष शाखा)**

**आदेश
11 मार्च 2019**

सं० एल/एच०जी०-14-21/2018-2806/सी०—श्री कृष्ण कुमार पण्डा, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, रोहतास के दिनांक 31.07.2018 के अपराहन में सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1829 वि० (2), दिनांक 07.04.2005 के आलोक में वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-712(23), दिनांक 21.08.2018 द्वारा संसूचित अवकाश आदेयता के आधार पर 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस आदेश में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
विमलेश कुमार झा, अपर सचिव।

15 मार्च 2019

सं० एल/एच०जी०-14-04/2019- 2992/सी०—श्री विश्वमोहन लाल, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, जहानाबाद के दिनांक 31.05.2018 के अपराहन में सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1829 वि० (2), दिनांक 07.04.2005 के आलोक में वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-1188(23), दिनांक 23.11.2018 द्वारा संसूचित अवकाश आदेयता के आधार पर 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस आदेश में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
विमलेश कुमार झा, अपर सचिव।

11 मार्च 2019

सं० एल/एच०जी०-14-05/2019-2807/सी०—श्री जीवेन्द्र नाथ झा, प्रमंडलीय समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के दिनांक 28.02.2019 के अपराहन में सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1829 वि० (2), दिनांक 07.04.2005 के आलोक में वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-12(23), दिनांक 04.01.2019 द्वारा संसूचित अवकाश आदेयता के आधार पर 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस आदेश में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
विमलेश कुमार झा, अपर सचिव।

शिक्षा विभाग

अधिसूचनाएं
9 मार्च 2019

सं० 15/ए 2-02/2016 (अंश 3) 622—बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 21, 2017) की धारा 09 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 227 दिनांक 25.01.2019 द्वारा प्रख्यापित बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2019 की धारा 03 में प्रदत्त शक्तियों के तहत बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग में निम्नांकित सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है।

1. श्री राजीव प्रसाद सिंह रंजन,
पूर्व निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार सरकार (सेवानिवृत्त)
2. डॉ० उपेन्द्र नाथ वर्मा,
प्रोफेसर, रसायनशास्त्र विभाग,
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
3. डॉ० विजय कान्त दास,
प्रोफेसर एण्ड हेड, पी०जी० डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश,
तिलका माँझी विश्वविद्यालय, भागलपुर
4. डॉ० अशोक कुमार,
पूर्व संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार (सेवानिवृत्त)
302, सूर्य शारदा विला, नियर डॉक्टर भगत सिंह क्लिनिक
न्यू पुनाईचक, थाना—शास्त्रीनगर, पटना—800023
5. श्री उमेश चन्द्र विश्वास,
पूर्व विशेष सचिव,
निगरानी विभाग, बिहार सरकार (सेवानिवृत्त)
6. डॉ० उषा प्रसाद, प्रोफेसर—सह—विभागाध्यक्ष, इतिहास,
कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एण्ड साइंस, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, पटना

2. सभी सदस्य अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से तीन वर्षों के कार्यकाल अथवा 70 वर्ष की आयु पूरी होने (इनमें से जो भी पहले हो) तक के लिए सदस्य के पद पर कार्यरत रहेंगे।

3. सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2019 के प्रावधानों के अनुसार अनुमान्य होंगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा, विशेष सचिव।

9 मार्च 2019

सं० 15/एम 1-06/2015/621—विभागीय अधिसूचना संख्या 611 दिनांक 08.03.2019 द्वारा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के परिनियम की धारा-12 (a) के आलोक में राज्य सरकार द्वारा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के सभा (Court) गठन किया गया है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा तीन सदस्यों को मनोनीत किया गया है।

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के परिनियम की धारा-12 (a) के प्रावधानानुसार राज्य सरकार के चौथे सदस्य के रूप में डा० रत्नेश्वर मिश्र, पूर्व विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग, एल०एन० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को इस विश्वविद्यालय के सभा (Court) में मनोनीत किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, विशेष सचिव।

9 मार्च 2019

सं० 15/ए 6-02/2008(अंश)/618—श्री दिनेश चन्द्र झा, प्रभारी अध्यक्ष—सह—निदेशक, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना एवं कार्यकारी अध्यक्ष—सह—निदेशक, मैथिली अकादमी, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त संस्कृत अकादमी, पटना का कार्यकारी अध्यक्ष—सह—निदेशक के रूप में अगले आदेश तक प्राधिकृत किया जाता है।

उक्त पद पर नियमित नियुक्ति अथवा अन्य कोई आदेश निर्गत होने के पश्चात् यह कार्यकारी व्यवस्था स्वतः समाप्त की जायेगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अरशद फिरोज, उप—सचिव।

28 फरवरी 2019

सं0 15/ए 2-02/2016 (अंश 3)/557—बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 21, 2017) की धारा 09 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 227 दिनांक 25.01.2019 द्वारा प्रख्यापित बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2019 की धारा 03 में प्रदत्त शक्तियों के तहत डॉ० राजवर्धन आज़ाद, Ex-Chief & Professor of ophthalmology, Dr. Rajendra Prasad Centre for ophthalmic Sciences, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi को बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है।

2. डॉ० आज़ाद अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से तीन वर्षों के कार्यकाल अथवा 72 वर्ष की आयु पूरी होने (इनमें से जो भी पहले हो) तक के लिए अध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहेंगे।

3. अध्यक्ष को वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2019 के प्रावधानों के अनुसार अनुमान्य होंगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अरशद फिरोज, उप—सचिव।

28 फरवरी 2019

सं0 15/ए 2-02/2016 (अंश 3)/558—बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 21, 2017) की धारा-1(3) के तहत इस अधिनियम को प्रवृत्त करने की शक्ति अधिसूचना द्वारा तिथि नियत कर राज्य सरकार को प्रदत्त की गई है। अधिनियम में प्रदत्त उक्त शक्ति के आलोक में बिहार अधिनियम 21, 2017 को इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त करने का निर्णय लिया गया है।

2. इस अधिनियम को प्रवृत्त होने की तिथि से बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को स्वतः अस्तित्व में माना जाएगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अरशद फिरोज, उप—सचिव।

8 मार्च 2019

सं0 15/एम 1-06/2015/611—आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के परिनियम की धारा-12 (a) के आलोक में समीक्षोपरान्त राज्य सरकार द्वारा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के सभा (Court) गठन निम्नवत् किया जाता है:-

1.	माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार	अध्यक्ष
2.	कुलपति, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना	उपाध्यक्ष
3.	श्री केदार पाण्डेय, सदस्य बिहार विधान परिषद	सदस्य
4.	श्री नीरज कुमार, सदस्य बिहार विधान परिषद	सदस्य
5.	श्री अंजनी कुमार सिंह, पूर्व मुख्य सचिव, बिहार	सदस्य
6.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार	पदेन सदस्य
7.	डीन, छात्र कल्याण, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना	पदेन सदस्य
8.	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार	पदेन सदस्य
9.	प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग, बिहार	पदेन सदस्य
10.	निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग, बिहार	पदेन सदस्य
11.	प्रॉक्टर, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना	पदेन सदस्य

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के परिनियम के प्रावधानानुसार इस सभा (Court) अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से तीन वर्षों के लिए होगी।

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के परिनियम की धारा-12 (a) (9), (10), (13), (14) एवं (15) में वर्णित व्यक्तियों को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को मनोनीत करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। विश्वविद्यालय द्वारा मनोनीत होने के पश्चात वे इस अधिसूचना के तहत सभा (Court) में मनोनीत समझे जाएंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, उप—सचिव।

9 मार्च 2019

सं० 15/ए 6-02/2008 (अंश)/617—श्री विनय कुमार, उप निदेशक, उच्च शिक्षा, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त दक्षिण भारतीय भाषा संस्थान, पटना का कार्यकारी अध्यक्ष—सह—निदेशक के रूप में अगले आदेश तक प्राधिकृत किया जाता है।

उक्त पद पर नियमित नियुक्ति अथवा अन्य कोई आदेश निर्गत होने के पश्चात् यह कार्यकारी व्यवस्था स्वतः समाप्त की जायेगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अरशद फिरोज, उप—सचिव।

The 1st March 2019

No. 15/M 1-112/2014/564---Under the provisions of section 32 of Bihar Private Universities Act 2013 the State Government has been pleased to approve the following first Ordinance for Gopal Narayan Singh University established vide State Government notification no.1066 dated 15.06.2018.

CHAPTER I: ADMISSION

Under the power conferred by Section 17 and Section 22 of the clause 1.2 of the First Statutes of the Gopal Narayan Singh University, the University hereby institutes the following Ordinances governing to admission to Institutes/ Faculties/ College of the University:

I. Institutes and Faculties

1.	Institutes:
i	Institutes of Agricultural Sciences
ii	Narayan Medical College and Hospital
iii	Narayan Academy of Managerial Excellency
iv	Narayan Institute of Pharmacy
v	Narayan Institute of Design
vi	Narayan Nursing College
vii	Narayan Paramedical Institute and Allied Sciences
2.	Faculty
i	Faculty of Agriculture
ii	Faculty of Arts
iii	Faculty of Ayurveda
iv	Faculty of Education
v	Faculty of Commerce
vi	Faculty of Dental Sciences
vii	Faculty Design
viii	Faculty of Law
ix	Faculty of Medicine
x	Faculty of Management Studies
xi	Faculty of Nursing
xii	Faculty of Performing Arts
xiii	Faculty of Pharmacy
xiv	Faculty of Physical Education
xv	Faculty of Science
xvi	Faculty of Social Sciences
xvii	Faculty of Visual Arts
xvii	Faculty of Information Technology

i	
---	--

II. Courses and Duration

1.	Post-Doctoral Degree	Duration
	Doctor of Science (D.Sc)	
	Doctor of Literature (D.Litt.)	
	Doctor of Law (LL.D.)	
2.	Doctorate Degree	
	Doctor of Philosophy (Ph.D)	3 years
3.	Master of Philosophy (M.Phil)	1 year

1. Faculty of Agriculture

	Course Name	Duration
A.	Bachelor of Science in Agricultural Science [B.Sc.{Ag}]	4 years
B.	Master of Science (Agriculture) M.Sc. (Ag) in	2 years
1.	Agricultural Economics	
2.	Agronomy	
3.	Animal Husbandry & Dairying	
4.	Entomology & Agricultural Zoology	
5.	Extension Education	
6.	Genetics & Plant Breeding	
7.	Horticulture	
8.	Mycology & Plant Pathology	
9.	Plant Physiology	
10.	Soil Science & Agricultural Chemistry	

2. Faculty of Arts

Sl.No.	Course Name	Duration
1.	Bachelor of Arts (B.A.)(Hons.)	3 years
2.	Master of Arts (M.A.)	2 years
3.	Five year Integrated Course in Journalism	5 years
4.	Master of Journalism & Mass Communication	2 years
5.	Bachelor of Journalism & Mass Communication	3 years
6.	Bachelor of Library Sciences	3 years
7.	Master of Library Sciences	2 years

3. Faculty of Ayurveda

S.No	Course Name	Duration
A.	Bachelor of Ayurveda Medicine & Surgery [B.A.M.S.]	5½ years
B.	Doctor of Medicine (Ayurveda)/Master of Surgery (Ayurveda) MD(Ay)/MS(Ay) in:	3 years
1	Dravyaguna	
2	Kaya-Chikitsa	
3	Kaumarbhritya	
4	KriyaSharir	
5	PrasutiTantra	
6	RachnaSharir	
7	Rasa Shastra	
8	Sangyahan	

9	Shalakyatantra	
10	Shalyatantra	
11	SidhantDarshan	
12	VikritiVijnan	

4. Faculty of Education

Sl.No.	Course Name	Duration
1.	Bachelor of Education (B.Ed)	2 years
2.	Master of Education (M.Ed)	2 years

5. Faculty of Commerce

Sl.No.	Course Name	Duration
1.	Bachelor of Commerce	3 years
2.	Master of Commerce	2 years

6. Faculty of Dental Sciences

1.	Bachelor of Dental Surgery (BDS)	4 years
2.	Master of Dental Surgery (MDS)	3 years

7. Faculty of Design

1.	Bachelor of Design (B.Des)	4 years
2.	Master of Design (M.Des)	2½ years

8. Faculty of Law

Sl.No.	Course Name	Duration
1.	BBA.LL.B (Hons) (Integrated Course)	5 years
2.	B.A.LL.B (Hons) (Integrated Course)	5 years
3.	LL.B.(Hons.)	3 years
4.	Master of Law (LL.M.)	2 years

9. Faculty of Medicine

Sl.No.	Course Name	Duration
A	Doctoratus Medicinus (D.M.) in	2 years
1	Cardiology	
2	Endocrinology & Metabolism	
3	Gastro-Enterology	
4	Neurology	
B.	Master of Chirurgiae (M.Ch.) in	2 years
1	Neuro-Surgery	
2	Paediatric Surgery	
3	Plastic Surgery	
4	Urology	
C.	Doctor of Medicine (M.D.) in	3 years
1.	Anaesthesiology	
2.	Biochemistry	
3.	Community Medicine	
4.	Dermatology, Venereology & Leprosy	
5.	Forensic Medicine	
6.	Medicine	

7.	Microbiology	
8.	Paediatrics	
9.	Pathology	
10.	Pharmacology	
11.	Physiology	
12.	Physical Medicine & Rehabilitation (PMR)	
13.	Psychiatry	
14.	Radio Diagnosis	
15.	Radiotherapy & Radiation	
16.	Tuberculosis & Respiratory Diseases	
D.	Master of Surgery	3 years
1	Anatomy	
2	Obstetrics & Gynaecology	
4	Ophthalmology	
5	Orthopaedics	
6	Otorhinolaryngology	
7	Surgery	
E.	Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery [M.B.B.S]	5½ years
F.	B.Sc in Cardiac Care Technology	3 years
G.	B.Sc in Critical care Technology	3 years
H	B.Sc in Forensic Science	3 years
I	B.Sc in Operation Theater & Anesthesia	3 years
J	B.Sc in Optometry	3 years
K	B.Sc in Medical Laboratory Technology	3 years
L	B.Sc in Medical Radiography & Radio-Imagine Technology	3 years
M	B.SC in Respiratory care Technology	3 years
N	B.Sc in Renal Dialysis Technology	3 years
O	B.Sc in Emergency Medicine Technology	3 years
P	Bachelor of Physiotherapy	4½ years
Q	Master of Physiotherapy	2 years

10. Faculty of Management Studies

Sl.No.	Course Name	Duration
1.	Bachelor of Management Studies (BMS)	3 years
2.	Master of Business Administration (MBA)	2 years

11. Faculty of Nursing

Sl.No.	Course Name	Duration
1.	Bachelor of Science in Nursing [B.Sc {Nursing}]	4 years
2.	Master of Science in Nursing [M.Sc {Nursing}]	2 years
3.	General Nurse Midwifery [GNM]	3 years

12. Faculty of Performing Arts

Sl.No	Course Name	Duration
1.	Bachelor of Music (B.Mus)/BPA	3 years
2.	Master of Music (M.Mus)/MPA	2 years

13. Faculty of Pharmacy

Sl.No	Course Name	Duration
1.	Bachelor of Pharmacy (B. Pharm)	4 years
2.	Master of Pharmacy (M. Pharm)	2 years
3.	Diploma in Pharmacy (D. Pharm)	2 years

14. Faculty of Physical Education

Sl.No	Course Name	Duration
1.	Bachelor of Physical Education	3 years
2.	Master of Physical education	2 years

15. Faculty of Social Sciences

Sl.No	Course Name	Duration
1.	Bachelor of Arts (B.A.)(Hons)	3 years
2.	Master of Arts (M.A.)	2 years

16. Faculty of Science

Sl.No.	Course Name	Duration
1.	Bachelor of Science {B.Sc(Hons.)}	3 years
2.	Master of Science (M.Sc) in	2 years
	Botany	
	Chemistry	
	Geography	
	Mathematics	
	Physics	
	Psychology	
	Statistics	
	Zoology	

17. Faculty of Visual Arts

Sl.No.	Course Name	Duration
1.	B.F.A	3 years
2.	M.F.A.	2 years

18. Faculty of Information Technology

Sl.No.	Course Name	Duration
1.	Bachelor of Computer Application (BCA)	3 years
2.	Master of Computer Application (MCA)	2 years
3.	B.SC. – I.T.	3 years
4.	M.Sc. – I.T.	2 years

CERTIFICATE AND DIPLOMA COURSES

Sl.No.	Course Name	Duration
1.	Diploma in Physiotherapy (DPT)	3.5 Years
2.	O.T. Assistant (DOTA)	2 Years
3.	Med. Lab Tech. (DMLT)	2 Years
4.	Med. Radiography (DMR)	2 Years
5.	Ophthalmic Assistant (DOA)	2 Years
6.	Orthotic & Prosthetic (DOP)	2 Years
7.	E.C.G (DECG)	2 Years
8.	Certificate in Dresser (CMD)	1 Year

CHAPTER II: General Ordinances

1	A notification related to admission to available courses through University Entrance Test shall be issued by the University every year.
2.	An Information Bulletin containing therein all information regarding name of the course, duration, eligibility for admission, fee structure and intake shall be published by the University.
3.	Total intake for admission to Institute/Faculty/College at entry level to any session and their eligibility condition for admission to the respective courses shall be prescribed by the Academic Council of the University.
4.	All admission shall be made online. The application shall contain the desired information and shall submit online on or before the last date prescribed for the purpose along with prescribed fee.
5.	After selection for admission, the candidate shall, within the time fixed by the University, deposit the tuition fee, hostel fee if desire so and other fees prescribed for the course.
6.	<p>At the time of admission, the followings are required:</p> <p>(i) certificates/degrees, along with self-attested Xerox copy of the same. After admission is over, all original documents shall return to the candidate.</p> <p>(ii) Migration and Transfer Certificate shall be produced in original issued from the University/College last attended indicating that he/she passed the qualifying examination from the institution.</p> <p>Provided that, if Dean/Head of the institution concerned is satisfied that there are genuine difficulties in the production of the above certificates, he/she may, on the request of the candidate, give him/her time to submit the above certificate and the candidate shall be admitted provisionally. The provisional admission shall be confirmed only if the candidate submits the above certificate(s) within the prescribed period, failing which the provisional admission shall be cancelled.</p> <p>(iii) Certificate of character from the Principal/Head of the Institution last attended; and</p> <p>(iv) Such other thing may be required along with the application form.</p>
7	Each Faculty/College shall have an Admission Committee for the UG/PG courses constituted under section 4.6. of the First Statutes of the University consisting of the Dean/Head//Principal of the Faculty/Department/College shall be Chairman of the Committee and two senior most members of the teaching staff nominated by the Dean/Head//Principal Faculty/Department/College. The Committee may co-opt additional members, if required so. In the case of PG admission, the Head of the department shall act as the chairman of the Committee.
8.	If the candidate selected for admission to a course, fails to deposit the required fees within the stipulated time, his/her selection shall automatically be cancelled. Such candidate shall not be admitted to the course concerned unless a fresh order of selection or extension of the date of payment of fees is issued by the Dean/Head/Principal of the Faculty/Department/College concerned.
9.	Admission cannot be claimed by any candidate as a matter of right. The admission or re-admission of a candidate shall be entirely at the discretion of the Admission Committee which may refuse to admit any candidate without assigning any reason therefore.
10.	Admission of a student is liable to be cancelled at any time if it is detected that there

	is something against the student which would have prevented him/her from being admitted to the institution for providing false information, act of gross misconduct and indiscipline involve moral turpitude.
11.	Admission of Foreign National/NRI will be made as per Govt. Rules.
12.	A student shall be deemed to have pursued a regular course of study in a subject during the each Semester/Year provided he/she has attended at least 100% of the classes actually held in each subject of higher examination, provided that Dean/Head/Principal of the Faculty/Department/College concerned may condone shortage of percentage on the following reasons: (i) 10% casual illness/ circumstantial essentiality; (ii) 15% on production of documentary evidence duly certify by the Medical Officer to the effect that the student was hospitalized due to pronged illness OR University deputation for youth festival certified by the Head of the Institution. OR Participation in University/College/Faculty Team Games or Inter-University tournaments, duly supported by a certificate from the Secretary of the University Athletic Association concerned/Participation in NCC Camps.
13.	Reservation in Admission for SC/ST/OBC/Minority & Physically Challenged candidates : Seats shall be reserved in the various Faculties/departments/Colleges as per norms of the Bihar Government.
Re-admission	
Re-admission shall be made under the ordinances governing to the each course prescribed in the syllabus of the course concerned.	
Inter University Ordinances	
Notwithstanding anything contained in these ordinances a student, who is qualified under the foregoing ordinances for admission to the University and who is a member of some other Indian University shall not be admitted to the University thereof without the production of : (a) Leaving or Transfer Certificate signed by the Principal of the College Last attended, and certifying to the satisfactory conduct of the students mentioning the highest examination he has passed, and (b) A certified copy of all the entries against his name in the enrollment register of the University if such a copy is obtainable.	

CHAPTER III: Eligibility requirement for Admission to the Various Courses

1.0 Admission to Medical Courses
Admission will be made through the National Eligibility cum Entrance Test or NEET . It is an entrance examination in India, for students who wish to study any graduate medical course (MBBS/ Dental course (BDS) or postgraduate course (MD / MS).
However, any changes by the Government or Regulatory Body shall be followed.
2.0 Admission to all other Courses:
In all other Courses, admission will be made as per eligibility requirement published in the Admission Information Bulletin of the concerned courses through Entrance Test.

However, any changes by the Government or Regulatory Body shall be followed.

CHAPTER IV: ORDINANCES GOVERNING TO CONDUCT OF EXAMINATIONS

1.0 Introduction	
<p>This Ordinance shall be called as Ordinances governing the Conduct of Examinations of the Gopal Narayan Singh University, 2018 (hereinafter called Ordinances) and shall come into force from the date the Board of Governors approves them.</p> <p>The Ph.D. course work Examination and evaluation of Ph.D Thesis shall be governed under Ordinances which shall be framed separately.</p>	
2.0 Enrolment of newly admitted students	
2.1	All newly admitted students in Gopal Narayan Singh University, as full time student will have to get himself/ herself enrolled by submitting the required details on prescribed application form, including original transfer certificate/ migration certificate within prescribed time.
2.2	The fact of issuance of Migration Certificate will be mentioned on the enrolment register against the enrolled student. A student who has not been issued the Migration Certificate can use the enrolment number issued at the time of first entry for entire duration of the course. For all subsequent studies, a student has to filled up again a fresh enrolment form for restoration of the same. If Migration Certificate already issued, it will be required to get himself/herself re-enrolled by submitting a fresh application form with required details, as usual.
3.0 Examination Application Form	
3.1	<p>All examinees (Regular & Ex-student) shall fill up an examination application form in the prescribed format under online mode by the dates notified for the purpose by the Controller of Examinations. The University can refuse to entertain Examination application Form altogether, received beyond the date so notified or can entertain it with late fee up to a limited period, to be notified separately.</p> <p>A “Regular Student” is one who has pursued a regular course of study and obtained prescribed attendance mentioned in respective ordinance and is eligible to appear in the examination.</p> <p>An “Ex-Student” means one who has studied in the Faculty/ College for at least one semester preceding the date of examinations and has filled up the examination forms but failed or has failed to appear in the examination though otherwise eligible.</p>
3.2	All Deans of the Faculties/Principals of the colleges /Heads of the Departments/ Coordinators of Course shall forward all examination forms in respect of each examination together with a hard copy of nominal roll within the prescribed dates, after verifying the correctness of data mentioned therein.
4.0 Examinations and Examiners	
<p>As prescribed in the respective Ordinances governing to different courses of study, each semester would have mid-semester/sessional evaluation and end-semester examination.</p> <p>Mid Semester Examination: For the mid-semester tests and sessionals, the teacher teaching the course would conduct the mid-semester/sessional examinations following the guidelines issued by the concerned Dean of the faculty from time to time.</p>	

The Coordinator of the given course would ensure that the mid-semester assessments are carried out by involving teachers in time and in manner prescribed by the concerned faculty and that the marks sheets for the mid-semester/sessional evaluations are submitted through the Head of Department in a consolidated manner to the office of the Controller of Examinations as per prescribed schedule OR are uploaded on the Examination Portal with a consolidated hard copy of the mid semester marks being provided to the Head of Department.

End-Semester Examinations: As per provisions contained in the Ordinances of the various programs, the question papers for the end-semester examinations shall be set and the answer-scripts shall be evaluated by teachers of the concerned courses.

4.1	Paper Setter for End Semester
4.1(i)	A teacher setting the question paper of End Semester Examination of a course shall be the 'Paper Setter' for the course.
4.1(ii)	Paper Setter should be from outside of the University not below the rank of Associate Professor in all discipline or Assistant Professor of more than 6 years teaching experience.
4.1(iii)	For Medical/Nursing/Pharmacy/Management or any other Technical course, pattern of examination will be carried out as per provisions of regulatory bodies.
4.2	Evaluators
<p>A teacher who evaluates the answer scripts of examinees shall be termed as the 'Evaluator' for the Course.</p> <p>Provided that 'Paper Setter' of a Course shall ordinarily also be the 'Evaluator' of the Course.</p> <p>Provided further that if 'Paper-setter' and Co-Paper Setter/s' are appointed for a course, the 'Paper Setter' shall be Examination Coordinator while others would be 'Co-Evaluator' for the course and shall evaluate the answer scripts pertaining to the concerned component of the Course.</p> <p>Provided further that if a course is run at multiple locations and/or multiple batches and there are more than one teacher teaching the course, then each one of them shall be appointed as 'Co-Evaluator' to examine the answer scripts of the examinees of his/her class/batch.</p> <p>Provide further that the 'Evaluator' and the 'Co-Evaluators' (if required) shall be appointed by the Board of Examiners.</p> <p>Provide still further that if the Board of Examiners considers appropriate, it can constitute a group of Evaluators comprising of University teachers belonging to the concerned subject (irrespective of the general condition that a teacher of the course can only be the evaluator of the course).</p>	
5.0 Board of Examiners and its Term	
5.1	Constitution
Each Board of Examiners shall consist of three members:	
5.1.1	Head of the Department/ Coordinator of the School/Centre concerned (Convener).
5.1.2	Two Senior most teachers of the Department. The HOD/Coordinator at his/her discretion can co-opt subject matter specialist(s), if felt necessary. There will ordinarily be no external member.
(i)	In case a course is not attached to a specific Department, the concerned Course Coordinator shall be the convener and two teachers teaching the course will be

	nominated by the concerned Dean as members. The Convener at his/her discretion can co-opt subject matter specialist(s) if felt necessary.
(ii)	In case the number of teachers in Department/Centre/School is less than 3, the Dean of the concerned faculty shall nominate two senior most teachers involved in the teaching of the course, in addition to Head/ Coordinator, to fill the slots as defined in 6.2.2.
5.1.3	The Term of Office of a Board of Examiners shall be three years.
5.2	Code of Conduct
	Any member/ convener of Board of Examiner will not participate in the proceeding of the meetings held for appointment of examiners in the paper(s) where his/her son/daughter or near relative is examinee or likely to be examinee, provided that in such eventuality, the remaining members will constitute the BoE with senior among them or Head of the Department functioning as Convener.
5.3	Reconstitution of the BoE
	The Board of Examiners shall be reconstituted following the above rules by the concerned Head/ Coordinator as and when a vacancy arises under intimation to the Dean of the Faculty and the Controller of Examinations (CE).
5.4	Procedure and Conduct of Business
(i)	The Convener shall preside at the meetings of the Board and shall be in-charge of the business which may be conducted by meetings or correspondence or both, as may be convenient.
(ii)	The meeting of the BoE should be convened well in advance so that its recommendation are received in the Office of the CE on or before the date scheduled in the Examination Calendar, of the University.
(iii)	In the event of an examiner not being able to fulfill his/her duties for cogent reasons, the Convener of the Board shall nominate other person in consultation with other members of the Board, a substitute.
6.0 Norms for Appointment of Evaluator(s)/ Co-Evaluators	
6.1	For Evaluator of the bilingually papers only such persons should ordinarily be nominated who can evaluate the answer books in either of the languages. Normally paper setter shall evaluate the answer books
6.2	No person should be appointed as Examiner consecutively for more than 3 years for the same paper.
6.3	The number of answer books allotted to a single examiner should not exceed 150 in the case of post graduate examinations and 250 in case of under graduate examinations in each semester.
7.0 Code of Conduct for Examiners (Paper Setter/Evaluator/Co-evaluator)	
7.1	The conduct of examination is an integral part of duty of a teacher and therefore, internal examiners shall not be permitted to refuse the examiner ship unless so exempted for cogent reasons by the Vice-Chancellor.
7.2	The Paper Setter will send the manuscript of question paper along with answer sheets in case of multiple types of questions.
7.3	Any teacher recommended as External/Internal Examiner by the Board of Examiners and approved by the Vice-Chancellor must submit a certificate before accepting their appointment that none of his/her son/daughter/other close relatives is an examinee in the said paper.

8.0 Setting of Question Paper	
	The formal letter of appointment as Paper Setter will be issued by the Controller of Examinations in the prescribed format together with documents necessary for preparation of the question paper, viz, relevant portions of prospectus of study, last year's question paper, a form of acceptance and a remuneration bill form. Acceptance of the appointment and the manuscript of the question paper along with dully filled up remuneration bill form shall be submitted in the sealed prescribed cover to the Controller of Examinations within the date prescribed therefore.
9 .0 Instructions to the Paper Setter	
9.1	Questions must be set with relation to the prescribed course of study. It must conform to the standard and syllabi lay down by the relevant Ordinances of the University.
9.2	Each question shall be clear and well define in language as also in regard to the form and nature of the answers expected from the candidates. Questions shall not be beyond the standard prescribed and shall be fairly distributed over the whole course of study.
9.3	The papers shall be such as a candidate of decided ability and well prepared in the subject can reasonably be expected to answer completely within the allotted time. Question papers should generally follow the pattern for types of questions and choices as defined by the given faculty/department for a given course.
9.4	Paper-setter shall send detailed solution of each numerical question set by him/her along with the question paper.
9.5	Any "Direction to candidates" which may be thought necessary to be given regarding the answering of different sections in different answer-book or regarding the number of questions to be answered or the choice amongst them should be specific, precise and free from ambiguity.
9.6	Information regarding drawing sheets, graph papers, maps, table charts, calculators (of simple function type) and reference books, if any, to be permitted/supplied to the candidates, shall be mentioned in the question paper, and this information shall also be furnished to the Controller of Examinations, separately.
9.7	The Question paper is to be kept in the envelope meant for it. Further, this separate envelope containing solution of numerical Questions and the envelope containing Questions paper are to be kept in a big envelope super scribed "Confidential", and the same must be sent to the Convener of BOM for moderation following which all the moderated papers of a subject are sent to the Controller of Examinations in one bunch by the Head of Department.
10.0 Pattern of Question Papers at the End-semester/Final Examination:	
10.1	The End-semester should in general cover the full syllabus for the course. The questions should be framed to elicit understanding, concepts, and analytical capacity of the examinee rather than only the information and memory power.
10.2	A general suggestive pattern of the question patterns, given in the following paragraphs may be followed. Individual courses, however, may modify the pattern, if required. However, these changes in the pattern may be defined and announced before the examination.

10.3	Duration of a theory paper of 3 or more credits should be of 03 hours. Courses that are of 2 Credits should of 02 hours duration. For technical Colleges it shall be as per its regulatory bodies.		
10.4	Compulsory Question: Each question paper or section thereof should have the 1st question as compulsory and should cover 20%-30% of the full marks of that paper/section. The compulsory question must have parts that together generally cover all the units of the course/paper.The pattern of question paper shall be as follows:		
	i) Multiple choice questions (with at least four choices of which only one is correct), each of 02 marks and requiring justification for the choice in 1 or 2 lines. ii) True/false statements, each of 02 marks and requiring justification for the choice in 1or 2 lines. iii) definitions, 01 mark each iv) brief-answer questions, 2 marks each v) small numerical, 2 marks each vi) matching of terms in two columns (one of the columns should have at least one extra term) with 0.5 marks for each correct match		
10.5	If there is more than one section in a given paper, each section will have its Compulsory question.		
10.6	No. of Questions: The total number of questions and the number of questions to be answered in a question paper (including the compulsory question) may, in general, be as follows		
	No. of Credits for the Course	Total no. of questions	Total no. of questions to be answered
	3 or 4 credits	7 or 8	5 or 6
	2 credits	4 or 5	3 or 4
	1 credit	3	2
In order to cover most of the prescribed content of the given course, each of the optional questions may have sub-sections of varying marks. Generally, the different sub-sections of a question should not be from the same topic/chapter and should not have any internal choices. One of the optional questions may require examinees to write short notes on defined topics; this question may have a limited internal choice. Marks/Credit for Technical College will be as per their regulatory body norms			
11.0 Moderation of Question Paper			
11.1	Board of Moderators There shall be a Board of Moderators (BOM) for each subject, consisting of the following, for the moderation of Question Papers:		
	(i) Head of Institution.		
	(ii) A person with specialized knowledge of the subject, but other than the paper setter, nominated by the Convener.		
	Provided further that the members of Board of Moderators will not participate in the proceeding of the meetings held for moderation of paper(s) where their son/daughter or near relative is examinee or likely to be examinee, provided that in such eventuality, the remaining members will constitute the Board of Moderators with senior among them functioning as Convener.		

11.2	Functions of the Board of Moderators The Board of Moderators shall have following functions:
11.2.1	To ensure that questions have been properly framed and they meet the pattern formulated and standard required.
11.2.2	To check the entire question paper particularly with reference to the following points:
(i)	Title and Code No. of the question paper and course/semester to which it relates.
(ii)	Maximum Marks of the question papers and as to whether the sum of marks of the number of questions to be answered matches with the total marks.
(iii)	Whether the questions represent the prescribed syllabus and if any of the questions are out of syllabus?
(iv)	Whether the pattern of question conforms to the prescribed/recommended pattern?
(v)	Whether Figures and notations are properly drawn/ numbered?
(vi)	Whether permission or otherwise for using calculators is appropriately mentioned?
11.3	Powers of the Board: The Board is authorized to make any corrections/alteration/addition/including change of content of the question(s) proposed by the paper setter if required.
12.0	Examination Schedule
12.1	The examination schedule for end semester examinations for various Certificates/UG & PG courses shall be finalized at least one month before the date of commencement and shall be proposed by the Dean or his authorized representatives for UG courses and HOD/Coordinator concerned in respect of PG courses.
12.2	All admit cards, after proper checking, shall be made available to examinees through the concerned Head/Dean either physically or as soft copy on confirmation of having attained the required percentage of attendance in respect of regular students. Ex-students should either download the admit card or can collect it in hard copy from the Office of the Controller of Examinations at least 03 days before the commencement of the examinations.
13.0	Guidelines to Centre Superintendents and Invigilators
13.1	Centre Superintendents and Invigilators shall be appointed by the Dean of the concerned Faculty (for under-graduate course examinations) and Head/Coordinator of the Department/School/Centre (for post-graduate courses) for conducting each theory paper. Invigilation is integral part of the teaching duty and cannot be refused on the ground that it is remunerative. All faculty members must be assigned duty on an equitable basis in the examination hall as invigilator except when otherwise permitted by the competent authority. There shall be minimum one invigilator for every 25-30 examinees, subject to a minimum of 02 invigilators in each room even if the number of candidates is less than 50-60 in the room. One Centre Superintendent will be appointed for each Centre where a given theory course is being examined.
13.2	Duty of the Invigilators is not to allow any opportunity to the examinees to use unfair means. Reports made about the use of unfair means should be complete in all respects including the statement of the examinee(s) and must bear the

	signature of Invigilators as also the Centre Superintendent of the examination on duty.
13.3	Invigilators are required to check the examinees at the main entry of the Examination Halls/Rooms in presence of the security staff and be vigilant thereafter in the Examination Hall throughout the period of examination.
13.4	The Superintendent of Examination/Invigilator/Proctor can call the security staff in the Examination Hall at their discretion, if a situation so demands.
13.5	The Proctor can call Police in the Examination Hall at his/her discretion, if a situation so demands.
13.6	The Invigilators should remain careful and vigilant regarding the issue of supplementary answer-books to examinees to avoid any malpractice by the examinees in the use of such answer-books. Invigilators will count the number of supplementary answer books issued to a candidate, sign each supplementary answer book and also make an entry on the cover page of the main answer book about the cumulative number of Supplementary answer books issued and keep an account of the supplementary answer books, fill up the statement slip supplied for this purpose and return the same to the Office of the Controller of examinations duly signed at the end of examination.
13.7	After the examination is over, the invigilators should serialize the answer scripts, count them as per the number of students signing on the Roster and hand them over through Superintendent to the representative of the Dean/Head or representative of the Controller of Examinations as per the prevailing guidelines at that time.
13.8	Superintendents and Invigilators kept on the Reserve List are requested to come and report to the Chief Superintendent half an hour before the commencement of examination.
13.9	No invigilator will absent himself/herself from duty without the prior approval of the Director/Dean/Principal taken in writing ordinarily a day in advance of the leave applied for, under intimation to Centre Superintendent. The Centre Superintendent also be informed about such absence so that alternative arrangement for invigilation duty could be made.
13.10	Superintendents and Invigilators are required to sign on each day their names in full and in clear hand-writing on the printed form supplied to Superintendents for claiming the remuneration.
13.11	Superintendents and Invigilators shall adhere to the following guidelines as well:
(i)	No candidate shall be allowed to enter the examination hall after thirty minutes of the commencement of the examination.
(ii)	Candidates shall not be allowed to bring into the examination hall any paper or book or leaflet or mobile or communicative electronic device or any other place of writing except their admit cards.
(iii)	Before the distribution of question papers, Invigilators in a room shall announce to the candidates that any notes, loose-sheets or papers and mobile phone etc. that they may have in their possession be left outside the examination hall.
(iv)	Candidates are required to keep their admit cards with them throughout the period of examination, so that they can be examined at any time. The Superintendent shall by himself/herself or through the invigilator/invigilators,

	inspect the admit cards on each day.
(v)	Superintendents and invigilator/invigilators shall distribute answer-books, original supplementary, personally and not through any other supporting staff.
(vi)	Superintendents shall see that no question paper, after distribution, goes out of the examination hall. All spare copies of the question papers shall be returned to the Superintendent by the Invigilators, immediately after the distribution is over.
(vii)	Candidates shall not be allowed to leave the examination hall once they have been admitted thereto, until the expiry of one hour from the commencement of the examination.
(viii)	Subject to the foregoing rule (vii), a candidate may be allowed to leave the examination hall at any time before it is 10 minutes to last bell, if he/she delivers up to the Superintendent or the Invigilator his/her answer books; such a candidate shall not be re-admitted during the pendency of the examination in that paper.
(ix)	None but the candidates under the foregoing rule, the Invigilators concerned, Controller of Examinations and the officers so nominated by Vice-Chancellor shall enter the examination hall except with the previous permission of the Superintendent.
(x)	Letters and any other communications and eatables including Tea, Pans & Cigarettes shall not be allowed to be delivered to or received by the candidates in the examination hall.
(xi)	Candidates shall not, during the examination, be permitted to talk to one another nor shall anyone be allowed to communicate with them, on any subject whatsoever, provided nothing in this rule shall be deemed to prevent a Superintendent from making by himself/herself or through the Invigilator, an announcement which he/she thinks proper or necessary.
(xii)	Invigilators and Observers shall remain within the Examination Hall throughout the period of examination and shall remain moving about in the Hall. The Superintendent shall give frequent visits to the examination room(s) under his/her charge and see that this rule is strictly followed by the Invigilators. The Invigilators shall not go out of the Hall except with the permission of the Superintendent and shall not use mobile phone while on duty.
(xiii)	When an Invigilator finds a candidate guilty of using unfair means in the examination, he/she shall report the matter immediately, in writing, to the Superintendent concerned. The Superintendent shall withdraw the answer book so far written by the candidate and the material in support of the finding and provide a separate answer book to the student immediately to write the answers to the remaining questions. After the days' examination is over, the candidate shall be asked to give a written explanation which may be scrutinized by the Invigilators and the Superintendent. Their reply to the points raised by the candidate along with their opinion be submitted in writing to the Controller of Examinations on the same day on the printed form supplied for the purpose along with such material in support which might have been recovered from the candidate.
(xiv)	Candidates shall not be allowed to take away any leaf from the answer books or to take away any unused answer books (original or supplementary); if any leaf

	is found to be loose by the candidate, he/she should bring it to the notice of the Invigilator immediately.
(xv)	Candidates shall not be allowed to write anything on the question paper or on their person or on their clothing or on any instruments that they are allowed to carry with them.
(xvi)	Candidates, who have finished answering their question paper at any time before 10 minutes to the last bell, shall remain standing in their seats till the answer books have been collected from them by the Superintendent or the Invigilator. No candidates shall be allowed to leave his/her seat during the period of 10 minutes before the last bell.
(xvii)	Candidates wishing to communicate with the Superintendent or Invigilator shall not be allowed to leave their seat but shall stand in their places and should be attended by the invigilator/invigilators immediately.
(xviii)	As soon as the last bell has been rung, candidates shall stop writing and remain in their seats; any answer or portion of answer written thereafter may be crossed out by the Superintendent or invigilator/invigilators who shall make an entry to that effect and sign and date the same.
(xix)	The answer books shall be printed in two forms (a) original and (b) supplementary. An original answer books shall be supplied only one. When more answer books are required by a candidate, supplementary answer books only shall be supplied.
(xx)	On each day of the examination, sufficiently in time before the commencement of the examination, the Controller of Examinations shall have the required number of original answer books counted and issued to the Superintendent concerned and so also a sufficient number of supplementary answer books, under receipt.
(xxi)	The Superintendent shall, at the end of each day's examination, return to the Controller of Examinations/ Centre Superintendent the unused original and supplementary answer books to the Controller of Examinations with the list of the candidates, present and absent.
(xxii)	On each day of the examination, the Superintendent shall, with the assistance of the Invigilators, see that each candidate has entered the required details on the cover page of his/her answer books; he/she or the Invigilator deputed by him/her shall sign and date each answer book on the cover page.
(xxiii)	Before complying with the request of any examinee for issue of supplementary answer books, the Superintendent/Invigilator should satisfy himself/herself that issue of supplementary answer book is actually necessary.
(xxiv)	At the time of issue of supplementary answer book, the invigilator shall ensure that the required entries on the cover page of supplementary answer books are made by the examinee concerned. The invigilator shall also sign and date each supplementary answer book against the column provided for the purpose on the cover page.
(xxv)	In cases where examinees have used supplementary answer books, the invigilators shall ensure that an entry to that effect is duly made against the column provided for the purpose on the cover page of original answer book and the Invigilator should put his signature with the date below said entry.
(xxvi)	Soon after the commencement of Examinations, the Superintendents/ Invigilators shall take the signature of examinees on the Roster provided for the

	purpose. Examinees have to sign a Roster at each sitting of the Examination, which should tally with the signature on the Admit Card/List. It is the responsibility of both the Superintendent and the Examinee concerned to see that the signature is taken on the Roster. In the event of the examinee refusing to sign or the signature not tallying with the one on the Admit Card/List, the answer book of the candidate concerned will not be sent to the examiner for evaluation, but kept in the Controller's custody to be destroyed later as waste paper. Before taking such an action, the Controller of Examinations shall give a reasonable opportunity to the examinee concerned, to explain the position.
(xxvii)	The Superintendent shall file with the Controller of Examinations/Centre Superintendent each day at the end of the examination, a statement of candidates, present and absent, in the printed form provided for the purpose.
(xxviii)	All invigilators must surrender main answer books which remained undistributed to the Centre Superintendent with proper accounting within one hour of commencement of said paper.
(xxix)	Wherever required, frisking of the candidate(s) may be undertaken, preferably prior to commencement of examination.
(xxx)	The invigilators in their reports on unfair means/practice should enumerate only the facts and should not recommend possible action to be taken against the concerned examinee(s).
14.0 Unfair means	
14.1	Ordinances:
(A)	'Unfair Means' includes any act which tends to give undue advantage to the examinee, or improperly affects him/her in the matter of performance at the examination or evaluation of the performance;
(i)	
(ii)	Without prejudice to the generality of the foregoing provision, "unfair" shall include:
	(a) All such acts and omissions connected with examinations which are subject matter of disciplinary action in the University,
	(b) Abetment of unfair practices,
	(c) Conspiracy to further the interests of an examinee by resorting to unfair practices,
	(d) Possession of unauthorized books, papers, informative materials of any kind whatsoever, connected with the examination.
	(e) Communication of information in the examination premises during the examinations hours,
	(f) Impersonation.
	(g) Tampering with or substitution of Admit Card, examination answer-books, papers and other relevant documents,
	(h) Communication with examiners or persons connected with examination with a view to obtain undue advantage or discriminatory action or unauthorized information,
	(i) Violation of any direction given by the appropriate authority of the University,
	(j) Possession of unauthorized electronic gadgets like mobile phone, calculator, laptop, ipod, ipad etc. or such other informative materials of any kind whatsoever, connected with the examination.
	(k) Possession of weapons.

	(l) Smuggling of answer books
(iii)	"Resource Material" means unauthorized books, papers informative material of any kind which can be used in furtherance of the interest of an examinee in the examination hall.
(iv)	"Unfair Means Committee" (UMC) means the Committee constituted under the ordinance 14.9
(v)	"Walk-Out" means the act of the examinees, after having entered and taken their seats in the examination hall/room/any place meant for the purpose, and after the distribution of the answer-books or question papers or both, decide not to appear in the examination on one or more of the pleas, to leave their allotted seats individually or jointly with or without making a protest of any kind, signing the attendance sheet (Roster), submitting the answer-books to the invigilator/Superintendent of the concerned examination and without creating any disruption.
(vi)	"Boycott" means staying away by the examinees individually or jointly from appearing in the examination, and notifying about it on or before the commencement of an examination, with a view to compel the authorities to accede to a demand.
(vii)	"Disruption in Examination" means where an examinee/any person individually, jointly or in collusion with other examinees or any other person, either before or after having entered the examination hall/room any place meant for the purpose, and either before or after distribution of the answer-book and the question paper does/do any act or instigate any other examinee/person for the commission of an act, such as, assaulting, manhandling, using of abusive language, creating rowdism, snatching and tearing of answer-books and such other things etc., so as to cause disturbance in the smooth conduct of the examination either in the centre in which he/she is scheduled to appear or is appearing, or in any other Centres of the examination.
(viii)	"Impersonation" means adopting unfair practice of allowing someone not duly authorized to appear and write the examination for himself/herself by conspiracy.
(ix)	"Smuggling" means taking out from or in the examination hall part or full answer book or related material supplied by the University for the use of examinee.
14.1 (B)	An act shall be deemed to be interfering with the proper conduct of examinations if it affects the peace and tranquility of the examinations premises, or results in violation of the directions of the Invigilator and other Officers connected with the examinations and, causes tension among the examinees in any of the following manner:
(i)	Bringing with him/ her into the examination room/hall any book, notes or other materials capable of being used by him/ her in connection with the examination
(ii)	Communication with or receiving from any other candidate any information.
(iii)	Assisting or receiving assistance from any other candidate in examination or adopt any unfair means to further his/her interests in connection with an examination.
(iv)	Adopting any unfair practice to further or adversely affect the interests of an examinee or indulge in act which interferes with the proper conduct of examinations.

14.2	The Invigilator shall report, on the prescribed form, all cases of violation of the provisions of clause 14.1 to the Superintendent of Examinations immediately he/she comes to know of such violation. Where the Invigilator detects an examinee copying or suspects his/her having copied, the Invigilator shall take back the answer-books already provided to a candidate alongwith the resource material and shall forthwith provide a new answer-books to the examinee concerned.	
	Note: If material is written on body parts or clothes, Invigilators shall copy the readable material written on a piece of paper under his signature and get it signed by the concerned examinee and also countersigned by Centre Superintendent, before forwarding it as enclosure of the duly filled in 'unfair means' proforma (UMC Schedule-I). Relevant part of the body be also photographed through the office of the Chief Proctor.	
14.3	The Superintendent of the examinations shall give the examinee an opportunity to submit a written explanation in his/her defense against the charge of unfair means on the prescribed format. The Superintendent of the Examinations may, after satisfying himself that the circumstances so demand, order the concerned candidate to vacate the examination premises forthwith, if his/her act interferes with the proper conduct of examination.	
14.4	The Superintendent of the Centre concerned, where an examinee is found using unfair means, shall provide another answer book to the student to write answers to the remaining questions for remaining time period.	
14.5	Any person, other than an examinee, violating the provisions of clause 14.1 (B), may be ordered by the Superintendent of Examinations to leave the examination premises immediately and the University shall take such further action in the matter as it deems fit and proper.	
14.6	In the event of notice of use of unfair means by a large number of examinees or in the event of refusal by examinee (s) to give statement, the Invigilator/Superintendent shall submit a confidential report to that effect to the Controller of Examinations and the University shall take suitable disciplinary action against the examinee (s) on the basis of such report. In such cases the names of the Invigilator/Superintendent making the report shall be kept confidential.	
14.7	On the written explanation submitted by the examinee alleged to have violated the provision of clauses 14.1 (B), a confidential report under the provision of clause 14.1 (A) shall be placed before the Unfair Means Committee for appropriate action.	
14.8	The following punishments are prescribed for the examinee/s found for using unfair means or adopting unfair practice during the examination:	
	Punishable Act	Punishment
(i)	Smuggling of answer book and / or pages thereof	Cancellation of the entire Examination and rustication for a period of TWO Academic Sessions
(ii)	Copying	First time Cancellation of the paper of the day. Second time in the same examinations cancellation of entire examination. in case of following courses like MBBS, BAMS

		Cancellation of entire paper of the concerned subject
Explanation: In case of cancellation of the semester examination the examinee shall be permitted to appear at the Second/Supplementary/Special Examination of the concerned annual /semester examination (whenever held) of that session. Further, such candidates will be eligible for promotion to the higher class/semester, if they are otherwise qualified for the same.		
(iii)	Found in possession of material relating to examination	Cancellation of examination in the concerned paper. For repeated act in the same examination on that day or any subsequent day, cancellation of the entire examination.
(iv)	Talking and consultation	Cancellation of examination in the concerned paper for repeated consultation even after warning by Invigilator/ Superintendent/ and other person deputed on examination duty.
(v)	Mass Copying in a paper duly reported by Invigilators and Superintendent (s) or by any other person deputed on examination duty.	Cancellation of the examination of the concerned paper of all examinee with no re-examination. Closing the examination centre concerned in the event of repetition of mass copying, or such other action as may be recommended by a committee to be nominated by the Examination Co-ordination Board.
(vi)	(a) Use of abusive Language (b) Assault/Manhandling (c) Creating rowdy condition (d) Tearing of answer-books	Necessary disciplinary action in addition to cancellation of entire examination.
(vii)	Attempt to influence an examiner if reported by the examiner concerned.	Cancellation of examination in the concerned paper and suitable disciplinary action, after enquiry.
(viii)	Conspiracy for Impersonation	Cancellation of entire examination and rustication for one Academic Session of the candidate as well as the person who is found impersonating if he/she is University student. In case the person impersonating is not University student he/she may be handed over to the Chief Proctor for further appropriate action.
(ix)	(i) Walk-out	Deemed absent, except for cogent reasons to be decided by the Central Grievance Board.
	(ii) Boycott	Deemed absent
(x)	Disruption in Examination	Cancellation of Examination and rustication for two Academic sessions. Action to be taken on the basis of report of Invigilator/Superintendent, Member of the Flying Squad after enquiry.
14.9	All the matter of Unfair Means shall be scrutinized by the Unfair means Committee (UMC) to be constituted by the Vice-Chancellor, comprising of	

	following members:	
(i)	A Senior Professor of the University	Chairman
(ii)	One Professor/Associate Prof. of Law:	Member
(iii)	One Professor of any other faculty:	Member
(iv)	The Controller of Examinations:	Member
(v)	The Asstt/Dy. Registrar (Exams):	Secretary
(vi)	The Dean and HOD of concerned Faculties:	By invitation
(vii)	The Subject expert:	By invitation
The Committee shall be constituted for each Academic Session and its recommendations would be implemented after approval of the Vice-Chancellor.		
15.0 Special Facilities for persons with disabilities		
(i)	The facility of providing “writer” during regular examination would be extended on recommendation of the University Medical Board to the candidate with disability, if so requested by him/her. The modalities for allowing the engagement of writer, allowing extra time would be as per notification of the University.	
(ii)	The guidelines issued by the Govt. of India from time to time for extending special facilities to persons with disability would be applicable to the University.	
16.0 Redressal of Grievance of students regarding question paper		
16.1	If an examinee or examinees has/have any genuine grievance regarding the question paper, he/she or they can make a representation, in writing to the Controller of Examinations individually or jointly, after the examination is over but within 48 hours.	
16.2	Preliminary enquiries on the representation will be made by the Examination Grievance Board consisting of the Head of the Department, the other members of the Moderation Board, and teaching the paper concerned. The Examination Grievance Board shall meet within 48 hours of receipt of the representation from the Controller of Examinations’ office.	
16.3	The Examination Grievance Board (EGB) shall give its comments on the following points only with regard to the concerned question paper	
(i)	whether the questions are covered by the prescribed syllabus;	
(ii)	whether the pattern of question conforms to the approved pattern;	
16.4	Head of the Department shall submit the report of the Grievance Board to the Dean of the Faculty concerned within 24 hours of the meeting of the Board.	
16.5	The recommendation of the Examination Grievance Board shall be forwarded by the Dean to the Controller of Examinations for being placed before a Central Grievance Board consisting of the following:	
(i)	Two Senior teachers of the University to be nominated by the Vice-Chancellor, one of whom shall be the Chairman;	
(ii)	Chairman, Examination Coordination Board - Ex-Officio Member	
(iii)	Dean of the Faculty and/or Director of the Institute concerned	
(iv)	Controller of Examinations	
(v)	Head of the Department concerned	
(vi)	The Asstt/Dy. Registrar (Exams), Member Secretary	
16.6	The Central Grievance Board shall consider the comments/recommendation of the EGB and shall recommend to the Vice-Chancellor whether any re	

	examination of the concerned paper is to be arranged. Provided further that the Central Grievance Board can also, at its discretion, recommend any other remedial measures that may be required for redressing the grievances of students.
17.0 Examination System	
17.1	Evaluation of answer scripts
17.1.1	a. Each theory/practical/seminar/field work/project work/ dissertation course shall be of 100 marks. For evaluation, the overall structure of the distribution of marks in a course shall be such that 25 marks are allotted to various assessments during the semester, while 75% marks shall be allotted for the end semester examinations.
	b. The distribution of marks (sessional University examination) for Medical, Nursing and Pharmacy courses the rule will be applicable to all courses in the University as per guidelines of MCI/DCI/CCIM/Nursing Council of India in respect of courses governed by these regulatory bodies.
	c. The question papers shall be set and the answer-scripts shall be evaluated by the teachers of the concerned courses. If more than one teacher teaches the course, the question paper shall ordinarily be set by the Paper-setter in consultation with other associated teachers of the group, appointed by the Board of Examiners.
17.2	Receipt of sessional and end semester awards and their tabulation
(i)	The component to be evaluated for award of sessional marks will be as prescribed in ordinance of the respective courses.
(ii)	The marks awarded, arranged roll number wise, in the sessional examinations for different courses must be made available to the office of the Controller of Examinations prior to the commencement of the given End Semester examination.
(iii)	In respect of End Semester examinations, the marks must be sent to the Controller of Examinations office online along with hard copy by the appointed examiner within the time prescribed under the examinations calendar. The Tabulation of the University examination results shall be done in the office of the Controller of Examinations.
(iv)	Checkers for checking the Tabulated results shall be appointed who shall be check the Tabulated results Tabulation Registers in the office of Controller of Examinations.
(v)	Work of tabulation and/or checking can also be done electronically and/or manually by teachers/non-teaching staff/officers, appointed for the purpose. Tabulators and checkers be paid remuneration as per the rates prescribed by the University from time to time.
17.3	Grace Rules
The following rules for grace marks will be uniformly applied to all examinations including Diploma, Under-graduate and Post-graduate degrees under all the Faculties of the University:	
(i)	0.5% marks will be awarded to each subject maximum to three subjects(papers) including theory and practical separately in the mid/end semester examination.
(ii)	Any fraction in computation of 0.5% shall be rounded off to the next higher integer.
(iii)	All grace marks awarded be shown as +G in the Grand total as well as at the

	places where the Grace marks were awarded. Further, grace mark awarded at a place, will not be carried forward at any other place.
(iv)	The above Grace Rule will not be applicable to technical courses. The regulations of its regulatory bodies will be applicable for the same.
(v)	Grace marks shall not be given separately for Supplementary or Second Examinations.
(vi)	No Grace marks shall be awarded for the examinations where the candidate can be promoted even if he/she fails in one or more papers.
(vii)	No grace mark shall be awarded for making up shortfall in the SGPA/CGPA.
17.6	Declaration of Results and issuance of mark sheet
(i)	All Results should be declared within the last date notified in examination calendar in order to ensure timely commencement of the next academic session.
(ii)	The classification of results as PASSED, PROMOTED or FAILED and the assignment of division to passed candidates will be as defined in the Ordinances governing individual courses
(iii)	The ranking of the student shall be given to only those candidates who pass all the courses of the program in one attempt.
(iv)	Notwithstanding any provision in the ordinance to the contrary, a student, who having been duly admitted to a regular examination of the course, was unable to take that examination in full or in part due to some disruption of examination, and took the next following examination of that course and passed, shall also be eligible for ranking.
(v)	A Provisional Certificate of having passed examination shall be issued by the office of the Controller of Examinations, if so requested by the candidate.
(vi)	The marks-sheet for courses following credit system must necessarily indicate on its back the formula of conversion of CGPA to Percentage .
17.7	Re-Totaling/Re-Evaluation
In case of any objection made by student referring evaluation, the same shall be looked after by the panel of two senior faculties nominated by Dean of Faculty after approval of Vice Chancellor. A fee, as decided by the university, shall be levied for the same.	
18.0	Malpractices by any persons connected with the conduct of Exams
18.1	The Board of Examinations shall be competent authority to take appropriate disciplinary action against the paper setter, examiners, moderators, referees, teachers or any other person connected with the conduct of examination committing lapses or using, attempting to use aiding, abetting, instigating or allowing to use malpractice/s at the examination conducted by the University.
18.2	Definitions: Unless the context otherwise requires 1. "Paper setter, Examiner, Moderator, referee and teacher means and includes person/s duly appointed as such for the examination by the Board of Examinations and the term any other person connected with the conduct of examination" means and includes person/s appointed on examination duty by authorized person. 2. Malpractice or lapses includes one or more of the following acts or omissions on the part of the person/s included in above relating to the examinations: (i) Leakage of question/s or question paper set at the University examination, before the time of examination; (ii) Examiner or Moderator, intentionally awarding marks to student in

	<p>assessment of answer books dissertation or project work to which the student is not entitled or not assigning marks to the student to which the student is entitled;</p> <p>(iii) Paper setter repeating question or setting question outside the scope of syllabus;</p> <p>(iv) Examiner or Referee showing negligence in detecting malpractice used by student/s;</p> <p>(v) Invigilator or Jr. Supervisor or Chief Conductor showing negligence or apathies in carrying out duties or aiding or abetting or allowing or instigating students to use malpractice/s;</p> <p>(vi) Or any other similar act/s and or omissions/s which may be considered as malpractices or lapses by the concerned authority.</p> <p>3. "Malpractices or lapses relating to examination" means and includes directly or indirectly committing or attempting to commit or threatening to commit any act of unfair means, fraud or undue influence with a view to obtaining wrongful gain to him or any other person or causing wrongful loss to other person/s or omitting to do what he is bound to do as duties.</p>
19.0 Payment of Remuneration	
(i)	Rates of remunerations to be paid to teachers for invigilation duty, working as Centre Superintendent, as paper setter and/or evaluator shall be decided by the University from time to time and notified accordingly.
(ii)	Non-teaching staff engaged in the examination work will also be remunerated as per the notifications applicable to them.
20.0 Disposal of Answer Books of candidates	
<p>After the Semester results are declared, the Answer-books of the students shall be preserved for a period of six months of such declaration and in case Medical, Nursing and Pharmacy the rules of MCI/CCIM/NCI/PCI will be applicable. There after they shall be pulped in paper-mill in the presence of the office staff of the Office of Controller of Examinations not below the rank of Section Officer/Senior Assistant and would be disposed of following the prescribed procedure.</p>	
21.0 Preparation of Degree	
<p>All Degrees shall be prepared within three months of declaration of results of the supplementary examinations. The Year of the award of a degree shall be the year of the date on which a candidate has successfully earned all the required Credits/passed all examinations of the course as prescribed in the Ordinances of the concerned course. The degrees which could not be distributed during the Convocation will be sent to the home address of the candidate by Registered/Speed-Post, charges for which shall be paid by the University.</p>	
22.0 Removal of Difficulties	
<p>Where any question relating to the interpretation of the Ordinance or any rule framed therein arises, shall be referred to the Vice-Chancellor for final decision. Further, the Vice-Chancellor shall also have the power to remove the difficulties in implementation of any of the provisions of the Ordinance.</p>	
23.0 Amendment of Ordinances	
<p>Notwithstanding anything contained in the Ordinance, the Vice-Chancellor may amend, modify or repeal any of the provisions of the Ordinance and report the same to the Academic Council and the Board of Governors.</p>	
24.0 Commencement	
<p>This Ordinance shall come into effect from the date of notification.</p>	

25.0 Examination Calendar	
There shall be an “Examination Calendar” notified in the beginning of the session, indicating therein dates of various activities. This shall be scrupulously observed by all concerned in order to ensure timely completion of all activities including declaration of results.	
26.0 Conferment of Degrees, Diplomas and other Distinctions	
26.1	The Degrees shall be conferred in an annual Convocation or in a separately organized convocation for the purpose of conferring degrees for specific reason
26.2	The Academic Council shall approve the text and the format of the degrees, diploma and the citations
26.3	The Visitor or in his absence; the Chancellor; or in the absence the Chancellor, the Vice-Chancellor shall preside over the convocation or the special convocation.
27.0 Medium of Instruction and Examinations	
	The medium of instruction and examinations shall be English, Hindi or respective languages

CHAPTER V: Award of Fellowships, Scholarships, Medals and Prizes

1.0 Introduction	
The Deans of the faculties shall institute and decide the policy for the award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes, to be approved by the Academic Council	
2.0 Co-operation and Collaborations	
The scope and the terms and conditions of cooperation and collaboration shall be as approved by the Board of Management from time to time	
2.1	<p>The University may cooperate and collaborate with other Universities, Institutions, Centers of Excellence and ‘Persons of Eminence’ on mutually agreed terms in areas including the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Establishment of University Centre abroad; (ii) Joint Research projects funded by national and international agencies; (iii) Exchange of faculty; (iv) Twinning program, Articulation of syllabus, Exchange of students at Under Graduate, Post Graduate level and higher levels under credit transfer arrangement; (v) Sharing of course and instruction materials; (vi) Developing e-courses for interactive and integrated learning; (vii) Sharing of Library, Laboratory and other learning resources; (viii) Joint arrangement for: <ul style="list-style-type: none"> (a) Holding Conferences, Seminars and Workshops; (b) Training and Internship Programs; (c) Refresher and continuing education Courses; (ix) Expert lectures; (x) Any other activities of mutual interest

3.0 Maintenance of discipline among Students	
3.1	Maintenance of discipline among the students is key to quality of education.
3.2	All powers relating to maintenance and enforcement of discipline and taking disciplinary action against the students shall vest in the Vice- Chancellor.
3.3	The Vice-Chancellor may delegate his powers pertaining to exercise of disciplinary control over the students to the Deans of the respective faculties
3.4	<p>Without prejudice to the generality of the power to maintain and enforce discipline under this ordinance, the following shall constitute as an act of misconduct on the part of a student of the University:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) physical assault or threat to use the physical force against any member of the teaching or non-teaching staff of the University or against any student of the University; (b) remaining absent from class, test or examination or any other curricular or co-curricular activity without permission of the concerned person; (c) carrying of, threat of, or use of any weapon; (d) misbehavior with employee of the University or a fellow student; (e) encouraging or indulging in violence or any act of unbecoming of student; (f) involving in any act or any offence involving moral turpitude; (g) violation of status, dignity and honor of a student belonging to weaker and socially deprived class or community; (h) discrimination against any student or staff on grounds of caste, creed, language, place of origin or social and cultural background; (i) practicing casteism and untouchability in any form or inciting any other person to do so; (j) any act, whether verbal action or otherwise or derogatory remarks in case of a woman; (k) any form of gambling; (l) an attempt of bribing or corruption in any manner; (m) willful destruction of the University property; (n) behaving in a rowdy, intemperate or disorderly manner in the premises of the University or encouraging or inciting any other person to do so; (o) causing disruption in any manner of the academic functioning of the University; (p) indulging in or encouraging any form of disruptive activity related to the assessment or the examination work or any other activities of the University; (q) indulging in any act of ragging; (r) use of drugs or other intoxicants banned by the Government; (s) any other act that may be construed as misconduct such as: <ul style="list-style-type: none"> (i) an act of sexual harassment perpetuated against a student, employee or a visitor in and around the University campus; (ii) resorting to mass bunks; (iii) staging dharna or any other form of protest against the University without resorting to Grievance Redressal mechanism of the University; (iv) committing theft of equipment, books, appliances, gadgets or any other material, tangible or intangible

3.5	The Vice-Chancellor may, on the recommendation of Dean, in exercise of the powers vested in him, order or direct that a student: (a) be expelled from the University for a specified period; (b) be rusticated for a specified period and shall not be admitted to any course in the University nor shall he be allowed for any examination of the University; (c) be imposed fine
3.6	At the time of admission, every student shall sign an undertaking that he shall submit himself to the disciplinary jurisdiction of the Vice-Chancellor and Dean of the School where he has been admitted
3.7	Provisions for prohibition of ragging: Ragging in any form is strictly prohibited within the University premises, in public transport or at any other place, public or private. Anybody found involved in an act of ragging shall be dealt with strongly including registration of criminal case with the police
3.8	Any individual or collective act or practice of ragging shall be treated as an act of gross indiscipline and shall be dealt with under the provisions of this Ordinance or the provisions of law enacted from time to time
3.9	Ragging, for the purposes of this ordinance, shall ordinarily mean any act, conduct or practice by which the dominant power or status of senior students is brought to bear upon the students who are in any way considered junior or inferior by the former and includes individual or collective acts or practices consisting of: (a) Physical assault or threat to use physical force; (b) Violation of the status, dignity and honor of students; (c) Expose students to ridicule or contempt or commit an act which may lower their self-esteem; (d) Verbal abuse, mental or physical torture, aggression, corporal punishment, harassment, trauma, indecent gesture and obscene behavior.
3.10	The Dean shall take immediate action either on his own or on the receipt of a complaint or information of ragging or its likelihood coming to his knowledge
3.11	The Vice-Chancellor, if satisfied that there was ragging or an attempt of ragging shall impose a penalty on the students involved in such act of ragging.
3.12	The Disciplinary Committee shall be constituted by the Vice-Chancellor to maintain discipline on the premises of the campus including hostels and avoid acts of indiscipline and ragging of students. The composition of the Disciplinary Committee shall be as under: (i) A Professor of the University - Chairman; (ii) Five teachers, of which one shall be a lady teacher and one from Backward Class of the University; The tenure of Disciplinary Committee shall be for a period of one year.
4.0 Migration of Students	
	Inter-university migration of the students may be allowed on the recommendation of a committee consisting of three members appointed by the Vice-Chancellor under the chairmanship of the Dean concerned.
5.0 Convocation	
5.1	The Convocation for the purpose of conferring degrees and other distinctions of the University shall be held annually on such date as the Visitor may fix.

5.2	The Convocation for the purpose of conferring degrees and other distinctions of the University shall be held annually on such date as the Visitor may fix.
5.3	The Academic Council shall approve the degrees, diplomas and other distinctions to be conferred.
5.4	The Examinations unit shall prepare a list of students who have completed all the requirements for conferment of a degree, diplomas and forward it to the Dean of the School/Faculty/Institute.
5.5	The Degree Certificates shall be signed by the Vice-Chancellor.
6.0 Academic Calendar	
6.1	The normal duration of the course leading to respective degrees shall be divided into the number of semesters specified in the structure of the respective courses.
6.2	The normal duration of the course leading to respective degrees shall be divided into the number of semesters specified in the structure of the respective courses.
6.3	Every academic year shall be divided into two semesters, each of minimum ninety working days duration including Examinations.
6.4	The schedule of academic activities for a Semester, including the dates of registration, mid-semester examination, end-semester examination, re-examination, inter-semester vacation, etc. shall be named as the Academic Calendar of the Semester, which shall be prepared by the Dean and approved by the Vice-Chancellor.
6.5	The Academic Calendar must be adhered to, and all other activities including co-curricular or extra-curricular activities must be scheduled so as not to interfere with the Curricular Activities as stipulated in the Academic Calendar.
6.6	Under any circumstances when any of the teaching days are declared as Holidays or otherwise when the classes get suspended, irrespective of any reasons, appropriate makeup for such loss shall be made by Program Coordinator by arranging the lectures or lab or teaching sessions on suitable days.
7.0 Registration	
7.1	Every Student after consulting his Faculty-Advisor is required to register for the approved courses of Parent Department at the commencement of each semester on the days fixed for such registration and notified in the academic calendar. Program coordinator will monitor and appoint Departmental Committees in order to properly facilitate course registration. All students must personally be present on these dates.
7.2	Every Student after consulting his Faculty-Advisor is required to register for the approved courses of Parent Department at the commencement of each semester on the days fixed for such registration and notified in the academic calendar. Program coordinator will monitor and appoint Departmental Committees in order to properly facilitate course registration. All students must personally be present on these dates.
7.3	Lower and upper limits of the course registered credits in a semester by a full-time student for a course shall be as follows: A full time student of a particular course shall register for the appropriate number of course credits in each semester i.e. within the minimum and maximum limits specific to that course as stipulated in the Regulations pertaining to that course.

7.4	Mandatory Pre-Registration for higher semesters: In order to facilitate proper planning of the academic activities of a semester, it is essential for the student to declare their intent to register for an elective course well in advance, before the actual start of the academic session, through the process of Pre-Registration, which is mandatory for all the students of second or higher semesters, wherever applicable. The schedule of pre-registration shall be declared on website and in the academic calendar.	
7.5	All students, other than the newly admitted students intending to register for the next higher semester are required to have completed the Mandatory Pre-Registration of elective courses, wherever applicable, at least TWO weeks before the last day of instruction specified in the academic calendar of the current semester. To facilitate this pre-registration, all teaching departments shall announce the list of courses to be offered for the next higher semester, at least FOUR weeks before the last day of instruction specified in the academic calendar of the current semester.	
7.6	Course Pre-Requisites: In order for a student to register for some specific courses, it may be required either to have knowledge of the credit course or registered, or have completed satisfactorily, or have prior earned credits in pre-requisite courses as prescribed by the respective Deans.	
7.7	Students who do not register on the day announced for the purpose may be permitted LATE REGISTRATION up to the notified day in academic calendar on payment of late fee.	
7.8	REGISTRATION IN ABSENTIA will be allowed only in exceptional cases through the authorized representatives of the student with the approval of the Head of the Department.	
7.9	A student will be permitted to register in the next semester only if he fulfills the following conditions: (i) satisfies all the academic requirements of the course of studies; (ii) cleared all Departmental dues, Hostel and Library dues and fines, if any, of the previous semesters; (iii) paid all required advance payments of the University and Hostel for the current semester; (iv) Has not been debarred from registering on any ground by the University.	
8.0Credit and Evaluation System		
8.1	The norms of UGC and other regulatory body shall be followed	
9.0Maximum duration for the completion of a program		
9.1	The maximum duration for completion of a program, shall be as detailed below:	
	Normal Duration (Years)	Maximum duration allowed (Years)
	1	2
	2	4
	3	6
	4	8
	5	10

9.2	The maximum duration for completion of a program, shall be as detailed below:	
	Normal Duration (Years)	Maximum duration allowed (Years)
	1	2
	2	4
	3	6
	4	8
	5	10
The enrolment of the student, who fails to complete the requirements of the award of a degree or diploma or certificate in prescribed duration, shall stand cancelled and no degree or diploma certificate shall be awarded.		
10.0 Transfer of Credits		
10.1	The courses for which credit obtained elsewhere, in Indian or foreign University or Institutions or Colleges by students during their study period may count towards the credit requirements for the award of degree.	
10.2	The credits transferred will reduce the number of courses to be registered by the student at the University. The guidelines for such transfer of credits shall be prepared by a committee of three Deans of the faculties nominated by the Vice-Chancellor. These guidelines shall be required to be approved by the Academic Council.	

11.0 Withdrawals from the Program	
11.1	Temporary Withdrawal
(i)	A student who has been admitted to a course of studies of the University may be permitted to withdraw temporarily, for a period of one semester or more, on the grounds of prolonged illness or otherwise;
(ii)	He applies to the Head of the Department stating fully the reasons for withdrawal;
(iii)	There are no outstanding dues with the Departments or University or Hostels or Library etc.;
(iv)	The decision of the Head of the Department of the University regarding withdrawal of a student is final and binding.
11.2	Permanent Withdrawal:
(i)	Any student who withdraws admission before the closing date of admission for the Academic Year is eligible for refund of the fees and deposits, after deduction of the processing fees as may be decided by the Vice-Chancellor.
(ii)	Once the admission for the year is closed, the following conditions shall govern the withdrawal from admission: <ul style="list-style-type: none"> a) A student, who wants to leave the University, shall be permitted to do so and take Transfer Certificate from the University, if needed, only after clearing all the dues. The fees and other charges paid by the student shall be refunded after deducting the processing charges, as may be decided by the University. b) Those students who have received any scholarship, stipend or other forms of assistance from the University shall re-pay the same. c) The decision of the Head of the Department regarding all aspects of withdrawal of a student shall be final and binding.

12.0 Committees or Functionaries	
The following committees shall be constituted for the various programs of studies to entertain the appeals of the students:	
12.1	Departmental Academic Appeals Board:
(i)	Constitution:
	<ul style="list-style-type: none"> a) Program Coordinator of the teaching or parent Department – Chairman; b) two faculty members of the concerned department nominated by the Head of the Department – Members; c) One faculty from outside the Department nominated by the Dean – Member; d) Faculty Advisor(s) of the Class from where the Appeal originates - Member(s)
	Note:
	<ul style="list-style-type: none"> i) There shall be one Departmental Academic Appeals Board for every department. ii) The Chairman may co-opt and or invite more members.
If there is any grievance of the student regarding, any member of the Departmental Academic Appeals Board, the concerned member shall keep himself away from proceedings of the Board pertaining to the grievance of that student	
(ii)	Functions:
	<ul style="list-style-type: none"> a) To receive grievance or complaints in writing from the students regarding anomaly in award of grades due to bias, victimization, erratic evaluation, etc. and redress the complaints on the basis of merit of the case. b) To interact with the concerned course Coordinator and the student separately before taking the decision. c) The decision of the Departmental Academic Appeals Board will be based on simple majority. d) The recommendations of the Departmental Academic Appeals Board shall be communicated to the Dean for further appropriate action, if required.
13.0 Faculty Advisor(s):	
The Faculty Advisor(s) will be appointed by the Program Coordinator of the concerned department, who will be assigned a specific group of students of the department, and will be valid throughout their duration of study.	
Functions:	
	<ul style="list-style-type: none"> (a) To help the students in planning their courses and related activities during their study period. (b) To monitor, guide, advice and counsel the students on all academic matters.
14.0 Hostels	
The University shall make suitable provision for residence of the students of the University. There shall be separate Hostel for Girls students. The admission to the Hostels shall be made by a committee constituted by the Vice-Chancellor. The Hostels shall be supervised by Rector or Warden appointed by the Vice-Chancellor. There shall be separate Rector or Warden for the each Hostel. There shall be a committee constituted by the Vice-Chancellor to oversee the discipline among the residents of the Hostels. The committee shall prepare the rules for proper maintenance and smooth functioning of the Hostels.	

By the order of Governor of Bihar,
Satish Chandra Jha, *Special Secretry*.

The 1st March 2019

No. 15/M 1-112/2014/563---Under the provisions of section 30 of Bihar Private Universities Act 2013 the State Government has been pleased to approve the following first statute for Gopal Narayan Singh University, Jamuhar, Sasaram established vide State Government notification no1066 dated 15.06.2018.

CHAPTER – 1: PRELIMINARY

Short Title and Commencement

These Statutes may be called the First Statutes of the **GOPAL NARAYAN SINGH UNIVERSITY**.

These Statutes shall come into the force from the date of publication of the Statutes in the official Gazette of Government of Bihar.

Definitions

In these statutes, unless the context otherwise requires:

“Act” means, The Bihar Private Universities Act, 2013;

“Board of Management” means, the Board of Management constituted under section 23 of the Act;

“Campus” means, the area of University within which it is established;

“Department” is a part of Institute running one or more courses in a University;

“Distance Education” means, education imparted by combination of any two or more means of communication, viz. broadcasting, telecasting, web casting, correspondence courses, seminars, contact programs and any other such methodology;

“Employee” means, any person appointed by the University and includes teachers, officers and other employees of the University;

“Fee” means, monetary collection made by the University or its colleges, institutions or study centers, as the case may be, from the students by whatever name it may be called;

“Government” or the “State Government” means, the Government of Bihar;

“Governing Body” means, the Governing Body constituted under section 22 of the Act;

“Higher Education” means, study of a curriculum or course for the pursuit of knowledge beyond 10+2 level;

“Hostel” means, a place of residence for the students of the University or its colleges, institutions or study centers, established/maintained or recognized to be as such by the University;

“Notification” means a notification published in the *Official Gazette*;

“*Official Gazette*” means, the *Bihar Government Gazette*;

“Prescribed” means, prescribed by statutes or ordinances or regulations, as the case may be, under this Act;

“Regulating Body” means, a body established by the Central Government for laying down norms and conditions for ensuring academic standards of higher education, such as University Grants Commission, All India Council of Technical Education, National Council of Teacher Education, Medical Council of India, Pharmacy Council of India, National Council of Assessment and Accreditation, Indian Council of Agriculture Research, Council of Scientific and Indian Research etc., and includes the Government;

“Rules” means the rules made under this Act;

“Institute” is combination of various departments run in the University wherein these departments are specialized in one particular area or faculty or subjects;

“Section” means a section of this Act;

“Sponsoring Body” means **DEO MANGAL MEMORIAL TRUST**;

“State” means, State of Bihar;

“Statutes”, “Ordinances” and “Regulations” means respectively, the statutes, ordinances and regulations of the University;

“Student” means, a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction instituted by the University, including research degree;

“Study Center” means a center established and maintained or recognized by the University for the purpose of advising, counseling or for rendering any other assistance required by the students in the context of education, distance education and online education;

“Teacher” means, a Professor, Associate Professor, Assistant Professor or any other person required to impart education or to guide research or to render guidance in any form to the students for pursuing a course of study of the University, who is so designated under this Act;

“University” means, **GOPAL NARAYAN SINGH UNIVERSITY** established and incorporated under section 6 of the Bihar Private Universities Act, 2013.

CHAPTER – 2: OFFICERS OF THE UNIVERSITY

2.0 Officers of University

The following shall be the officers of the University namely:

- (1) The Visitor;
- (2) The Chancellor;
- (3) The Vice-Chancellor;
- (4) The Deans of Faculties;
- (5) The Registrar;
- (6) The Controller of Examinations;
- (7) The Chief Finance and Accounts Officer;
- (8) The Dean of Students’ Welfare;
- (9) The Chief Proctor

2.1 The Visitor

2.1.1 Appointment of the Visitor

An academician of eminence or a person having long standing experience in administration or social work of recognition may be Visitor of the university. The visitor shall be appointed by the Sponsoring Body for a term of three years.

2.1.2 Powers and Duties of the Visitor

The Visitor shall, when present, preside at the convocation of the University for conferring degrees and diplomas. The Visitor shall have the following powers, namely:

- (1) to call for any paper or information relating to the affairs of the University;
- (2) on the basis of the information received by the Visitor, if he is satisfied that any order, proceeding, or decision taken by any authority of the University is not in conformity with the provisions of this Act or Statutes, Ordinances, Regulations and rules made there under, he may issue such directions as he may deem fit in the interest of the University and the directions so issued shall be complied with by the University.

2.1.3 Removal of the Visitor

The Visitor may be removed from his office by the sponsoring body, if it is satisfied that the incumbent,-

- (1) Becomes insane and stands so declared by a competent court;
- (2) Has been convicted by a court for any offence involving moral turpitude;
- (3) Becomes an un-discharged insolvent and stands so declared by a competent court;
- (4) Become physically unfit and incapable of discharging the functions or duties of the office due to protracted illness or physical disability; or
- (5) Has willfully omitted or refused to carry out the provisions of this Act or has committed breach of any of the terms and conditions of the service contract or any other conditions laid down by the statutes, or has abused the powers vested in him or if the continuance of the Visitor in the office has become detrimental to the interests of the University:

Provided that the Visitor shall be given a reasonable opportunity to show-cause by the sponsoring body before taking recourse to action under clauses (4) and (5) above in this Statute for his removal from the said office.

2.2 The Chancellor

2.2.1 Appointment of the Chancellor

The Chancellor shall be a person having long standing experience in administration or social work of recognition. He shall be appointed by the sponsoring body for a period of three years with the approval of the Visitor. He shall be eligible for re-appointment for one or more term of three years with the approval of the Visitor. The Chancellor shall be the head of the University. The Chancellor shall preside at the meetings of the Governing Body and shall, when the Visitor is not present, preside at the convocation of the University for conferring degrees, diplomas or other academic distinctions.

2.2.2 Powers and Duties of the Chancellor

- (1) The Chancellor shall have the following powers, namely:
 - (i) To call for any information or record;
 - (ii) To appoint the Vice-Chancellor;
 - (iii) To remove the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of sub-section (7) of section 17 of the Act;
- (2) The Chancellor may call any information or records from any officers or authority of the University, relating to any affair of the University as he may think necessary and the Vice-Chancellor shall furnish the same. It shall be lawful for the Chancellor, after perusal of such information or records, to give, in the interest of the University, any directive to the Vice-Chancellor, or take any action against any one as he deems fit and the Vice-Chancellor shall comply with such directives.
- (3) The Chancellor shall have the right to conduct either, *suomoto* or on a representation received by him, an inspection of an Institute, hostel, office, or any other establishment or part of the University and of the examination centers himself or can direct any person or authority to do so. He can order an inquiry to be made in respect of any of these establishments. He can also order an inquiry to be made in respect of any matter connected with the administration and finances of the University.
- (4) The Chancellor shall communicate to the Vice-Chancellor, the result of such an inspection or inquiry together with his views and advice with regard to the action to be taken thereon. On receipt of the communication made by the Chancellor, the

- Vice-Chancellor shall communicate forthwith to the Authority concerned, the result of the inspection or inquiry and the views of the Chancellor and the advice tendered by him regarding action to be taken thereon. The Authority concerned shall take action on the advice given by the Chancellor within a reasonable time.
- (5) The Vice-Chancellor shall, along with his opinion, communicate to the Chancellor the action proposed to be taken by the concerned authority.
 - (6) Where the Authority concerned does not take action to the satisfaction of the Chancellor within the time limit, if any, fixed by the Chancellor, the Chancellor may, after considering any explanation furnished or representation made by the Authority concerned, issue such directions as he may think fit and the Vice-Chancellor or the Authority concerned shall be bound to comply with such directions.
 - (7) Without prejudice to the foregoing provisions, the Chancellor may by an order in writing annul, suspend or modify any resolution, order or proceeding of any of the officers or authorities of the University not in conformity with the Act, the Statutes or the Ordinances or not in the interest of the University:
 Provided that, before making any such order, he shall call upon the Officer or the Authority, as the case may be, of the University to show cause why such an order should not be made and if any cause is shown within the time limit fixed by the Chancellor the same shall be considered.
 - (8) Every proposal for the conferment of an Honorary Degree as recommended by the Committee appointed for the purpose by the Governing Body shall be subject to confirmation by the Chancellor.
 - (9) In case of resignation or termination of the Vice-Chancellor, the Chancellor shall nominate the Senior Director or Dean as Officiating Vice-Chancellor due to temporary absence of the regular incumbent.
 - (10) In case of an emergency like illness, absence or death of the Chancellor, in his absence, the Vice-Chancellor shall perform the duties of the Chancellor till the Chancellor reassumes his office or a new Chancellor is appointed as the case may be. However, such a period will normally not exceed six months.
 - (11) The Chancellor shall appoint the Vice-Chancellor as per the procedure laid down in the Statutes.
 - (12) The Chancellor shall be the appointing and disciplinary authority for the following officers of the university, namely:
 The Vice-Chancellor;
 The Deans of Faculties;
 The Registrar;
 The Controller of Examinations;
 The Chief Finance and Accounts Officer;
 - (13) The Chancellor may in writing under his signature, to the Sponsoring Body, resign from his office by giving a notice of three months. The Sponsoring Body may accept his resignation.

2.2.3 Removal of the Chancellor

The Chancellor may be removed from his office by the sponsoring body on the recommendation of the Visitor, if it is satisfied that the incumbent, has become insane and stands so declared by a competent court; or has been convicted by a court for any offence involving moral turpitude; or has become an un-discharged insolvent and stands so declared by a competent court; or has become physically

unfit and incapable of discharging the functions or duties of the office due to protracted illness or physical disability; or willfully omitted or refused to carry out the provisions of this Act or has committed breach of any of the terms and conditions of the service contract or any other conditions laid down by the Statutes, or has abused the powers vested in him or if the continuance of the Chancellor in the office has become detrimental to the interests of the University: Provided that, the Chancellor shall be given a reasonable opportunity to show-cause by the sponsoring body before taking recourse to action for his removal from the said office.

2.3 Vice-Chancellor

2.3.1 Appointment, Terms and Conditions of the Vice-Chancellor

- (1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor from a panel of three persons recommended by the Governing Body and shall, subject to the provisions contained in sub-section (1) of Section 17 of the Act, hold office for a term of three years:

Provided that, after expiry of the term of three years, a person shall be eligible for re-appointment for another term of three years.

Provided further that a Vice-Chancellor shall continue to hold the office even after expiry of his term till new Vice-Chancellor joins. However, in any case this period shall not exceed one year after re-appointment.

- (2) There shall be a five member search committee constituted by the Chancellor for appointment of Vice-Chancellor.
 - (i) Chancellor shall be the Chairman of the search committee
 - (ii) A nominee of the Sponsoring body nominated by the Chairman.
 - (iii) One person nominated by Governing Body
 - (iv) An eminent educationist nominated by the Sponsoring body.
 - (v) Two educationist who are not connected to the University.
- (3) The Search Committee shall recommend a panel of not more than five names in alphabetical order to the Governing Body in a sealed envelope for appointment to the post of Vice-Chancellor within such period as the Chancellor may stipulate while appointing the Search Committee.
- (4) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor from the panel of three persons recommended by the Governing Body. The Chancellor may call all the members from the panel for discussion and appoint one of them as Vice Chancellor.
- (5) In case the Search Committee fails to make a unanimous recommendation, each member of the Committee shall submit a panel of not more than five names to the Governing Body and the Governing Body shall recommend a panel of three persons to the Chancellor for appointment of the Vice-Chancellor.
- (6) Non Submission of the panel by any member of the Search Committee shall not invalidate the appointment of the Vice-Chancellor.
- (7) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office and shall be eligible for reappointment for one more term of three years.

Provided that, the Vice-Chancellor shall continue to hold his office after the expiry of his term till new Vice-Chancellor joins for a period not exceeding one year, in the aggregate.

- (8) The eligibility and criteria for the post of Vice-Chancellor shall be as may be prescribed by the rules and regulations issued by the University Grants Commission from time to time.
- (9) The Vice-Chancellor may by writing addressed to the Chancellor, resign from his office by giving a notice of three months.
- (10) If the vacancy occurs in the office of the Vice-Chancellor because of leave, illness, suspension pending departmental enquiry, resignation, termination or otherwise; the Chancellor may appoint Pro-Vice-Chancellor or in his absence, a suitable person to act as the Vice-Chancellor for a period not exceeding six months, in the aggregate.

2.3.2 Powers and Duties of Vice-Chancellor

- (1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University responsible for the development of the University and shall have the powers of superintendence and control over the affairs of the University and shall execute the decisions of various authorities of the University.
- (2) The Vice-Chancellor shall observe that the Statutes, Ordinances and Regulations, of the University, State Government, Regulating bodies and University Grants Commission are strictly followed and complied with.
- (3) The Vice-Chancellor shall have the power to convene the meetings of any of the authorities, bodies and committees as and when he considers it necessary so to do.
- (4) The Vice-Chancellor shall have the power to constitute committees which he deems necessary for the performance of the duty assigned to him by or under the Act.
- (5) The Vice-Chancellor shall oversee and monitor officers and staff; the working, performance and administration of the departments; institutions of specialized studies, laboratories, library, museums, hostels and institutes maintained by the University.
- (6) The Vice-Chancellor may call for reports from the University Institutes, hostels, or any other department imparting education or working under or supervision of the University in respect of any of the activities, as he may deem it necessary for the proper functioning of the University.
- (7) The Vice-Chancellor shall supervise and control the residence, conduct and discipline of the students of the University. He shall also oversee the general welfare of the students of the University.
- (8) The Vice-Chancellor shall, with the approval of the Board of Management, enter into, vary, carry out or cancel contracts on behalf of the University in exercise of the performance of the powers and duties assigned to him by or under the Act.
- (9) The Vice-Chancellor shall have power to call for any documents and information from any of the institute of the University in respect of any matter connected with teaching, examination, research, finance or any matter affecting the discipline or efficiency of teaching in the institutes, as he thinks fit and necessary.
- (10) In absence of the Chancellor, the Vice-Chancellor shall preside over the meetings of Governing Body and convocation of the University.
- (11) The Vice-Chancellor may defer implementation of a decision taken or a resolution passed by any authority, body or committee of the university if, in

his opinion the same is not consistent with the provisions of the Act, Statutes, Ordinances or Regulations or that such decision or resolution is not in the interest of the university and refer it back to the authority, body or committee concerned for reconsideration within fifteen days from the date of its decision or resolution. In case the authority, body or committee refuses to revise such decision or resolution wholly or partly or fails to take any decision within fifteen days then such matter shall be referred to the Chancellor and his decision thereon shall be final.

- (12) If there are reasonable grounds for the Vice-Chancellor to believe that there is an emergency which requires immediate action to be taken, he shall take such action, as he thinks necessary, and shall at the earliest opportunity, report in writing the grounds for his belief that there was an emergency, and the action taken by him, to such authority or body as would, in the ordinary course, have dealt with the matter.

In the event of a difference arising between the Vice-Chancellor and the authority or body whether there was in fact an emergency, or on the action taken (where such action does not affect any person in the services of the University), or on both, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final:

Provided that, where any such action taken by the Vice-Chancellor affects any person in the service of the university, such person shall be entitled to prefer, within one months from the date on which he receives notice of such action, an appeal to the Board of Management and the Board of Management may confirm or modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

- (13) Where any matter is required to be regulated by the Statutes, Ordinances and Regulations, but no Statutes, Ordinances or Regulations are made in that behalf the Vice-Chancellor may, for the time being, regulate matter by issuing such directions as he thinks necessary, and shall, at the earliest opportunity thereafter, place them before the Governing Body or other authority or body concerned for approval. He may, at the same time, place before such authority or body for consideration the draft of the Statutes, Ordinances and Regulations, as the case may be, required to be made in that behalf.
- (14) As the Chairman of the authorities or bodies or committees of the University, the Vice-Chancellor shall have the power to suspend a member from the meeting of the authority, body or committee for persisting to obstruct or stall the proceedings or for indulging in behavior unbecoming of a member, and shall report the matter accordingly, to the Chancellor.
- (15) The Vice-Chancellor shall place before the Governing Body a report of the work of the university periodically as provided under the Ordinances.
- (16) The Vice-Chancellor shall be disciplinary authority for teachers and Class I (Group A) officers of the University.
- (17) The emoluments and other terms and conditions of service of Vice-Chancellor shall be such as may be prescribed by the University.

2.3.3 Removal of the Vice-Chancellor

- (i) The Vice-Chancellor may be removed from his office by the sponsoring body on the recommendation of the Chancellor, if it is satisfied that the incumbent, -has become insane and stands so declared by a competent court;

- (ii) Has been convicted by a court for any offence involving moral turpitude;
- (iii) Has become an un-discharged insolvent and stands so declared by a competent court;
- (iv) Has been physically unfit and incapable of discharging functions due to protracted illness or physical disability;
- (v) has willfully omitted or refused to carry out the provisions of this Act or has committed breach of any of the terms and conditions of the service contract or any other conditions, or has abused the powers vested in him or if the continuance of the Vice-Chancellor in the office is detrimental to the interests of the university:

Provided that, the Vice-Chancellor shall be given a reasonable opportunity to show cause by the Chancellor before taking recourse for his removal.

Provided further that, the Chancellor may, at any time before making such order, place the Vice-Chancellor under suspension, pending enquiry.

2.4 Dean of Faculties

2.4.1 Appointment, Terms and Conditions of the Dean

- (1) The Dean of the Faculty shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of duly constituted Selection Committee consisting of the following:
 - (i) The Vice-Chancellor – Chairman;
 - (ii) A nominee of the Governing Body appointed by the Chancellor – Member;
 - (iii) Registrar – Member Secretary.
- (2) The Dean of the faculty shall be appointed from amongst the Professor in the institute of subjects under the faculty:

Provided that where there is no Professor in the institute, the Vice-Chancellor shall appoint, for time being, a teacher in the faculty as Dean.
- (3) The Dean shall be appointed for a period of three years and shall not be eligible for consecutive or subsequent terms unless there is no other Professor eligible or suitable for the appointment as Dean.
- (4) The Dean shall be the Chief Executive and Academic Officer of the faculty and shall supervise and control over the affairs of the institute and will take decision on the recommendation of the various heads of the Institute or Departments. He will be accountable to the Vice-Chancellor.
- (5) The emoluments and other terms and conditions of service of the Dean shall be such as may be prescribed by the University.
- (6) The Deans shall work under the control, direction and supervision of the Vice-Chancellor.

2.4.2 Powers and Duties of the Dean of Faculties

- (1) He shall preside over the meetings of departments under the institute and shall see that the various decisions taken at these meeting are implemented and submit its report to the Vice-Chancellor;
- (2) He shall be responsible for the academic development and application of quality benchmarks for the various academic programs, maintenance of standards of teaching and research and training of teachers within his faculty;

- (3) The Dean shall also exercise the following powers and perform following duties:
- (i) Facilitate the creation of a learner-centric environment conducive for quality education and faculty maturation to adopt the required knowledge and technology for participatory teaching and learning process;
 - (ii) Arrange for feedback responses from the students, the teachers, the non-teaching staff, the parents and the other stakeholders on quality-related institutional processes;
 - (iii) Organize of inter and intra institutional workshops, seminars on quality related themes and promotion of quality circles;
 - (iv) Arrange for document of the various programs/activities of higher education, leading to quality improvement;
 - (v) Coordinate the quality-related activities, including adoption and dissemination of good practices; development and maintenance of institutional database through management information system for the purpose of maintaining /enhancing the quality;
 - (vi) Develop quality culture in higher education;
 - (vii) Planning and implementation of academic programs such as orientation courses, seminars, in service and other training programs organized by University for academic competence of the faculty members;
 - (viii) Make proposals to the Board of Management through Academic Council for the institution of fellowships, travelling fellowships, scholarships, medals and prizes and making regulations for their award;
 - (ix) Recommend to the Board of Management through the Academic Council proposals for the conduct of inter-faculty and area or regional studies, common facilities, such as instrumentation centers, knowledge resource centers, Science & Technology Parks, entrepreneurship development and industry incubation centre, IPR centre, workshops, hobby centers, museums, etc.;
 - (x) Control, regulate and coordinate research activities to maintain standards of teaching and research in the University Departments;
 - (xi) Make recommendations to the Academic Council for conduct of post-graduate courses in University Departments;
 - (xii) Recommend to the Academic Council the course structure for undergraduate, post-graduate, M. Phil., pre-Ph.D., and Ph. D. courses;
 - (xiii) Exercise such other powers and perform such other duties as directed by the Vice-Chancellor;
 - (xiv) Co-Ordinate and supervise the procedure of admission of students made by the various University Teaching Departments or Institutes;
 - (xv) Make arrangements for classes including, evening classes, diploma courses, etc.;
 - (xvi) Get the academic calendars prepared;
 - (xvii) Prepare proposals of fellowship and other distinctions;
 - (xviii) Co-Ordinate with other Deans in respect of matters of inter-faculty;
 - (xix) Consider and decide upon the grievance of students regarding enrollment, eligibility and migration.

2.5 Registrar

2.5.1 Appointment, Terms and Conditions of the Registrar

- (1) The Registrar shall be a whole-time salaried officer of the University and shall be appointed by the Chairperson of the sponsoring body on the recommendation of a Selection Committee, for tenure of three years, which may be renewed for similar term by the Chairperson of the sponsoring body.
- (2) Selection Committee for Appointment of Registrar shall consist of the following:
 1. The Vice-Chancellor, *ex-officio* Chairman;
 2. One person nominated by the Sponsoring Body from amongst its members;
 3. One person, nominated by the Governing Body from amongst its members;
 4. Two experts having special knowledge in the field related to the post who are not connected with the University, nominated by the Vice-Chancellor.
- (3) The qualifications and experience for appointment of the Registrar shall be such as may be prescribed by the University Grants Commission and approved by the Government.
- (4) The emoluments and other terms and conditions of service of the Registrar shall be such as may be prescribed by the University.
- (5) When the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is, by reason of illness, absence or otherwise, unable to perform the duties of his office, the Vice-Chancellor may appoint a suitable person to officiate as the Registrar until the Registrar resumes duties.
- (6) The Registrar may by writing under his signature addressed to the Chancellor, resign from his office by giving notice of three months.
- (7) The Registrar shall work under control, direction and supervision of the Vice-Chancellor.

2.5.2 Power and Duties of Registrar

- (1) The Registrar shall be member Secretary of the Governing Body, the Academic Council, the Board of Management and Grievance Redressal Committee. He shall place before these authorities all such information as may be necessary for the transaction of the business. He shall also be the Member Secretary of Selection Committee for the appointment of the teachers of the University. However, he shall not be entitled to vote.
- (2) The Registrar shall be the chief administrative officer of the University. Subject to the decision of the authorities of the University, he shall have the power to enter into agreements, contracts, sign documents and authenticate records on behalf of the University.
- (3) The Registrar shall be the disciplinary authority for non-teaching staff of group B, C and D (class II, III and IV) of the University:
 Provided that the employee may prefer and appeal to the Vice-Chancellor against the order of the Registrar imposing any of the penalties within a period of thirty days from the date order.
- (4) The Registrar in his work shall be assisted by a number of other officers including Deputy and Assistant Registrars, if required. They shall work under the control, direction and superintendence of the Registrar.
- (5) To represent the University in suits or proceedings by or against the University, the Registrar shall sign powers of attorney and verify the pleadings.

- (6) The Registrar shall make available such papers and documents and other information as the Chancellor or the Vice-Chancellor may require.
- (7) It shall be the duty of the Registrar -
 - (i) To be custodian of the records, the common seal and such other property of the University as the Board of Management may commit to his charge;
 - (ii) To issue all notices convening meetings of the Governing Body, Board of Management, Academic Council or any other committee appointed by the authority of the University or Vice-Chancellor;
 - (iii) To prepare the agenda of the meetings of the authorities of the University and circulate the same to the concerned members;
 - (iv) Shall receive complaints and suggestions regarding improvement of administration;
 - (v) Shall perform such other duties as may be directed by the Vice-Chancellor.

2.5.3 Removal of the Registrar

The Registrar may be removed from his office if the Chancellor is satisfied that the incumbent,-

- (1) Has become insane and stands so declared by a competent court;
- (2) Has been convicted by a court for any offence involving moral turpitude;
- (3) Has become an un-discharged insolvent and stands so declared by a competent court;
- (4) Has been physically unfit and incapable of discharging functions due to protracted illness or physical disability;
- (5) Has willfully omitted or refused to carry out the provisions of this Act or has committed breach of any of the terms and conditions of the service contract or any other conditions, or has abused the powers vested in him or if the continuance of the Registrar in the office is detrimental to the interests of the university:

Provided that the Registrar shall be given a reasonable opportunity to show cause by the Chancellor before taking recourse for his removal.

Provided further that the Chancellor may, at any time before making such order, place the Registrar under suspension, pending enquiry.

2.6 Controller of Examinations

2.6.1 Appointment, Terms and Conditions of the Controller of Examination

- (1) The Controller of Examination shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of a duly constituted Selection Committee consisting of the following:
 - (i) The Vice-Chancellor, *ex-officio* Chairman;
 - (ii) One nominee of the Sponsoring Body from amongst its members;
 - (iii) One persons, nominated by the Governing Body from amongst its members;
 - (iv) Twoexperts, nominated by the Vice-Chancellor, having special knowledge in the field related to the post, who are not connected with the University.
- (2) The Controller of Examination shall be a whole-time salaried officer of the University appointed for a tenure of three years, which may be renewed for a similar terms by the Chancellor.

- (3) The qualifications and experience for appointment of the Controller of Examinations shall be such as may be prescribed by the University Grants Commission and approved by the Government.
- (4) The emoluments and other terms and conditions of service of the Controller of Examinations shall be such as may be prescribed by the University:
Provided that the term of appointment of the Controller of Examinations shall not be continued beyond the date of his attaining the age of sixty five years.
Provided further that notwithstanding his attaining the age of sixty five years, he shall continue in the office until his successor is appointed and enters upon his office, or for a period of one year, whichever is earlier.
- (5) When the office of the Controller of Examination is vacant or when the Controller of Examination is, by reason of illness, absence or otherwise, unable to perform the duties of his office, the Vice-Chancellor may appoint a suitable person to officiate as the Controller of Examinations.
- (6) The Controller of Examinations may by writing under his signature addressed to the Chancellor, resign from his office by giving a notice of three months.

2.6.2 Powers and Duties of Controller of Examinations

- (1) The Controller of Examinations shall be the principal Officer in-charge to conduct examinations and declaration of their results and making it available on internet and intranet for the students. He shall discharge his functions under the supervision, direction and control of the Vice-Chancellor.
- (2) The Controller of Examinations shall be the Member Secretary of the Board of Examination and may be invited a meeting of the Board of Management or Governing Body, as and when required. But he shall have no right to vote.
- (3) The Controller of Examinations shall be responsible for making all the arrangements necessary for holding and conducting examinations and tests properly and timely declaration of their results.
- (4) Subject to the prior approval of the Vice-Chancellor, the Controller of Examinations shall perform the following duties and responsibilities, namely:
 - I To prepare and announce in advance the calendar of examinations which shall be placed before the Board of Examinations;
 - II To appoint Examiners and Moderators from the list approved by the Board of Examinations after approval of the vice chancellor.
 - III To arrange for printing of question papers and blank answer books and their safe custody;
 - IV To arrange to get performance of the candidates at the examinations properly assessed and to process results;
 - V To postpone or cancel examinations in part or in whole, in the event of malpractices or if the circumstances so warrant and take disciplinary action or initiate any civil or criminal proceedings, against any person or group of persons or department or institute alleged to have committed malpractices;
 - VI To implement the recommendations of the Board of Examinations pertaining to conducting and supervising the online examinations pattern for the courses wherever feasible;

- VII To take disciplinary action where necessary against the candidates, paper – setters, examiners, moderators, or any other persons connected with examinations and found guilty of malpractices in relation to the examinations;
- VIII To make appraisal from time to time of the conduct of the University Examinations, wherever required to ensure efficiency and confidentiality;
- (ix) To submit report regarding conduct of examinations to the Board of Examination and Academic Council.
- (5) The Controller of Examination shall advise the Vice-Chancellor in all matter related to the Examinations and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be assigned to him, from time to time, by the Board of Examinations, the Vice-Chancellor and the Chancellor.
- (6) When the office of the Controller of Examinations is vacant or when the Controller of Examinations is, by reason of illness, absence or otherwise, unable to perform his duties the Vice-Chancellor may appoint a suitable person to officiate as the Controller of Examinations until the Controller of Examinations resumes duties.

2.6.3 Removal of the Controller of Examinations

The Controller of Examination may be removed from his office if the Chancellor is satisfied that the incumbent,-

- (1) Has become insane and stands so declared by a competent court;
- (2) Has been convicted by a court for any offence involving moral turpitude;
- (3) Has become an un-discharged insolvent and stands so declared by a competent court;
- (4) Has been physically unfit and incapable of discharging functions due to protracted illness or physical disability;
- (5) Has willfully omitted or refused to carry out the provisions of this Act or has committed breach of any of the terms and conditions of the service contract or any other conditions, or has abused the powers vested in him or if the continuance of the Controller of Examinations in the office is detrimental to the interests of the university or miserably failed in his duties in supervising and controlling examinations which in result has seriously affected credibility and reputation of the University:

Provided that the Controller of Examinations shall be given a reasonable opportunity to show cause by the Chancellor before taking recourse for his removal.

Provided further that the Chancellor may, at any time before making such order, place the Controller of Examination under suspension, pending enquiry.

2.7 Chief Finance and Accounts Officer

2.7.1 Appointment of Chief Finance and Accounts Officer

- (1) The Chief Finance and Accounts Officer shall be a whole time salaried officer of the University and shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of Selection Committee for a tenure of three years, which may be renewed for a similar term by the Chancellor.
- (2) Selection Committee for appointment of Chief Finance and Accounts Officer shall consist of the following:

- (1) The Vice-Chancellor, *ex-officio* Chairman;
 - (2) One persons of the Sponsoring Body from amongst its members;
 - (3) One persons, nominated by the Governing Body from amongst its members;
 - (4) Two experts having special knowledge in the field related to the post who are not connected with the University, nominated by the Vice-Chancellor.
- (3) The Chief Finance and Accounts Officer shall be an officer of the University responsible for handling finance, accounts and audit of the University.
- (4) The qualifications of Chief Finance and Accounts Officer shall be from Indian Audit and Account Service, or from any other accounts service of government of India/Bihar or Subordinate Audit Service Examination (SASE) passed official with 8 year experience as senior Audit officer/Audit Officer and Sr.Account Officer/Accounts Officer from Indian Audit and Account Department Or any other post graduate degree in Finance or equivalent.
- (5) The emoluments and other terms and conditions of service of Chief Finance and Accounts Officer shall be such as may be prescribed by the University:
 Provided that the term of appointment of Chief Finance and Accounts Officer shall not be continued beyond the date of his attaining age prescribed by the University.
 Provided further that, notwithstanding his attaining the age prescribed by the University, he shall continue in the office until his successor is appointed and enters upon his office for a period prescribed by the University.
- (6) When the office of the Chief Finance and Accounts Officer is vacant or when the Chief Finance and Accounts Officer is, by reason of illness, absence or otherwise, unable to perform the duties of his office, the Vice-Chancellor, after taking consent of Chancellor may appoint a suitable person to officiate as the Chief Finance and Accounts Officer until the Chief Finance and Accounts Officer resumes duties.
- (7) The Chief Finance and Accounts Officer may by writing under his signature addressed to the Chancellor, resign from his office by giving a notice of three months.
- (8) The Chief Finance and Accounts Officer shall work under the direction, supervision and control of the Vice-Chancellor.
- (9) The Chief Finance and Accounts Officer shall be member secretary of the Finance Committee and the Central Purchase Committee and may be invited to a meeting of the Board of Management or the Governing Body, as and when required, but he shall have no right to vote.
- (10) The Chief Finance and Accounts Officer shall be responsible for presenting the annual budget, statement of accounts, balance sheet and audit report of statutory auditor to the Finance and Accounts Committee, the Board of Management and the Governing Body.

2.7.2 Powers and Duties of Chief Finance and Accounts Officer

The duties of the Chief Finance and Accounts Officer shall be to-

- (I) Exercise general supervision over the funds of the university, and shall advise the Vice-Chancellor as regards the finances of the university;
- (II) Hold and manage the funds, property and investments, including trust and endowed property, for furthering any of the objects of the university;

- (III) Ensure that the limits fixed by the university for recurring and non-recurring expenditure for a year are not exceeded, and that all allocations are expended for the purposes for which they are granted or allotted; keep watch on the state of the cash and bank balance and of investments;
- (IV) Keep watch on the progress of collection of revenue and advise the Vice-Chancellor on the methods to be employed for collection;
- (V) Collect the income, disburse the payments and maintain the accounts of the University;
- (VI) Arrange for the conduct of continuous internal audit of the accounts of the University and shall pre-audit such bills as may be required in accordance with any standing orders in that behalf;
- (VII) Perform such other functions in respect of financial matters as may be assigned to him by the Governing Body or the Board of Management or the Vice-Chancellor;
- (VIII) Ensure that the registers of buildings, land, equipment and machinery are maintained up-to-date and that the stock taking of equipments and other consumable materials in all offices, University Departments, workshops and stores of the university is conducted regularly;
- (IX) Probe into any unauthorized expenditure and other financial irregularities and suggest to the competent authority, disciplinary action against persons at fault;
- (X) Propose to the Vice-Chancellor that explanation be called for unauthorized expenditure or other financial irregularities from any university teacher;
- (XI) Propose to the Registrar that explanation be called from any non-teaching staff for unauthorized expenditure or irregularities in any particular case, and recommend disciplinary action against the persons at fault;
- (XII) Call from any office, centre, laboratory, departments or institutes of the university, for any information and returns that he thinks necessary for the proper discharge of his financial responsibilities;
- (XIII) Have the accounts of the University audited regularly;
- (XIV) Submit unaudited quarterly report to the Chancellor, Governing Body and Board of Management;
- (XV) Exercise such other powers, perform such other duties, and discharge such other financial functions as are assigned to him by the Vice-Chancellor.

2.7.3 Removal of the Chief Finance and Accounts Officer

The Chief Finance and Accounts Officer may be removed from his office if the Chancellor is satisfied that the incumbent,-

- (1) Has become insane and stands so declared by a competent court;
- (2) Has been convicted by a court for any offence involving moral turpitude;
- (3) Has become an un-discharged insolvent and stands so declared by a competent court;
- (4) Has been physically unfit and incapable of discharging functions due to protracted illness or physical disability;
- (5) Has willfully omitted or refused to carry out the provisions of this Act or has committed breach of any of the terms and conditions of the service contract or any other conditions, or has abused the powers vested in him or if the continuance of the Chief Finance and Accounts Officer in the office is detrimental to the interests of the university:

Provided that the Chief Finance and Accounts Officer shall be given a reasonable opportunity to show cause by the Chancellor before taking recourse for his removal.

- (6) If at any time upon representation made or otherwise and after making such enquiry as may be deemed necessary, the situation so warrants that the continuance of Chief Finance and Accounts Officer is not in the interest of University, the Vice-Chancellor may request the Chancellor, in writing stating the reasons therein for the removal of Chief Finance and Accounts Officer:

Provided that before taking any action the Chief Finance and Accounts Officer shall be given an opportunity of being heard.

Provided further that the Chancellor may, at any time before making such order, place the Chief Finance and Accounts Officer under suspension, pending enquiry.

2.8 Dean Students' Welfare

- (1) The Dean Students' Welfare shall be nominated by the Vice-Chancellor from amongst the teachers of the University, who possess teaching experience of not less than ten years and who is not below the rank of Associate Professor.
- (2) The Dean shall hold office for a term of three years and shall be eligible for re-appointment.
- (3) The teacher who is appointed as Dean of Students' Welfare shall perform his duties as Dean in addition to his own duties as teacher.
- (4) The Dean of Students' Welfare shall be assisted by a team of teachers, nominated by the Vice-Chancellor, who shall perform their duties in addition to their normal duties of teacher. Amongst the nominated teachers at least one shall be a lady teacher of the university who shall look after the welfare of the girl's students.
- (5) It shall be the duty of the Dean of Students' Welfare to assist the students in matters requiring help and guidance and, in particular, to help and advice students and prospective students in
 - (i) Obtaining admission to the University and its courses;
 - (ii) The choice of suitable courses and hobbies;
 - (iii) Finding living accommodation;
 - (iv) Making boarding arrangements;
 - (v) Obtaining medical advice and assistance;
 - (vi) Securing scholarships, stipends, part-time employment and other pecuniary assistance through earn and learn scheme;
 - (vii) Obtaining travel facilities for holidays and educational excursions;
 - (viii) Securing facilities for further studies abroad and; conducting themselves in proper pursuit of academic studies as to maintain the traditions of the University.
- (6) The Dean of Students' Welfare may communicate with the guardian of students in respect of any matter requiring his assistance when necessary.
- (7) The Vice-Chancellor may on the recommendation of the Dean of Students' Welfare take disciplinary action against students.
- (8) The Dean of Students' Welfare may be paid honorarium out of the funds of the University as the Vice-Chancellor may decide with prior approval of the Board of Management.
- (9) The Dean of Students' Welfare shall work under the direction, supervision and control of the Vice-Chancellor.

2.9 The Chief Proctor

- (1) The Chief Proctor shall be nominated by the Vice-Chancellor from amongst the teachers of the University, as are not below the rank of Associate Professor.
- (2) The tenure of Chief Proctor shall be two year.
Provided that if and any time Vice-Chancellor things it proper on administrative grounds he may send the chief proctor to his original post and appoint another person as Chief Proctor for the unexpired period of his term.
- (3) The teacher who is appointed as Chief Proctor shall perform his duties as chief proctor in addition to his own duties as teacher.
- (4) There shall be a Proctorial Board. Vice-Chancellor shall nominate at least one faculty member as Proctor from each faculty.
- (5) In case of the Vacancy of the Chief Proctor/Proctor caused due to resignation or illness or any other reason his duties shall be discharged by the person appointed for the purpose by the Vice-Chancellor.
- (6) It shall be the duty of the Chief Proctor to maintain the discipline amongst the teachers, employee and students of the university.
- (7) The Chief Proctor may communicate with the guardian of students in respect of any matter requiring his assistance when necessary.
- (8) The Vice-Chancellor may on the recommendation of the Chief Proctor take disciplinary action against Teachers, Employee and students.
- (9) The Chief Proctor may be paid honorarium out of the funds of the University as the Vice-Chancellor may decide with prior approval of the Board of Management.
- (10) The Chief Proctor shall work under the direction, supervision and control of the Vice-Chancellor.

CHAPTER – 3: AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

3.0 Authorities of the University

The following shall be the authorities of the University:

1. The Governing Body;
2. The Board of Management;
3. The Academic Council;
4. The Faculties;
5. The Boards of Studies;
6. The Planning and Monitoring Board;
7. The Board of Inter-disciplinary Studies
8. The Board of University Teaching and Research
9. The University Board of Sports and Physical Culture
10. The Directorate of Skill Development

3.1 Governing Body

- (1) The Governing Body shall be the principal executive authority to lay policy of the University.
- (2) The Governing Body shall consist of the following members, namely:
 1. The Chancellor; Chairperson;
 2. The Vice-Chancellor;
 3. Five persons, nominated by the sponsoring body out of whom two shall be eminent educationists;

4. One expert of management or information technology from outside the University, nominated by the Chancellor;
 5. One expert of finance nominated by the Chancellor;
 6. The Registrar shall be member secretary, but shall not have right to vote.
- (3) The term of the members, other than ex-officio, of the Governing Body shall be three years.

3.1.1 Meetings of Governing Body

The Governing Body shall meet at least three times in a calendar year. A meeting of the Governing Body shall be convened by giving advance notice of fifteen days:

Provided that any emergency meeting of the Governing Body may be held without any notice if the quorum is complete either by the presence or the members at the venue of the meeting or the members joined through Video conference.

A copy of the proceedings of each meeting shall be furnished to the Chancellor of the University as soon as possible after the meeting.

The quorum for the meeting of the Governing Body shall be four.

Each member of the above Governing Body including its Chairman shall have one vote and decisions at the meeting of the Governing Body shall be taken by simple majority of members present. In case of a tie, the Chairman shall have a casting vote.

Any business, which may be necessary to be urgently transacted by the Governing Body, may be carried out by circulating appropriate resolution thereon among its members and any resolution so circulated and approved by a simple majority shall be as effective and binding as if such resolution had been passed at the meeting of the Board.

If a member, other than the Vice Chancellor does not attend three consecutive meetings of the Governing Body without leave of absence granted by the Chairman, he ceases to be a member of the Governing Body.

3.1.2 Powers and Duties of Governing Body

The Governing Body shall be the supreme authority of the University and principal executive body of the University and shall have the following powers, namely:

1. To provide general superintendence and directions and to control functioning of the University by using all such powers as are provided by the Act and Statutes and Ordinances of the University;
2. To review the decisions of other authorities of the University in case they are not in conformity with the provisions of this Act or the Rules or regulations made there under;
3. To approve the budgets and annual report of the University;
4. To lay down the policies to be followed by the University;
5. To make the amend or repeal statutes;
6. To recommend to the sponsoring body about the voluntary liquidation of the University if a situation arises when smooth functioning of the University does not remain possible, in spite of all efforts;
7. To carry out such activities as may be necessary or feasible in furtherance of the objects of the University;
8. To provide instruction, training and research in such branches of learning as the University may think fit and to make provision for research and advancement and dissemination of knowledge particularly in professional and innovative courses;

9. To establish and maintain departments of the University;
10. To develop innovative patterns of teaching for the courses run in the University;
11. To make provisions for curricular, co-curricular, extracurricular activities for the students and employees;
12. To create academic, administrative support staff and other necessary posts;
13. To hold examination and to grant and confer degrees, titles, diplomas, certificates and other academic distinctions on persons who have pursued and passed an approved course of study of the University, subject to such conditions as the University may determine and to withdraw any such degrees, titles, diplomas, certificates and other academic distinction on good and sufficient cause;
14. To recognize academic credits acquired through examinations, periods of study (whether in full or in part) of other universities, institutions or other places of higher learning as equivalent to examinations and periods of study in the University and to withdraw such recognition at any time;
15. To consider the recommendation of the Board of Management, and thereupon confer honorary degrees or other academic distinctions;
16. To hold and manage endowments and arrange other properties and funds of the University and to raise loans required for the purposes of the University by seeking approval of the sponsoring bodies;
17. To fix fees and to demand and receive such fees and other charges as may be prescribed;
18. To institute and maintain hostels and to recognize places of residence for the students of the University and to withdraw such recognition accorded to any such places of residence;
19. To supervise and control the places of residence for the students of the University and to regulate the discipline of the students of the University and to make arrangements for promoting their health;
20. To create academic, technical, administrative, ministerial and other posts and to make appointments thereto;
21. To regulate and enforce discipline amongst the employees of the University and to take such disciplinary measures as may be necessary;
22. To institute professorship, associate professorship, assistant professorship and any other teaching academic or research posts as may be deemed necessary by the University and to appoint duly qualified persons as professors, associate professors, assistant professors, research assistant or otherwise as teachers and researchers of the University;
23. To provide for printing, reproduction and publication of research and other works and to organize exhibitions;
24. To organize and conduct refreshers courses, orientation courses, workshops, seminars, conferences and other programs for teachers, evaluators and other academic staff;
25. To determine standards of admission to the University with the approval of the Academic Council;
26. To co-operate with other organizations in matters of education, training and research;

27. To co-operate with institutions with higher learning in any part of the world having objects wholly or partly similar to those of the University, through faculty exchange program and scholars and generally in such manner as may be conducive for furtherance of the objects of the University;
28. To regulate expenditure and to manage the funds of the University;
29. To establish and maintain within the premises of the University or elsewhere such classrooms, study halls, etc., as the University may consider necessary, and to adequately furnish the same;
30. To receive grants, subscriptions, donations and gifts for the purpose of the University consistent with the objects for which the University is established;
31. To establish, the centers, sub-centers, or study centers in the State of Bihar for promotion of distance education and online education;
32. To purchase, take on lease or accept as gift or otherwise any land or building or works which may be necessary or convenient for the purpose of the University and on such terms and conditions as it may think fit and proper, to construct buildings or alter and maintain any such buildings or works.

The Governing Body may by a resolution, delegate to the Chancellor, Vice-Chancellor, Pro-Vice-Chancellor or any other officer, such of its powers as it may deem fit, subject to the condition that the action taken by the Chancellor or the Vice-Chancellor or the Pro-Vice-Chancellor, if any or the officer concerned in the exercise of the powers so delegated shall be reported at the next meeting of the Governing Body.

3.2 Board of Management

3.2.1 Members of Board of Management

- (1) The Board of Management shall consist of the following members, namely:-
 1. the Vice-Chancellor;- Chairperson;
 2. two members of the Governing Body, nominated by the sponsoring body;
 3. three persons, who are not the members of the Governing Body, nominated by the sponsoring body;
 4. three persons from amongst the teachers, nominated by the sponsoring body;
 5. two teachers, nominated by the Vice-Chancellor;
 6. the Registrar shall be Member Secretary but shall not have right to vote;
- (2) The Board of Management shall meet at least once in every two months.
- (3) The quorum for meetings of the Board of Management shall be five.
- (4) The term of the nominated members of the Board of Management shall be of three years. No member shall be nominated for more than two consecutive terms.

3.2.2 Powers and Functions of Board of Management

- (1) The Board of Management shall exercise the following powers and perform the following duties, namely:
 - a. To accept financial accounts and audit report;
 - b. To present the budget estimate as received from the finance committee with its own modification, if any, to the Governing Body for its consideration and approval;
 - c. To perform any other function that may be assigned by the Governing Body and the Chancellor;

- d. To make, amend or repeal Statutes for approval of Governing Body;
 - e. To recommend to the Governing Body to make, amend or repeal Ordinances recommended by Academic Council;
 - f. To consider and approve the report of the selection committee and forward the same to the Governing Body for information;
 - g. To monitor, control and administer the general activities of the University;
 - h. To frame fee structure for various courses and decide criterion for exemption in fee to needy and meritorious students;
 - i. To create teaching and other academic posts including Chairs;
 - j. To appoint such Professors, Associate Professors, Assistant Professors and other academic staff including Chairs, as may be necessary, on the recommendation of the Selection Committee constituted for the purpose and to fill up temporary vacancies therein;
 - k. To promote inter-disciplinary research through joint appointments of teaching staff in various Institutes and Departments;
 - l. To create administrative, ministerial and other necessary posts and to define their duties and conditions of their service and to make appointments thereto in the manner prescribed by the ordinances;
 - m. To regulate and enforce discipline among employees in accordance with the Human Resource Manual;
 - n. To manage and regulate the finances, accounts, investments, property, business and all other administrative affairs of the University and for that purpose to appoint such agencies or persons as it may think fit;
 - o. To fix limits on the total recurring and the total non-recurring expenditure for a year on the recommendation of the Finance Committee;
 - p. To provide buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;
 - q. To enter into vary, carry out and cancel, agreements and contracts on behalf of the University;
 - r. To appoint examiners and moderators and, if necessary, to remove them, and to fix their emoluments and travelling and other allowances;
 - s. To select a common seal for the University and provide for the use of such seal;
 - t. To make such special arrangements as may be necessary for the residence of women students;
 - U. To institute and decide the policy for award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;
 - V. To provide for the appointment of Visiting Professors, Emeritus Professors, Consultants and Scholars and determine the terms and conditions of such appointments;
 - W. To enter into partnership with industry and non-government organization for the advancement of knowledge and establish a corpus fund out of the profits of such partnership; and
 - X. To exercise such other powers and duties which are not assigned to any other authorities of the University.
- (2) The Board of Management shall have the power of management and administration of the revenues and property of the University and all other matters otherwise not provided for, anywhere in these Statutes.

- (3) The Board of Management shall, from time to time, prepare its fees structure and forward it for approval of the committee constituted by the State Government for the purpose.
- (4) The Board of Management shall not charge any fees, by whatever name called, other than that for which it is prescribed.
- (5) Fees for duplicate mark-sheets, Re-evaluation of answer papers, issuance of degree certificates and for such other matters shall be charged from the students, as prescribed by the Board of Management.
- (6) The Board of Management shall take action in regard to the number, qualifications and emoluments of teachers after considering the advice of Academic Council and the Institutes concerned.
- (7) The Board of Management shall give due consideration to every resolution of the Governing Body and take such action thereon as necessary and report to the Governing Body, the action taken.

3.3 Academic Council

3.3.1 Composition and Responsibilities of Academic Council

The Academic Council shall be responsible for laying down the academic policies in regard to maintenance and improvement of standards of teaching, research, extension and collaboration programs in academic matters and evaluation of workload of the teachers.

The Academic Council of the University shall consist of the following persons, namely:

1. The Vice-Chancellor, Chairperson;
 2. The Pro-Vice-Chancellor, if any;
 3. The Deans of faculties;
 4. The Director/The Principal/HODs of all department;
 5. The Controller of Examinations shall be the permanent invitee and he shall have right to speak on matters pertaining to examinations but shall not have right to vote;
 6. The Registrar shall be the Member Secretary of the Academic Council but shall not have the right to vote.
- (3) The Academic Council shall meet as often as may be necessary but not less than twice a year.
 - (4) One-third members of the total members of the Academic Council shall constitute the quorum for the meeting of the Academic Council.
 - (5) Any business which may be necessary for the Academic Council to transact except such as may be placed before its meeting, may be circulated along with the proposed resolution among all its members. The resolution so circulated and approved by a simple majority of total members shall be effective and binding as if such resolution has been passed in the meeting of the Academic Council.

3.3.2 Powers and Duties of Academic Council

- (1) The Academic Council shall be the principal academic authority of the University and shall be responsible for regulating and maintaining the standards of teaching, research and examination in the University.
- (2) The Academic Council shall exercise the following powers and duties, namely:
 - I. To recommend to the Board of Management regarding institution of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;

- II. To recommend to the Board of Management to make, amend or repeal Ordinances on issues related to the students and academic matters;
- III. To allocate subjects to the faculties;
- IV. To make proposals for the establishment of institutes of the University, departments of higher learning, research and specialized studies, academic services units, libraries, laboratories and museums in the university;
- V. To consider and make recommendations regarding new proposals for creation of professorships, professorship of chair, associate professorships, assistant professorship, Head of Research and Publication and non-vocational academic staff required by the university;
- VI. To promote research within the University, acquire reports on such research from time to time;
- VII. To make proposal to the Board of Management for the institution of fellowships, travelling fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes and make regulations for their award;
- VIII. To prescribe qualifications and norms for appointment of papers setter, examiners, moderators and others, concerned with the conduct of examinations;
- IX. To appoint committees to review periodically the utility and practicability of the existing courses of study and the desirability or necessity of reviewing or modifying them in the light of new knowledge or changing societal requirements;
- X. To make proposal for the conduct of interfaculty and area or regional studies, common facilities, such as instrumentation centres, workshops, hobby centers, museums, etc.;
- XI. To prescribe norms for recognition of teacher of the University as M.Phil./Ph.D. Guide;
- XII. To make proposals to the Board of Management to prescribe fees and other charges;
- XIII. To exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed on it by or under the Act, the Statutes, Ordinances, and Regulations;
- XIV. To exercise general supervision over the academic policies of the University and to give directions regarding methods of instruction, co-ordination of teaching among the Institutes, evaluation of research and improvement of academic standards;
- XV. To bring about and promote inter-Institute co-ordination and to establish or appoint such committees or boards as may deem necessary for the purpose;
- XVI. To consider matters of general academic interest either on its own initiative, or on a reference by a Institute or the Board of Management, and to take appropriate action thereon;
- XVII. To recognize diploma and degrees of other Universities including foreign Universities and to determine equivalence of such diplomas and degrees in consonance of existing norms;
- XVIII. To assess the viability of collaboration of academic programme with other universities including foreign university and make such recommendation of tie-up to the Governing Body.

- (3) Academic Council shall, generally, advise the university on all academic matters and submits to the Board of Management the details of the academic calendar and feasibility reports on academic programs.

3.5 Faculties

- (1) The faculties shall be principal academic coordinating authority of the university. The faculty shall co-ordinate studies and research in the subjects included in the faculty and also studies and research in multi-faculties.
- (2) The faculty shall consist of the following members:
 - (i) The Dean of the faculty – Chairman;
 - (ii) The Chairman of each Board of Studies for the subjects comprised in the faculty;
 - (iii) Two members of each Board of Studies to be nominated by the Vice-Chancellor.

3.6 Board of Studies

3.6.1 Members of Board of Studies

There shall be a Board of Studies for every subject or group of subjects, as may be decided by the Dean of the Institute concerned and approved by the Vice-Chancellor.

The Board of Studies shall consist of:

- (i) Head of the Department - Chairman. If the Board has been constituted for more than one subject, the Vice Chancellor shall nominate the Chairman;
- (ii) Three teachers each from the category of Professors, Associate Professors and Assistant Professors of the subjects nominated by the Vice-Chancellor;
- (iii) Two Experts having experience in Industry or Academia or Research Organizations etc. nominated by the Vice-Chancellor.

The term of the nominated members shall be three years.

3.6.2 Powers and functions of the Board of Studies

- (1) The Board of Studies shall have the following powers and duties, namely:
 - I. To prepare syllabus for various courses of studies and design online courses of studies, wherever feasible;
 - II. To recommend books, including textbooks, supplementary reading, reference books and other material for such courses of Graduate and Postgraduate studies;
 - III. To prepare requirements in respect of teaching of the subject at various courses including teachers' qualifications and infrastructure, such as library, laboratory, equipments, consumables etc. for consideration of Academic Council and Board of Management;
 - IV. To make recommendations to the Academic Council regarding the norms of recognition of postgraduate teachers;
 - V. To make recommendations to the Academic Council regarding the conduct of courses in University;
 - VI. To recommend names of suitable persons for inclusion in the panels for appointment of paper-setters, examiners and moderators at the University examinations in the subject;
 - VII. To suggest organization of orientation and refresher courses in the subject.
- (2) Every decision of the Board of Studies shall be placed before the Dean of concerned Faculty for approval and make further recommendations to the Academic Council, wherever necessary.

- (3) The Board shall meet as often as required but not less than four times in an academic year.

The Chairman of the Board of Studies shall preside over the meetings of the Board. In the absence of the Chairman, the person elected by members present from amongst themselves shall preside at that meeting.

The chairman shall convene the meeting of the Board by issuing a notice of minimum eight days and shall inform the Registrar. However, for the urgent and special meetings no notice will be required to be given provided all the members are present either in person or through video conference.

The quorum for the meeting of Board of Studies shall be four.

Any items, questions, matters or proposals on the agenda shall be decided by majority votes of members present. In case of equality of votes, the Chairman shall have a casting vote.

A copy of minutes of meetings will be forwarded to Registrar of University under the signatures of the Chairman and the Dean of faculty.

3.7 Planning and Monitoring Board

3.7.1 Members of Planning and Monitoring Board

- (1) The Planning and Monitoring Board shall be the principal Planning Body of the University and shall be responsible for monitoring of the development programs.
- (2) The Planning and Monitoring Board shall consist of:
1. The Vice-Chancellor-Chairman;
 2. All Deans of Faculties;
 3. The Chief Finance and Accounts Officer;
 4. The University Engineer or Project Engineer of the University;
 5. Three persons to be nominated by the Chancellor, one of them should be from Board of Management, one should be renowned Architect and one should be eminent Educationist;
 6. Registrar – Member-Secretary.

3.7.2 Powers and functions of Planning and Monitoring Board

- (1) The Planning and Monitoring Board shall have the following powers and duties, namely:
- (i) To ensure compliance of the norms laid down by the University Grants Commission and other statutory bodies in respect of infrastructure and supportive teaching aids;
 - (ii) To assess the need and plan the utilization of the infrastructure as per the guidelines of the University Grants Commission and other statutory bodies;
 - (iii) To devise ways and means to augment the financial resources of University;
 - (iv) To plan the development of University campus and ensure its implementation;
 - (v) To consider any other matter which may be referred to it by the Governing Body or Board of Management.
- (2) The Planning and Monitoring Board shall meet at least twice in a year.
- (3) The minutes of the meeting of Planning and Monitoring Board shall be drawn by the Registrar and signed by the Vice-Chancellor.

- (4) The Planning and Monitoring Board may advise the Governing Body and the Academic Council on any matter, which it may consider necessary for the fulfillment of the objectives of the University.
- (5) The quorum for meetings of the Planning and Monitoring Board shall be five.

3.8 Board of Inter-disciplinary Studies

3.8.1 Members of Board of Inter-disciplinary Studies

- (1) There shall be a Board of Inter-disciplinary Studies.
- (2) The Board of Inter-disciplinary Studies shall consist of the following members:
 1. The Chairmen of the Boards of Studies in the respective subjects including Chairmen Ad- hoc Boards, if any;
 2. The Heads of the Departments in the respective subjects;
 3. Two members from each of the Boards of Studies concerned, nominated by the Academic Council, One of the members so nominated shall be a person with specialized knowledge, co-opted on the Board of Studies, and the other shall be a teacher in the subject concerned;
 4. One Professor, in the subject or discipline, to be nominated by the Vice-Chancellor;
 5. One expert in the subject or discipline co-opted by the Board of Inter-disciplinary Studies.
- (3) The Chairman of the Board of Inter-disciplinary studies shall be elected from amongst the members, at its first meeting.

3.8.2 Powers and functions of Board of Inter-disciplinary Studies

- (1) The Board of Inter disciplinary studies shall have the following powers and duties, namely:
 1. To recommend to the Academic Council, the projects relating to the Inter-disciplinary subjects;
 2. To make proposals to the Academic Council, for the conduct of inter- disciplinary studies and area or regional studies;
 3. To recommend to the Academic Council, upon a reference to it by the Governing Body or Board of Management or by the Academic Council or by the Faculty concerned or otherwise, the course of inter-disciplinary studies;
 4. To recommend to the Academic Council and to the Board of Management and the Governing Body, projects relating to the inter-disciplinary subjects, which may be useful for industrial, technological, agricultural, social, economic or such other development;
 5. Such other matters as may be referred to it by other authorities of the University.
- (2) The board of Inter-disciplinary Studies shall meet at least once in a year. The meeting of the Board shall be convened by the Chairman with ten clear days' notice.
- (3) The minutes of the meeting of Inter-disciplinary Studies shall be prepared by the Chairman and submitted to the Academic Council for its consideration.

3.9 Board of University Teaching and Research

3.9.1 Members of Board of University Teaching and Research

There shall be a Board of University Teaching and Research. It shall consist of the following members:

- | | |
|---|------------|
| 1. The Vice-Chancellor, ex-officio | -Chairman; |
| 2. The Deans of the Faculties; | -Member |
| 3. The Head of each Department | -Member |
| 4. One Professor other than the Head of the | |

Department from each faculty to be
nominated by the Vice-Chancellor;

-Member

5. The Registrar -

-Member Secretary.

3.9.2 Powers and functions of Board of University Teaching and Research

- (1) Subject to the provisions of the Act, Statutes, Ordinances and Regulations, the Boards of University Teaching and Research shall have the power to control, regulate and co-ordinate post-graduate teaching, training and research in the University and to promote industry-university interactions.
- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the Board shall exercise the following powers and perform the following functions:
 - (i) To recommend to the Academic Council the conduct of post-graduate instruction, teaching, training and research in the University;
 - (ii) To recommend to the Academic Council the requirements regarding post-graduate teachers in the respective subjects including the adjunct teachers;
 - (iii) To recognize research guides and post-graduate teachers;
 - (iv) To determine the programs of instruction, teaching, training and research, and decide the nature and extent of the work that the recognized teachers may be called upon to undertake;
 - (v) To exercise the powers of the University in so far as they are related to co-operation and collaboration with other universities, institutions, authorities or organizations; for research and advisory services and for such academic matters; to enter into appropriate agreements with other universities, institutions, organizations, authorities to conduct certain courses as the situation may demand; and further, to undertake development programs in higher education, research consultancy based projects and training programs for outside agencies by charging fees so as to generate resources;
 - (vi) To approve subjects for research for various degrees and other requirements for research degrees.
- (3) The Board of University Teaching and Research shall ordinarily meet twice in a year with eight clear days' notice to the members.
- (4) The Vice-Chancellor or in his absence, a Dean of the Faculty nominated for the meeting by the Vice-Chancellor shall preside over the meeting of the Board. The Chairman shall have a right to vote and in the case of equality of votes, a casting vote.

3.10 University Board of Sports and Physical Culture

3.10.1 Objectives and Members of University Board of Sports and Physical Culture

- (1) The objectives of the Board are as under:
 - (i) To promote, organize and control the sports, games and physical culture in the University area;
 - (ii) To promote, inculcate and enhance the spirit of true sportsmanship;
 - (iii) To undertake and conduct University and Inter-University and other types of sports and tournaments.

- (2) The University Board of Sports and Physical Culture shall consist of the following:
1. the Vice-Chancellor - Chairman;
 2. two experts in the field of sports and physical culture to be nominated by Vice-Chancellor;
 3. two members of the Board of Management nominated by the Board of Management ;
 4. the Director of Students' Welfare;
 5. the Director of Sports and Physical Culture - Member Secretary.
- (3) The term of office of the nominated members shall be three years.
- (4) (i) The Board of Sports and Physical Culture shall meet at least twice in a year.
(ii) The meeting of the Board shall be convened by the Vice-Chancellor.
(iii) Seven days' notice shall ordinarily be required to be given for the meetings of the Board.
(iv) Three members shall constitute the quorum.
(v) The minutes of the meeting of the Board of Sports and Physical Culture shall be drawn by the Director of Sports and Physical Culture and submitted to the Board of Management for perusal.

3.10.2 Powers and functions of University Board of Sports and Physical Culture

The powers and functions of the Board shall be:

1. To frame rules for the control and conduct of various sports, games and tournaments;
 2. To prepare and present to the Board of Management the Annual Budget of the Board of Sports and Physical Culture;
 3. To allot funds to various Councils, Committees and subcommittees;
 4. To make arrangements for the purchase of materials and other necessary equipment, to secure grounds and other appendages in order to ensure the proper discharge of its functions and for the fulfillment of its objectives;
 5. To organize coaching camps with a view to raising the standards of sports in general and increase the caliber of sportsmen in particular;
 6. To decide in which games, sports and tournaments the University should participate in the Inter University tournaments;
 7. To select players for the various teams for participation in Inter-University tournament;
 8. To appoint whenever necessary committees and sub-committees;
 9. To organize and conduct University and Inter-University sports and meets;
 10. To incur expenditure within the frame-work of the sanctioned budget;
 11. To institute and receive Prizes and Trophies and to receive donations for the purpose;
 12. To settle disputes referred to it;
 13. To nominate team Managers, Selection Committees and Coaches for the teams which are participating in the Inter-University tournaments;
 14. To collect such amount, as decided by the Board of Management, from time to time, per year per student on the roll of University;
 15. To advise the university in all matters pertaining to sports and physical culture: Provided that an appeal shall lie with the Board of Management in respect of the interpretation of the rules, regulations and byelaws in respect of Sports.
- The decision of the Board of Management shall be final.

Generally, the Board of Sports and Physical Culture shall do everything except to enter into financial commitments, for the promotion of sports and physical culture.

3.11 Directorate of Skill Development

- (1) There shall be a Directorate of Skill Development in the university. The Directorate shall have the status of a university department and shall be headed by the Director.
- (2) The Director shall be appointed by the Board of Management on the recommendation of a selection committee s constituted for selection and appointment of a university teacher.
- (3) The Director shall be appointed for tenure of five years and shall be eligible for reappointment of another term following due process of selection:
Provided that the term of appointment of the Director shall not be continued beyond the date of his attaining the age of sixty-five years.
- (4) The emoluments and other terms and conditions of service of the Director shall be such as may be prescribed by the Human Resource Manual of the University.
- (5) The Director shall work under the control, direction and superintendence of the Vice-Chancellor.
- (6) The Directorate of skill development shall be mainly concerned with the development of various types of skills of students in collaboration with various National and State Level Skill development agencies and shall have the following objectives:
 - To build an alternative structure to increase capacity, to fulfill the demand of skilled craftsmen and to train the persons in the field of informal and unorganized sector through Skill Development mode;
 - to establish Skill Development Centres in Faculties of the University for training of the Youth;
 - To prepare the work plans to meet sector specific skill sets;
 - To establish centres for Skill Development, Employment and Entrepreneurship guidance;
 - To provide extensive training support & assistance for service seeker;
 - To provide congenial environment for progressive advancement of Technical Education and Vocational Training in the University;
 - To prepare proposals for upgrading skills through regular courses as per the needs of the industry and to provide technology courses in the emerging areas;
 - To upgrade professional and managerial skills;
 - To motivate students to achieve world class skills;
 - To provide opportunity of skill development and technical education to all sections of the society;
 - To ensure a transparent and fast system in the management of Technical Education and Vocational Training through the use of information and communication technology.
- (7) The Directorate of Skill Development shall consist of:
 - (i) The Director, Directorate of Skill Development Department;
 - (ii) Trainers of the Skill Development department;
 - (iii) Non-vocational academic staff.

- (8) There shall be an Advisory Board for the Directorate of Skill Development to plan and oversee the skill development programs and shall consist of the following:
 - (i) Vice-Chancellor – Chairman;
 - (ii) Two Deans associated with the activities of Skill Development, nominated by the Vice-Chancellor;
 - (iii) Two Skill Development Experts nominated by the Vice-Chancellor;
 - (iv) Three Faculty members associated with Skill Development in the University nominated by Academic Council;
 - (v) The Registrar;
 - (vi) Director, Directorate of Skill Development - Member Secretary.
- (9) The Director shall have the following powers and duties:
 - (i) The Director shall execute the decisions of the Advisory Board of the Directorate of Skill Development, the Academic Council and the Board of Management, as the case may be.
 - (ii) The Director, shall conduct the Skill Development Examinations of the various courses offered by the Directorate and shall finalize the results.
 - (iii) the Director shall recommend to the Vice-Chancellor to place any matter of academic importance related to the courses offered under Skill Development Scheme before the concerned Board of Studies or Faculties or the Academic Council, as the case may be.
 - (iv) The Director shall exercise such powers and perform such duties assigned to him by the Board of Management or the Vice-Chancellor from time to time.

3.12 General Provisions

- (1) The term of every authority, except as otherwise provided in these statutes, shall be of three years from the date of its first meeting.
- (2) Notwithstanding anything contained in these Statutes, where a person, elected, nominated, appointed or co-opted as an officer of university or a member of any of the authorities or bodies of the university by virtue of his being eligible to be so elected, nominated, appointed or co-opted as such an officer or a member under any of the categories of the officers or members under the relevant statutes in relation to such office, authority or body, shall cease to be such an officer of the university or a member of such an authority or a body as soon as he ceases to belong to such category and shall be deemed to have vacated his office as such officer or member.
- (3) A meeting of an authority or body or committee shall be convened on the date determined by the Chairman by a notice issued by its Secretary.
- (4) Except as otherwise provided, the quorum for a meeting of authority, body or committee shall ordinarily be one-third of the number of the sitting members. If there is no quorum, the meeting shall be adjourned by the Chairman to a specific time on the same day, or on a later date and no quorum shall be necessary for such adjourned meeting.
- (5) Where no provision is made by or under the Statutes for a Chancellor or Chairman to preside over a meeting of any authority or body of the university or the Chairman is absent and no provision is made for any other

- person to preside, the members present shall elect a person from amongst themselves to preside at the meeting.
- (6) Save as otherwise provided all items, questions, matters or proposals on the agenda shall be decided by a majority of votes of members present. The Chairman shall have a casting vote. The Secretary, if not a member, shall have right to participate in the deliberations but shall not have the right to vote.
 - (7) The officer who is designated to be the permanent invitee of the authority shall be entitled to receive the notice of its meetings and take part in the deliberations relating to the topics with which he is concerned, but shall not have right to vote.
 - (8) The decisions, or proceedings or any action of any authority or body or committee shall not be deemed to be invalid merely on the ground of any vacancies or defect in constitution, or disqualification of member or any irregularity in procedure etc.
 - (9) A person shall be disqualified for being a member of any of the authorities or bodies of the University, if he or she-
 - I. is of unsound mind and stands so declared by a competent court;
 - II. is an undercharged insolvent;
 - III. has been convicted of any offence involving moral turpitude;
 - IV. is conducting or engaging himself in private coaching classes; or
 - V. has been punished for indulging in or promoting unfair practice in the conduct of any examination, in any form, anywhere;
 - (10) Any member other than an ex-officio member of any authority may resign by a letter addressed to the Registrar of the University and the resignation shall take effect as soon as it is accepted by the concerned person or authority, as the case may be.
 - (11) Casual vacancies, if any, among the members (other than ex-officio members) of any authority or any other committee of the University, shall be filled as soon as it may be convenient, by the person or the authority or committee who had appointed or co-opted such member whose place has become vacant and the person appointed or co-opted to a casual vacancy shall be member of such authority or committee for the residual term for which the person in whose place he has been nominated would have held it, had the vacancy not occurred.

CHAPTER – 4: Recruitment & Assessment Cell

4.1 Committee for Selection and Appointment of University Teachers and Librarian

- (1) There shall be a selection committee for making recommendations to the Chancellor for the appointment of teachers and librarian of the University.
- (2) The selection committee shall consist of:
 - (a) The Vice-Chancellor, Chairman;
 - (b) The Dean of the faculty concerned;
 - (c) The Head of the University department concerned; and
 - (d) Two subject experts, nominated by the Board of Management from a panel of not less than three persons recommended by the Vice-Chancellor, being persons not connected with the University, who have special knowledge of the subject for which the teacher is to be selected;

The Registrar shall act as Secretary of the Committee.

- (3) (i) Every post of a teacher of the University, to be filled by selection, shall be duly and widely advertised according to a draft approved by the Board of Management.
- (ii) The date of the meeting of every selection committee shall be so fixed as to allow notice thereof being given of at least thirty days to each member and to the candidates, and the particulars of each candidate shall be sent to each member so as to reach him at least seven days before the date of the meeting.
- (iii) The quorum at a meeting of every selection committee shall be four members of whom at least two shall be a person's nominated under sub-clause (1) (ii) (d) above.
- (iv) The selection committee shall interview, adjudge the merits of each candidate in accordance with the qualification advertised, and report to the Chancellor the names, arranged in order of merit of the person or persons if any whom it recommends for appointment.
- (v) The report of the selection committee shall be submitted to the Chancellor or a member of the Governing Body if nominated by the Chancellor. The Chancellor or a member of the Governing Body nominated by the Chancellor, as case may be, shall appoint from amongst the persons so recommended, the number of persons required to fill the posts as advertised:
 Provided that, where the Chancellor or the member of the Governing Body nominated by the Chancellor, as the case may be, proposes to make an appointment otherwise than in accordance with the order of merit arranged by the selection committee, he shall record its reasons in writing:
 Provided further that, where a selection committee recommends to the Chancellor or the member of the Governing Body nominated by the Chancellor, as the case may be, the name of one person only and that person is not acceptable, he shall record its reasons in writing for not accepting the recommendation, and direct the Registrar to advertise the vacancy.

4.2 Filling Temporary Vacancies of University Teachers

- (1) Where an appointment is to be made to a temporary vacancy of a teacher in the University, the appointment shall be made, if the vacancy is for a period of one year or more, on the recommendation of the selection committee constituted for regular selection of University teacher:
 Provided that, if the Vice-Chancellor is satisfied that in the interest of teaching, it is necessary to fill up the vacancy immediately, he may make the appointment of a person duly qualified for the post for a period not exceeding one year on the recommendation of a local selection committee constituted as follows, and shall inform the Board of Management of such appointment.
- (2) The Local Selection Committee shall consist of the following:
1. the Vice-Chancellor, Chairman;
 2. the Dean of the faculty concerned;
 3. the Head of the University department concerned;
 4. one person nominated by the Vice-Chancellor, except that, where the Head of the Department is also the Head of the Institute, the Vice-Chancellor shall nominate two persons instead of one, who have special knowledge of the subject for which the teacher is to be appointed:

Provided further that, before the expiry of six months, the Vice-Chancellor shall take steps to convene a meeting of the selection committee for regular appointment of University teacher.

4.3 Library Committee

- (1) There shall be a library committee for administering, organizing and maintaining the library of the University consisting of:
 - (i) The Vice-Chancellor, Chairman;
 - (ii) Three Deans of faculties, nominated by the Vice-Chancellor;
 - (iii) Three Heads of University Departments, nominated by the Vice-Chancellor;
 - (iv) Two teachers, nominated by the Board of Management;
 - (v) The Registrar; and
 - (vi) The Librarian *ex-officio* Secretary.
- (2) All members of the committee, other than *ex-officio* members, shall hold office for a period of three years.
- (3) The procedure at its meeting shall be such as may be decided by the Library Committee.

4.4 Central Purchase Committee

- (1) There shall be a Central Purchase Committee dealing with all matters pertaining to all purchases in respect of such items where individual cost of each item exceeds Rs. Five Lakh at a time.
- (2) The Central Purchase Committee shall consist of:
 - (i) The Vice-Chancellor, Chairman;
 - (ii) Two members from amongst Board of Management nominated by the Chancellor;
 - (iii) Two Heads of Departments nominated by the Vice-Chancellor;
 - (iv) The Registrar; and
 - (v) The Chief Finance and Accounts Officer – Member Secretary.
- (3) The committee shall meet as and when convened by the Chairman.
- (4) All members of the committee other than *ex-officio* members shall have a term of two years.
- (5) The committee may, if necessary, suggest the names of the Technical experts to scrutinize the proposals of purchases of technical nature.
- (6) The Chief Finance and Accounts Officer shall in consultation with the Vice-Chancellor prepare the agenda for the meeting.
- (7) The quorum for the meeting of the Central Purchase Committee shall be five.
- (8) The notice of ten clear days excluding the day of meeting, shall be given to each member.
- (9) The recommendations of the committee shall be placed before the Board of Management for approval.

4.5 The Finance Committee

- (1) There shall be Finance Committee consisting of the following members:
 1. The Vice-Chancellor – Chairman;
 2. The Registrar;
 3. The Controller of Examinations;
 4. One professor, not being a member of the Board of Management or the Academic Council but in the service of the University for at least five years, nominated by the Chancellor;

5. Two experts in the field of finance, accounts or audit nominated by the Board of Management;
6. The Chief Finance and Accounts Officer - Member Secretary.
- (2) The term of membership of the persons other than ex-officio members shall be three years.
- (3) The Finance Committee shall guide the Chief Finance and Accounts Officer on matters relating to the administration of property and funds of the University. The committee shall, having regard to the income and resources of the University, decide the limits for the total recurring and non-recurring expenditure for the ensuing financial year and may, for any special reasons, revise during the financial year the limits of expenditure approved in the budget. The decision of Finance Committee shall be binding on the Chief Finance and Accounts Officer.
- (4) The financial estimates of the financial year of the University prepared by the Chief Finance and Accounts Officer shall be placed before the Finance Committee for consideration and approval. The finance committee shall with or without modification in the proposed financial estimates forward it to the Board of Management. The Board of Management shall have the power to pass the financial estimates of the University for the financial year.
- (5) The Finance Committee shall meet at least twice in a year.
- (6) The statutory auditor for auditing the accounts of the University for every financial year shall be appointed by the Board of Management.

4.6 The Admission Coordination Board

4.6.1 Admission Coordination Board

- (1) There shall be an Admission Coordination Board to frame rules, regulation for admission and to monitor the admissions procedure.
- (2) The Board shall consist of:
 - (i) The Vice-Chancellor - Chairman
 - (ii) Vice Chairman – (Nominated by the Vice-Chancellor) - Member
 - (iii) All Deans/The Principal, The Heads
 - (iv) The Controller of Examinations
 - (iv) The Registrar/Deputy Registrar(Academic) –Mem.-Sec.

Powers and Functions

- (1). The Main Function of the Board to lay on general admission policy which takes in to consideration, majors to be adopted for reducing pressure on the University System, lay on minimum eligibility of admission to various courses. The Committee will be concerned with formulation of general admission policy and guidelines and recommendation to the academic council:
 - a. Minimum eligibility requirements and principal of weightage and reservation, if permissible, to various courses and fixing the last date of admission.
 - b. Printing and publishing the information bulletin and advertisements concerning admission to the university.
 - c. Annual review of admission made in every academic session and submission the report to the academic council.
 - d. Any matter pertaining to admission referred to it by the academic council and its chairman.

4.7 The Examination Coordination Board

(1) The Examination Coordination Board shall consist of:

- | | |
|--|-------------|
| (i) The Vice-Chancellor | - Chairman, |
| (ii) Vice Chairman – (Nominated by the Vice-Chancellor) | - Member |
| (iii) Directors/Deans/Principals/
HOD of faculties, colleges, departments | -Member |
| (iv) The Controller of Examinations | -Mem. Sec. |

Powers and Functions

(1) The Board will be concerned with laying down a policy and guidelines pertaining to conduct of examinations and the periodical review of examination systems and reforms with a view to ensuring integrity and standards of evaluation of examinees. The boards will make recommendation to the academic council pertaining to:

- Conducting examinations in conformity with the ordinance and fixing of date for holding the exams;
- Maintenance of proper standards of examination on the basis of scrutiny of results;
- Any other matter on examination reforms referred to it by the academic Council or its Chairman.

4.8 Grievance Redressal Committee

(1) There shall be a Grievance Redressal Committee to entertain, adjudicate and redress grievances of the students and the employees of the University.

(2) The Grievance Redressal Committee shall consist of:

- Senior Most Dean - Chairman;
- Two university teachers to be nominated by the Vice-Chancellor out of which one shall be female;
- Chief Finance and Accounts Officer
- One Non-Teaching staff from amongst the non-teaching staff of the University to be nominated by the vice chancellor;
- One member of academic council to be nominated by the Vice-Chancellor;
- Registrar – Member Secretary.

(3) The term of the nominated members shall be three years.

(4) The Grievance Redressal Committee shall deal with the grievances of teachers and other employees regarding the following:

- any dispute, difference, claim or grievance in connection with any matter regarding functioning of the university;
- interpretation of any provision of statutes, ordinance, regulation or decision of the university

Provided that the matter regarding suspension, reduction in rank, removal, dismissal or otherwise termination of employees shall be governed by the Human Resource Manual.

(5) Any employee aggrieved may prefer an application to the Grievance Redressal Committee within thirty days from the date of cause of action.

(6) Every application regarding grievance of any employee shall be decided as expeditiously as possible. The Grievance Committee shall make endeavor to decide upon the grievance within three months after giving reasonable opportunities to both the parties of being heard.

(7) The Grievance Redressal Committee shall decide the procedure to be followed for the disposal of grievance of the employee.

- (8) The decision or direction issued by the Grievance Redressal Committee shall be communicated to both the parties in writing and shall be complied with by the officer of the University.
- (9) Any employee aggrieved by the direction or the order of the may within thirty days from the date of such direction or order prefer an appeal to the court of the University and the decision of the court shall be final and binding.

4.9 The Arbitration

In case of disputes between the employees and the University and between the Students and the University:

- (1) In case of any dispute, difference, claim in connection with any matter related to the university, the same may be referred to a sole arbitrator to be appointed by the Chancellor with concurrence of the other party.
- (2) The Arbitrator shall be a person having knowledge of law or long standing experience in administration, not connected with the University and his decision shall be final and binding on both the parties.
- (3) No person shall have a right to take any matter to a civil court or any other Tribunal without first resorting to arbitration.
- (4) The matter regarding suspension, reduction in rank, removal, dismissal or otherwise termination of employees shall be governed by the Human Resource Manual.

4.10 Appointment, Emoluments & Terms and Conditions of the University Employees

The qualification, experience, procedure of selection and appointment and terms and conditions of service for teaching as well as non-teaching employees, shall be as laid down in the university approved by the Board of Management.

4.11 Annual Report

- (1) The annual report of the University shall be prepared by the Board of Management which shall include among other matters, the steps taken by the University towards the fulfillment of its objects and shall be approved by the Governing Body and copy of the same shall be submitted to the sponsoring body.
- (2) Copies of the annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Visitor and the Government.

4.12 Annual Accounts and Audit Report

- (1) The annual accounts including balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Board of Management and the annual accounts shall be audited at least once in every year by the auditors appointed by the University for this purpose.
- (2) A copy of the annual accounts to get her with the audit report shall be submitted to the Governing Body.
- (3) A copy of the annual accounts and audit report along with the observations of the Governing Body shall be submitted to the sponsoring body.
- (4) Copies of annual accounts and balance sheet prepared under sub section (1) shall also be presented to the Visitor and the State Government. The advice of the Government or the Visitor, if any, arising out of the accounts and audit report of the University shall be placed before the Governing Body. The Governing Body shall issue such directions, as it may deem fit and compliance shall be reported to the Visitor or the Government, as the case may be.

4.13 Convocation

- (1) Convocation for conferring Degrees, Diplomas and Certificates shall be held on the dates to be fixed by the Vice-Chancellor in consultation with the Visitor. At such Convocation, Dean of each Faculty or in his absence, a person, nominated by the Vice-Chancellor, as the case may be, shall present the persons who have sought admission to the respective Degrees, Diplomas, or Certificates.
- (2) In the meeting proceeding to the Convocation, the Academic Council shall recommend the names of Degrees, Diplomas and Certificates to be conferred in the Convocation to the Board of Management.
- (3) The Board of Management shall consider the question of giving assent to confer Degrees, Diplomas and Certificates and to pass the grace at the Convocation upon persons duly qualified, and in accordance with such assent of the Board of Management, the grace shall be passed at the Convocation.
- (4) The Convocation for the award of the Degrees, Diplomas and other Distinction of the University shall normally be held annually.
- (5) The Academic Council shall frame Regulations relating to the format of the Degree, Diploma and Certificates, Citations and other Documents, their text and procedure for holding Convocation.

4.14 Honorary Degree

- (1) The Governing Body may consider and decide upon the conferment of an honorary degree or other academic distinction on any persons without requiring him to undergo any test or examination, on the ground solely that he by reason of his eminent position, attainments and public service, is fit and proper person to receive such degree or other academic distinction and such recommendation shall be deemed to have been duly passed, if supported by a majority of not less than two-thirds of the members present at the meeting of the Governing Body, and not less than one-half of its total membership.
- (2) The Governing Body shall not entertain or consider any proposal in that behalf without the Board of Management having obtained previous approval of the Chancellor.
- (3) Honorary degrees shall be conferred only at convocation, and may be collected in person or in absentia.
- (4) The presentation at the Convocation of person on whom honorary degrees are to be conferred shall be made by the Vice-Chancellor or in his absence, by a member of the Governing Body, nominated by the Chancellor.
- (5) The certificate of an honorary degree shall be signed by the Chancellor.
- (6) The following shall be the degrees to be conferred as Honorary Degrees:
 - (i) Doctor of Literature, D.Litt.;
 - (ii) Doctor of Science, D.Sc.
 - (iii) LL.D.

By the order of Governor of Bihar
Satish Chandra Jha, *Special Secretry*.

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचनाएं

14 मई 2018

सं० 8/आ० (राज० उ०)—2-11/2017-1603—श्री राजकिशोर प्रसाद सिंह, तत्का० निरीक्षक उत्पाद, रोहतास द्वारा जिले में अवैध, शराब के निर्माण तथा चौर्य बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में असफल होने कारण कर्तव्य के प्रति लापरवाही तथा प्रभावी पर्यवेक्षण के अभाव के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं०-4434 दिनांक 29.10.2017 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, को तत्कालिक प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

2. निलंबन अवधि के वेतनादि का भुगतान इनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल से प्रभावित होगा।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, विशेष सचिव।

14 मई 2018

सं० 8/आ० (राज० उ०)—2-10/2017-1604—श्री किशोर कुमार साह, तत्कालीन प्रभारी सहायक आयुक्त उत्पाद, रोहतास द्वारा जिले में अवैध, शराब के निर्माण तथा चौर्य बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में असफल होने कारण कर्तव्य के प्रति लापरवाही तथा प्रभावी पर्यवेक्षण के अभाव के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं०-4435 दिनांक 29.10.2017 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, को तत्कालिक प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

2. निलंबन अवधि के वेतनादि का भुगतान विभागीय कार्यवाही के फलाफल से प्रभावित होगा।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, विशेष सचिव।

14 मई 2018

सं० 8/आ० (राज० उ०)—01-05/2017-1599—सुश्री अपर्णा शिवा, अवर निबंधक, ठाकुरगंज (किशनगंज) के विरुद्ध केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा आयोजित राजपत्रित पदाधिकारियों की प्रथम/द्वितीय 2014 तथा प्रथम/द्वितीय अर्द्धवार्षिक विभागीय परीक्षा 2015 के दौरान कदाचार में लिप्त पाये जाने आदि आरोप में विभागीय संकल्प सं०-2647 दिनांक 20.06.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. विशेष सचिव-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा गै०स०प्रे०सं०-152 दिनांक 12.04.2018 द्वारा अपना जाँच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन में निष्कर्षित किया गया है कि सुश्री अपर्णा शिवा के विरुद्ध लगाये गये आरोप को संलग्न साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट रूप से प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। साक्ष्य के रूप में उपलब्ध करायी गयी उत्तर पुस्तिका पर कक्ष में उपस्थित दोनों वीक्षकों एवं केन्द्राधीक्षक का हस्ताक्षर उपलब्ध है, परन्तु उसपर आरोपित पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं होना आरोपित पदाधिकारी के इस बचाव बयान को कि उक्त प्रतिवेदन उनके परोक्ष में किया गया है, को ही बल प्रदान करता है। साथ ही साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराए गए परीक्षा गार्ड के किसी भी पन्ने पर आरोपित पदाधिकारी का नाम/हस्ताक्षर नहीं है। सभी पन्ने उप सचिव, राजस्व पर्षद द्वारा हस्ताक्षरित हैं, जिसपर किसी वीक्षक का भी हस्ताक्षर नहीं है। साथ ही साक्ष्य की बरामदगी स्थल वह बेंच है, जिसपर सुश्री शिवा के अतिरिक्त दो अन्य परीक्षार्थी बैठकर परीक्षा दे रहे थे। उक्त तथ्य और साक्ष्य भी सुश्री शिवा के इस अभिकथन को कि यह पुस्तक उनके अतिरिक्त किसी अन्य दो परीक्षार्थी की भी हो सकती है, का ही समर्थन करते हैं। अतः आरोप के साथ जो साक्ष्य उपलब्ध कराये गये हैं वे लगाये गये आरोपों को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं।

3. विभागीय कार्यवाही के दौरान केन्द्राधीक्षक एवं वीक्षक को गवाही के लिए उपस्थित होने की सूचना दी गई, परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। राजस्व पर्षद द्वारा दिनांक 26.11.2016 को परीक्षा से निष्कासन के पश्चात दिनांक 14.12.2016 तथा दिनांक 19.01.2017 को आयोजित दो परीक्षाओं में सुश्री शिवा के शामिल होने एवं पर्षद द्वारा उन्हें अंक प्रदान किये जाने के संबंध में कोई भी तथ्य नहीं देते हुए मात्र वीक्षक एवं केन्द्राधीक्षक के प्रतिवेदन के आलोक में अग्रेतर निर्णय लेने का मंतव्य दिया गया है। अतः निष्कासन वाली परीक्षा की तिथि के पश्चात् की तिथियों में आयोजित परीक्षाओं पर सुश्री शिवा का शामिल किया जाना, उक्त परीक्षा के केन्द्राधीक्षक एवं वीक्षकगण की गवाही/सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं होना, उत्तर पुस्तिका पर वीक्षक एवं केन्द्राधीक्षक के प्रतिवेदन के पश्चात् सुश्री शिवा का हस्ताक्षर नहीं होना, प्राप्त परीक्षा गार्ड पर सुश्री शिवा का नाम/हस्ताक्षर नहीं होना तथा एक ही बेंच पर तीन परीक्षार्थी को बैठाकर परीक्षा लिया जाना आदि तथ्यों के आधार पर सुश्री शिवा पर लगाये गये आरोप को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। आरोप की जाँच हेतु दिए गए साक्ष्य आरोप प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अतएव आरोप अप्रमाणित निष्कर्षित किया गया है।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई तथा पाया गया है कि विभागीय पत्रांक-360 दिनांक 30.01.2018, 505 दिनांक 12.02.2018 एवं 877 दिनांक 14.03.2018 द्वारा राजस्व पर्षद से केन्द्राधीक्षक एवं

वीक्षकगण को विभागीय कार्यवाही में सुनवाई की तिथि को गवाही देने हेतु उपस्थित होने का निदेश देने का अनुरोध किया गया। परन्तु किसी भी सुनवाई की तिथि को कोई गवाह उपस्थित नहीं हुए।

5. राजस्व पर्षद द्वारा अपने पत्रांक-633 दिनांक 23.03.2018 द्वारा संसूचित किया गया कि कक्ष के वीक्षक एवं केन्द्राधीक्षक द्वारा समर्पित प्रतिवेदन को आरोप का पर्याप्त प्रमाण मानते हुए अग्रेतर निर्णय लिया जा सकता है।

6. परीक्षा में कदाचार में लिप्त पाये जाने के बावजूद आरोपी पदाधिकारी को अगली परीक्षा में बैठने देने एवं साक्षात्कार में भाग लेने का अवसर दिया जाना यह स्थापित करता है कि बरामद पुस्तिका आरोपी पदाधिकारी की ही थी, संदेहास्पद प्रतीत होता है।

7. अतः पूर्ण विचारोपरान्त संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन एवं अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के फलाफल के आधार पर सुश्री अपर्णा शिवा को आरोप से मुक्त करते हुए उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

8. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
देवकीनन्दन दास, उप-सचिव।

13 जून 2018

सं० 8/आ०(राज० नि०)1-41/2014-1992—श्री धनन्जय कुमार राव, अवर निबंधक, दानापुर सम्प्रति अवर निबंधक के विरुद्ध निबंधन अधिनियम 1908 एवं निबंधन नियमावली 2008 में वर्णित प्रावधानों की अनदेखी कर फर्जी निबंधन को स्वीकार करना, प्रशासनिक क्षमता की कमी एवं दायित्व बोध का अभाव आदि आरोप के लिए आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय संकल्प सं०-5257 दिनांक 16.12.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी। उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री राव को कार्यालय प्रधान के नाते कार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं प्रशासनिक क्षमता की अभाव के लिए दोषी मानते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 14 (V) के तहत विभागीय अधिसूचना सं०- 3572 दिनांक-28.07.2016 द्वारा तीन वार्षिक वेतनवृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

2.. उक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्री राव द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी०डब्लू०जे०सी० नं०-11174/2017 दायर किया गया। उक्त वाद में दिनांक-18.05.2018 को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा निम्ननांकित आदेश पारित किया गया:-

"In view of the aforesaid, the order of punishment dated 28.07.2016 cannot be sustained and is fit to be quashed on the sole ground that the second show cause notice issued to the petitioner herein does not communicate, to the petitioner herein, any reason for disagreeing from the inquiry report submitted by the Inquiry Officer, thus, the second show cause notice dated 04.05.2016 is quashed, having caused prejudice to the petitioner herein and consequently the order of punishment dated 28.07.2016 also stands vitiated and is accordingly set aside.

The law in this regard is well settled by the Hon'ble Apex Court in cases reported in 1998 (7) SCC 84 (Punjab National Bank Vs. Kunj Behari Mishra), 1993(4) SCC 727 (ECIL Vs B. Karunakar) and 2013 (7) SCC 251 (S.P.Malhotra Vs. Punjab National Bank and Ors).

For the reasons mentioned herein above, the present writ petition is allowed and the order of punishment dated 28.07.2016 stands quashed"

3. सी०डब्लू०जे०सी० नं०-11174/2017 में दिनांक 18.05.2018 को माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में श्री राव के विरुद्ध विभागीय अधिसूचना सं० 3572 दिनांक 28.07.2016 द्वारा अधिरोपित दण्डादेश को निरस्त किया जाता है।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, विशेष सचिव।

21 जून 2018

सं० 8/आ० (राज०नि०)-1-04/2018-2075—श्री सरोज कुमार सिन्हा, तत्का० जिला अवर निबंधक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी सम्प्रति निलंबित मुख्यालय-निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार पटना को जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक-45/गो० दिनांक-08.02.2018 द्वारा प्रेषित अनुशासनहीनता, कार्य के प्रति गम्भीर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता का आरोप के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या-655 दिनांक-23.02.2018 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था।

2. जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण से प्राप्त आरोप पर विभागीय पत्रांक-615 दिनांक-22.02.2018 द्वारा श्री सिन्हा से स्पष्टीकरण मांग की गयी। श्री सिन्हा से प्राप्त स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत स्वीकार करते हुए उनके निलंबन आदेश अधिसूचना सं0-655 दिनांक-23.02.2018 को निरस्त किया जाता है।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
देवकीनन्दन दास, उप-सचिव।

14 अगस्त 2018

सं0 8/आ0(राज0उ0)-2-27/2016-2850—श्री संजय कुमार चौधरी, तत्का0 निरीक्षक उत्पाद, गोपालगंज सम्प्रति निरीक्षक उत्पाद रोहतास के विरुद्ध दिनांक 16.08.2016 को गोपालगंज जिला में हुई जहरीली कांड में अवैध शराब का निर्माण एवं चौर्य व्यापार पर प्रतिबंध लगाने में असफल, कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता तथा प्रभावकारी पर्यवेक्षण का अभाव आदि आरोप में विभागीय संकल्प संख्या-355 दिनांक 25.01.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त उत्पाद, पटना-सह-मगध प्रमंडल, पटना द्वारा अपने पत्रांक-60 दिनांक 11.06.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें निष्कर्षित किया गया है कि आरोपित पदाधिकारी का स्पष्टीकरण, समर्पित साक्ष्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी पर लगाया गया आरोप सं0-1,2 एवं 3 प्रमाणित नहीं होता है। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक-2196 दिनांक 29.06.2018 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से द्वितीय बचाव वयान की माँग की गई। आरोपित पदाधिकारी द्वारा दिनांक 17.07.2018 को द्वितीय बचाव वयान समर्पित किया गया जिसमें आरोपों से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय बचाव वयान पर सम्यक विचारोपरान्त श्री संजय कुमार चौधरी, तत्कालीन निरीक्षक उत्पाद गोपालगंज सम्प्रति निरीक्षक उत्पाद, रोहतास के विरुद्ध वर्ष 2016-17 के आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियामावली 2005 के नियम-14 (i) के तहत "निन्दन" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

4. इस पर सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, विशेष सचिव।

14 अगस्त 2018

सं0 8/आ0 (राज0 उ0)-2-12/2017-2851—श्री रामबाबु, तत्का0 अधीक्षक उत्पाद, वैशाली सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय-उपायुक्त उत्पाद का कार्यालय, तिरहुत-सह-सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से दिनांक 16.11.2017 को वैशाली जिलान्तर्गत राजापाकर थाना के बरांटी ओ0पी0 के बसौली ग्राम में जहरीली शराब पीने से 04 (चार) व्यक्तियों की संदेहास्पद मृत्यु की घटना घटित होने के कारण उनके विरुद्ध कर्तव्य के प्रति लापरवाही, प्रभावी पर्यवेक्षण का अभाव एवं बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के आलोक में छापेमारी नहीं करना आदि आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-1966 दिनांक 11.06.2018 द्वारा आरोप पत्र-प्रपत्र-क' गठित करते हुए लिखित अभिकथन की मांग की गयी थी।

2. श्री रामबाबु द्वारा दिनांक 25.06.2018 को विभाग में समर्पित बचाव वयान में कहा गया है कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अंतर्गत छापेमारी में कोई कमी नहीं की गई है और न ही कर्तव्य के प्रति कोई लापरवाही बरती गई है। अतएव आरोप से मुक्त किया जाय।

3. वैशाली जिलान्तर्गत राजापाकर थाना के बरांटी ओ0पी0 के बसौली ग्राम में तीन व्यक्तियों की संदेहास्पद मृत्यु की घटना के संबंध में जिला पदाधिकारी, वैशाली एवं थानाध्यक्ष के समक्ष मृतकों के परिजनों द्वारा दिये गये बयान में मृत्यु का कारण बीमारी बताया गया है। असाैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा भी प्रथम द्रष्टतया मृतक का टी0बी0 का मरीज होना बताया गया है। तथाकथित जहरीली शराब कांड का बिक्रेता अदालत पासवान नीरा अनुज्ञप्ति धारक था और उप विकास आयुक्त के जाँच में यह निष्कर्षित है कि प्रयोग के तौर पर पहली बार अपने घर में शराब बनाने का प्रयास किया था। घटित घटना में आरोपित पदाधिकारी श्री रामबाबू तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, वैशाली का कोई दोष परिलक्षित नहीं होता है। अतएव मामले को संचिकास्त किया जाता है।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, विशेष सचिव।

14 अगस्त 2018

सं0 8/आ0 (राज0 उ0)-2-12/2017-2852—श्री फैयाज अहमद तत्का0 निरीक्षक उत्पाद, वैशाली सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय-सहायक आयुक्त उत्पाद का कार्यालय, पटना से दिनांक 16.11.2017 को वैशाली जिलान्तर्गत राजापाकर थाना के बरांटी ओ0पी0 के बसौली ग्राम में जहरीली शराब पीने से 04 (चार) व्यक्तियों की संदेहास्पद मृत्यु की घटना घटित होने के कारण उनके विरुद्ध कर्तव्य के प्रति लापरवाही, प्रभावी पर्यवेक्षण का अभाव एवं बिहार मद्य निषेध और उत्पाद

अधिनियम 2016 के आलोक में छापेमारी नहीं करना आदि आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-1967 दिनांक 11.06.2018 द्वारा आरोप पत्र-प्रपत्र-‘क’ गठित करते हुए लिखित अभिकथन की मांग की गयी थी।

2. श्री अहमद द्वारा दिनांक 25.06.2018 को विभाग में समर्पित बचाव वयान में कहा गया है कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अंतर्गत छापेमारी में कोई कमी नहीं की गई है और न ही कर्त्तव्य के प्रति कोई लापरवाही बरती गई है। अतएव आरोप से मुक्त किया जाय।

2. वैशाली जिलान्तर्गत राजापाकर थाना के बरांटी ओ0पी0 के बसौली ग्राम में तीन व्यक्तियों की संदेहास्पद मृत्यु की घटना के संबंध में जिला पदाधिकारी, वैशाली एवं थानाध्यक्ष के समक्ष मृतकों के परिजनों द्वारा दिये गये बयान में मृत्यु का कारण बीमारी बताया गया है। असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा भी प्रथम द्रष्टतया मृतक का टी0बी0 का मरीज होना बताया गया है। तथाकथित जहरीली शराब कांड का बिक्रेता अदालत पासवान नीरा अनुज्ञप्ति धारक था और उप विकास आयुक्त के जाँच में यह निष्कर्षित है कि प्रयोग के तौर पर पहली बार अपने घर में शराब बनाने का प्रयास किया था। घटित घटना में आरोपित पदाधिकारी श्री फैयाज अहमद तत्कालीन निरीक्षक उत्पाद, वैशाली का कोई दोष परिलक्षित नहीं होता है। अतएव मामले को संचिकास्त किया जाता है।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, विशेष सचिव।

10 अगस्त 2018

सं0 8/आ0(राज0उ0)-2-08/2015-2795—श्री तारिक महम्मूद, तत्का0 प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, मुंगेर सम्प्रति निरीक्षक उत्पाद (मुख्यालय) के विरुद्ध कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही के फलस्वरूप फर्जी चालान के माध्यम से सरकारी राजस्व की क्षति पहुँचाना, प्रशासनिक क्षमता का अभाव के कारण अधीनस्थ कर्मियों/कार्यालय पर प्रभावकारी नियंत्रण का अभाव एवं निजी स्वार्थ के लिए पद का दुरुपयोग कर अनुज्ञाधारियों को अनुचित लाभ पहुँचाकर सरकारी राजस्व का गबन करना आदि आरोप में विभागीय संकल्प सं0-335 दिनांक 19.01.2016 सह पठित संकल्प सं0-1541 दिनांक 18.03.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना ने अपने पत्रांक-357 दिनांक 01.08.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें निष्कर्षित किया गया है कि आरोप संख्या-01 प्रमाणित, 02 एवं 03 प्रमाणित नहीं होता है। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-3626 दिनांक 22.08.2017 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से द्वितीय बचाव वयान की मांग की गयी। श्री महमूद द्वारा दिनांक 24.10.2017 को विभाग में अपना द्वितीय बचाव वयान समर्पित किया गया, जिसमें आरोप से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

3. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय बचाव वयान पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री महमूद के तीन वार्षिक वेतन वृद्धियों संचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने के प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक-635 दिनांक 23.02.2018 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना ने अपने पत्रांक-520 दिनांक 25.05.2018 द्वारा परामर्श दिया गया कि आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित दण्ड अधिक होने के कारण आनुपातिक नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग के अभिमत से सहमत होते हुए संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री तारिक महमूद, तत्का0 निरीक्षक उत्पाद, मुंगेर सम्प्रति निरीक्षक उत्पाद (मुख्यालय) को वर्ष 2013-14 के प्रतिवेदित आरोप के लिये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14 (1) के तहत 'निन्दन' का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

4. इस पर सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
देवकीनन्दन दास, उप-सचिव।

29 अगस्त 2018

सं0 9/आरोप (राज0) (उ0)-2-06/2012-2966—श्री संजय कुमार, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, मुजफ्फरपुर को रू0 10,000/- (दस हजार) रुपये घूस लेने के आरोप में निगरानी धावादल द्वारा निगरानी थाना कांड सं0-069/2009 दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने एवं प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में निगरानी थाना कांड सं0-086/2009 दर्ज किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 यथासंशोधित 2007 के नियम-14 (xi) के प्रावधान के अंतर्गत विभागीय अधिसूचना सं0-2744 दिनांक-27.06.2014 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड संसूचित किया गया था।

2. श्री कुमार, द्वारा संसूचित दण्डादेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0-18674/15 दायर किया गया जिस में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-11.09.2017 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया:-

"Having regard to the facts discussed above, this writ petition is allowed and the impugned order dated 27.06.2014 (Annexure-22) is set aside. The matter is remitted to the

disciplinary authority to proceed a fresh from the stage of asking second show cause and pass order in accordance with law within a period of four months from the date of receipt of this order".

3. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन हेतु विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया। विधि विभाग द्वारा परामर्श दिया गया है कि पारित न्यायादेश के विरुद्ध एल0 पी0 ए0 दायर करने हेतु पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा कर नियमानुसार आदेश पारित करने का आदेश पारित किया गया है। चूँकि श्री कुमार सेवा से बर्खास्त थे अतएव न्यायादेश के अनुपालनार्थ द्वितीय कारण पृच्छा करने के लिये उन्हें पुनः सेवा में बहाल करने का विभागीय प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की दिनांक 27.12.2017 की बैठक में मद सं0-3 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के आलोक में श्री संजय कुमार, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, के विरुद्ध संसूचित बर्खास्तगी के दण्डादेश सं0-2744 दिनांक-27.06.2014 को निरस्त करते हुये पुनः विभागीय अधिसूचना सं0-5192 दिनांक-28.12.2017 द्वारा सेवा में बहाल किया गया।

4. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन से असहमत होते हुये विभागीय पत्रांक-08 दिनांक-02.01.2018 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय बचाव वयान की मांग की गयी।

5. श्री कुमार द्वारा अपना द्वितीय बचाव वयान दिनांक 19.01.2018 को समर्पित किया गया, जिसमें द्वेष की भावना से फसाने की बात बतायी गयी है तथा उन्हीं बातों को पुनः दोहराया गया है जो उनके द्वारा विभागीय जांच आयुक्त सह-संचालन-पदाधिकारी से समक्ष रखा गया था।

6. निगरानी द्वारा प्रतिवेदित प्रत्यानुपातिक 'धर्नाजन' के संबंध में श्री कुमार के द्वारा तार्किक एवं प्रमाणिक तथ्य अपने द्वितीय बचाव वयान में समर्पित नहीं किया गया है। श्री कुमार द्वारा रिश्तत लेना एवं प्रत्यानुपातिक धनार्जन करना बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। विभागीय जांच आयुक्त सह-संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुये जांच प्रतिवेदन के असहमति के बिन्दुओं पर द्वितीय बचाव वयान में तार्किक एवं प्रमाणिक जबाव प्राप्त नहीं होने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम-14 (xi) के तहत सेवा से बर्खास्त करने के दण्ड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक-1445 दिनांक 20.04.2018 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की मांग की गई।

7. बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1238 दिनांक 01.08.2018 द्वारा परामर्श दिया गया है कि पूर्व में आयोग के पत्रांक-617 दिनांक 10.06.2014 द्वारा बर्खास्तगी के विभागीय दण्ड प्रस्ताव में सहमति विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है। किसी ऐसे मामले में आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा, जहाँ आयोग किसी पूर्व में दिए जाने वाले आदेश के बारे में अपनी सलाह दे चुका हो और उसके बाद कोई नया निर्धारणीय प्रश्न न उठा हो। अतएव पुनः आयोग का परामर्श आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

8. अतएव उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री संजय कुमार, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निलंबित को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 24.08.2018 में मद सं0-23 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(xi) के तहत सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

9. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, संयुक्त सचिव।

29 अगस्त 2018

सं0 9/आरोप (राज0) (उ0)-2-22/2012-2962-श्री सुरेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन निरीक्षक उत्पाद, समस्तीपुर को रू0 10,000/- (दस हजार) रिश्तत लेने के आरोप में निगरानी धावा दल द्वारा निगरानी थाना काण्ड संख्या-053/2007 दिनांक 24.04.2007 दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के परिणाम स्वरूप बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम-3 में निहित प्रावधान के तहत सरकारी सेवक के लिये निर्धारित आचरण के प्रतिकूल कार्य करने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम-14 (Xi) के परन्तुक के तहत मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 24.06.2014 के मद सं0-18 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-2743 दिनांक 27.06.2014 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित किया गया।

2. श्री प्रसाद द्वारा अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC NO- 13744/2014 दायर किया गया। उक्त याचिका में दिनांक 30.10.2017 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है कि :- On the face of it, it appears that the finding of the Enquiry Officer with regard to guilt of misconduct of the petitioner is based on no evidence and, therefore, the punishment inflicting on such enquiry report based on no evidence is also bad and is illegal and not sustainable in the eye of law.

Consequently, the writ petition is allowed and the order, dated 27.06.2013, as contained in Memo No. 2743, Annexure 1, by which the petitioner has been terminated from service of Excise Inspector, is set aside.”

3. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.10.2017 को पारित आदेश के विरुद्ध LPA दायर करने हेतु विधि विभाग से परामर्श प्राप्त की गयी। विद्वान महाधिवक्ता का मतव्य है कि —It is, thus, apparently a case of ‘no evidence’ or ‘no legal evidence at all’ even remotely implicating this petitioner in the departmental proceeding which will lead to his dismissal from services.

In my view, thus, no useful purpose would be served in filing Letters Patent Appeal against the order of the Hon’ble Writ Court.

4. निगरानी विभाग (अन्वेषण व्यूरो), बिहार, पटना के पत्रांक-5047 दिनांक 01.10.12 द्वारा सूचित किया गया है कि आपराधिक वाद में श्री सुरेन्द्र प्रसाद के विरुद्ध आरोप पत्र सं०-95/2007 दिनांक 24.04.2007 समर्पित किया गया है। आपराधिक वाद माननीय विशेष न्यायालय निगरानी के अधीन विचाराधीन है और न्यायादेश प्रतीक्ष्य है।

5. अतएव उक्त के आलोक में पूर्ण विचारोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी०नं०-13744/2014 में दिनांक 30.10.2017 को पारित आदेश के आलोक में श्री सुरेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन निरीक्षक उत्पाद, समस्तीपुर के विरुद्ध विभागीय अधिसूचना सं०-2743 दिनांक 27.06.2014 द्वारा अधिरोपित सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड को इस शर्त के साथ निरस्त किया जाता है कि यदि श्री प्रसाद के विरुद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या-053/2007 दिनांक 20.04.2017 दर्ज है, उक्त आपराधिक काण्ड में भविष्य में सजा होगी तो पुनः विभाग के द्वारा दंडित किये जा सकेंगे। श्री प्रसाद को सेवा में पुनः स्थापन के फलस्वरूप अनुमान्य वित्तीय लाभ देय होगा।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, संयुक्त सचिव।

4 सितम्बर 2018

सं० 9/आरोप (राज०) (नि०)-1-10/2012/3023—श्री मोहन कुमार, तत्कालीन अवर निबंधक, जयनगर (मधुबनी) को 2500/- (दो हजार पाँच सौ रुपये) घूस लेने के आरोप में आर्थिक अपराध इकाई के धावा दल द्वारा आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या-11/2012 दर्ज कर दिनांक 03.08.2012 को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फलस्वरूप विभागीय आदेश सं०-4024 दिनांक 24.08.2012 द्वारा गिरफ्तार किये जाने की तिथि से निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प सं०-6262 दिनांक 06.12.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-213 दिनांक 14.08.2013 सह पठित पत्रांक-भूय दिनांक 09.03.2014 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरुद्ध सरकारी सेवक के निर्धारित कर्तव्य के विरुद्ध आचरण एवं कदाचार के आरोप को प्रमाणित निष्कर्षित किया गया है। संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 (xi) के तहत मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के उपरांत विभागीय अधिसूचना सं०-2742 दिनांक 27.06.2014 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

3. विभागीय अधिसूचना सं०-2742 दिनांक 27.06.2014 द्वारा अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-24 (2) के तहत माननीय मंत्री को संबोधित पुनर्विलोकन अर्जी विभाग में दाखिल किया गया है। श्री कुमार के विरुद्ध दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय मंत्रिपरिषद् स्तर से हुई है अस्तु विभाग स्तर पर विचारणीय नहीं होने के कारण संचित कर रखा गया।

4. श्री कुमार द्वारा विभागीय दण्डादेश सं०-2742 दिनांक 27.06.2014 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका सी०डब्लू०जे०सी० सं०-19331/2015 दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक में दिनांक-16.05.2018 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया है:-

“The respondent no. 3 shall be obliged to dispose off the memorial of the petitioner (Annexure 14) which has been submitted under Rule 24 (2) before the respondent no. 3 after a detailed consideration of all these aspects which have also been raised by the petitioner, including such submissions which have been recorded in the order of this Court within a period of four weeks from the date of receipt/production of a copy of this order in accordance with law.

It is made clear that this Court has not expressed any opinion on the merits of the submissions made by the petitioner. The writ petition is disposed off.”

5. श्री कुमार के विरुद्ध निगरानी विभाग द्वारा दायर आर्थिक अपराध इकाई वाद सं०-11/2012 से संबंधित माननीय विशेष न्यायालय निगरानी में दायर आपराधिक वाद सं०-35/2012 में दिनांक 20.09.2017 को माननीय विशेष न्यायालय निगरानी द्वारा निम्नांकित न्यायादेश पारित किया गया है:-

“On the basis of foregoing discussions court finds that prosecution not proved charge U/s 7/13(2) r/w 13(1)(d) of the P.C Act 1988 against the accused and accused

not found guilty of the aforesaid charge. Accused Mohan Kumar also held not guilty of charge U/s 7/13(2) r/w13 (1) (d) of the P.C. Act 1988 and also acquitted from aforesaid charges and discharged from the liability of his bail bond.”

6. माननीय विशेष न्यायालय निगरानी के द्वारा दिनांक 20.09.2017 को पारित आदेश के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 16.05.2018 को श्री कुमार के पुनर्विलोकन अर्जी निस्तारित करने का आदेश पारित किया गया है। अतएव माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु पुनर्विलोकन अर्जी पर विचार समीचीन है।

7. श्री कुमार ने अपने पुनर्विलोकन अर्जी में विभागीय कार्यवाही के दौरान निगरानी धावादल के सदस्यों और परिवादी का परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण नहीं कराने, नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कारणपृच्छा तथा दण्डादेश नहीं निर्गत करने, रिश्वत की राशि की सत्यापित प्रति, गवाहों का बयान आरोप पत्र के साथ संलग्न नहीं करने, न्यायालय में वाद लंबित रहने के बावजूद विभागीय कार्यवाही पूर्ण किये जाने, दण्ड अधिरोपित करने के पूर्व बिहार लोक सेवा आयोग का मंतव्य पर आरोपी पदाधिकारी का मंतव्य नहीं प्राप्त करने और अभियोजन की स्वीकृति विधि विभाग द्वारा प्रदान किये जाने आदि को न्यायसंगत नहीं होना मुख्य रूप से उल्लिखित किया गया है। इसके अतिरिक्त श्री कुमार के द्वारा अपने अर्जी में माननीय न्यायालय के विभिन्न न्यायादेशों का उल्लेख करते हुए कार्रवाई को न्याय निर्णय के विरुद्ध बताया गया है।

8. कार्यपालिका नियमावली के नियम-21 के तहत आवंटित विभागीय कार्य के आधार पर नियुक्ति प्राधिकार के अधीनस्थ पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से आरोप पत्र और दण्डादेश निर्गत किये गये हैं। निगरानी धावादल के द्वारा रंगे हाथ पकड़े जाने का प्रतिवेदन प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित होने के कारण कारणपृच्छा किया जाना आवश्यक नहीं है। आपराधिक मामले में आपराधिक मुकदमा के साथ-साथ विभागीय कार्यवाही चलाने का प्रावधान है। कार्यपालिका नियमावली के नियम-53(i) के अनुसार अभियोजन का स्वीकृत्यादेश विधि (न्याय) विभाग द्वारा निर्गत किया जाना है न कि नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत किया जायेगा। बिहार लोक सेवा आयोग के अभिमत पर आरोपी पदाधिकारी का मंतव्य प्राप्त करने का प्रावधान नहीं है। विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार का आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 (1) के प्रतिकूल पाया गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अनुसार कोई लोक सेवक होते हुए वैध पारिश्रमिक से भिन्न किसी प्रकार का कोई परितोषण स्वीकार नहीं करेगा। श्री कुमार को आर्थिक अपराधिक इकाई द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया जो सरकारी कर्म के आचरण के प्रतिकूल एवं अशोभनीय है। श्री कुमार को बर्खास्तगी का दण्ड के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त कर अधिरोपित किया गया है। स्पष्टतः श्री कुमार द्वारा उठाये गये बिन्दु नियमसंगत और तार्किक नहीं है। स्वीकार योग्य नहीं रहने के कारण श्री कुमार द्वारा विभागीय अधिसूचना सं०-2742 दिनांक 27.06.2014 द्वारा अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत किया जाता है।

9 इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, संयुक्त सचिव।

4 सितम्बर 2018

सं० 8/आ० (राज० उ०)-2-12/2017/3027—श्री फैयाज अहमद, तत्का० निरीक्षक उत्पाद वैशाली को दिनांक 16.11.2017 को वैशाली जिलान्तर्गत राजापाकर थाना के बरांटी ओ०पी० के बसौली ग्राम में 03 (तीन) व्यक्तियों की संदेहास्पद मृत्यु होने के फलस्वरूप अधिसूचना सं०- 4731 दिनांक 24.11.2017 द्वारा निलंबित किया गया है। विषयगत मामले में श्री अहमद का कोई दोष नहीं पाते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के मामले को क्रमशः विभागीय अधिसूचना सं०-2852 दिनांक 14.08.2018 द्वारा संचिकास्त किया गया है।

2. उक्त स्थिति में श्री फैयाज अहमद, तत्कालीन निरीक्षक उत्पाद, वैशाली को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बन से मुक्त किया जाता है तथा उनके निलम्बन अवधि को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-11 के उप नियम-3 एवं 4 के तहत कर्तव्य अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

3 इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, संयुक्त सचिव।

31 अगस्त 2018

सं० 8/आ०(राज० उ०)-2-11/2015-2992—मुंगेर जिला के अधीक्षक उत्पाद कार्यालय का अंकेक्षण में यह प्रकाश में आया कि उत्पाद शुल्क वसूली से संबंधित ट्रेजरी चलान में हेराफेरी कर सरकारी राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर मामले की जाँच की गयी और पाया गया कि विभिन्न पदाधिकारियों के पदस्थापन काल में फर्जी चलान के माध्यम से राजस्व क्षति पहुँचाई गयी है।

2. श्री सुनील कुमार, अधीक्षक उत्पाद का मुंगेर जिला में पदस्थापन काल दिनांक-13.09.13 से 19.05.14 तक रहा है और उक्त अवधि में रु. 2,03,17,760/—(दो करोड़ तीन लाख सत्रह हजार सात सौ साठ) रुपये राजस्व की क्षति प्रतिवेदित है। श्री कुमार, तत्का० प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, मुंगेर सम्प्रति प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, औरंगाबाद के विरुद्ध कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही के फलस्वरूप फर्जी चालान के माध्यम से सरकारी राजस्व की क्षति पहुँचना, प्रशासनिक क्षमता के

अभाव के कारण अधीनस्थ कर्मियों/कार्यालय पर प्रभावकारी नियंत्रण का अभाव एवं निजी स्वार्थ के लिए पद का दुरुपयोग कर अनुज्ञाधारियों को अनुचित लाभ पहुँचाकर सरकारी राजस्व का गबन करना आदि आरोप में विभागीय संकल्प संख्या-335 दिनांक 19.01.2016 यथा संशोधित संकल्प सं०-1540 दिनांक 18.03.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार पटना ने अपने पत्रांक-354 दिनांक 01.08.17 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया है, जिसमें आरोप संख्या-2 (प्रशासनिक क्षमता के अभाव के कारण अधीनस्थ कर्मियों/कार्यालय पर प्रभावकारी नियंत्रण का अभाव) को प्रमाणित तथा आरोप संख्या-1 एवं 3 को प्रमाणित नहीं निष्कर्षित किया।

4. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-3628 दिनांक 22.08.2017 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी। श्री कुमार द्वारा दिनांक 16.10.2017 को द्वितीय बचाव बयान विभाग में समर्पित किया गया, जिसमें आरोप से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया।

5. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान के समीक्षोपरांत यह पाया गया है कि श्री कुमार के कार्यालय प्रधान की भूमिका में रहने की अवधि में राशि का गबन हुआ है, जो इनकी विफलता का परिचायक है। अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 14 (ix) के अंतर्गत अनिवार्य सेवा निवृत्ति का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

6. विभागीय निर्णय पर पत्रांक-809 दिनांक 09.03.2018 द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्ड अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना का परामर्श/अभिमत की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना ने अपने पत्रांक 1030 दिनांक 14.07.2018 द्वारा दण्ड के विभागीय निर्णय पर अपनी सहमति व्यक्त की है।

7. अतएव उक्त के आलोक में पूर्ण विचारोपरान्त श्री सुनील कुमार तत्कालीन प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, मुंगेर सम्प्रति प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, औरंगाबाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 14 (IX) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

8. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, संयुक्त सचिव।

4 सितम्बर 2018

सं० 8/आ० (राज० उ०)-2-12/2017-3028—श्री रामबाबु, तत्का० अधीक्षक उत्पाद, वैशाली को दिनांक 16.11.2017 को वैशाली जिलान्तर्गत राजापाकर थाना के बरांटी ओ०पी० के बसौली ग्राम में 03 (तीन) व्यक्तियों की संदेहास्पद मृत्यु होने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना सं०-4732 दिनांक 24.11.2017 द्वारा निलंबित किया गया है। विषयगत मामले में श्री रामबाबु का कोई दोष नहीं पाते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के मामले को विभागीय अधिसूचना सं०-2851 दिनांक 14.08.2018 द्वारा संचिकास्त किया गया है।

2. उक्त स्थिति में श्री रामबाबु, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, वैशाली को तत्कालिक प्रभाव से निलम्बन से मुक्त किया जाता है तथा उनके निलम्बन अवधि को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-11 के उप नियम-3 एवं 4 के तहत कर्तव्य अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

3 इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, संयुक्त सचिव।

22 अक्टूबर 2018

सं० 9/आ०अरा०उ०-04-20/2012-3554—श्री विजय कुमार चौरसिया, तत्कालीन निरीक्षक उत्पाद, नालन्दा सम्प्रति सेवा निवृत्त जिन्हें जिन्हें निगरानी थाना कांड संख्या-122/07 दिनांक 02.11.2007 धारा 7(13)(2) एवं 13 (1)(3) भ०नि० अधिनियम 1988 में गिरफ्तारी के कारण विभागीय आदेश संख्या-4900 दिनांक 14.11.2007 द्वारा दिनांक 02.11.2007 के प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा न्यायिक हिरासत से मुक्त होकर उपायुक्त उत्पाद, पटना-सह-मगध प्रमंडल, पटना के कार्यालय में योगदान करने के कारण विभागीय आदेश सं०-5264 दिनांक 02.12.2008 द्वारा श्री चौरसिया को तत्कालिक प्रभाव से मुक्त किया गया है।

2. श्री चौरसिया द्वारा न्यायिक हिरासत से मुक्त होकर उपायुक्त उत्पाद, पटना-सह-मगध प्रमंडल, पटना के कार्यालय में दिनांक 18.04.2008 को योगदान दिया गया था। अतएव विभागीय आदेश सं०-5264 दिनांक 02.12.2008 में अंकित निलंबन से मुक्ति की तिथि दिनांक 02.12.2008 के स्थान पर 18.04.2008 संशोधित किया जाता है। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का परामर्श प्राप्त है।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, संयुक्त सचिव।

22 नवम्बर 2018

सं० 8/आ०(राज० नि०)-1-60/2016-3792—श्रीमती गायत्री अग्रवाल, तत्का० अवर निबंधक, बिक्रमगंज (रोहतास) सम्प्रति अवर निबंधक, बलिया (बेगुसराय) के विरुद्ध कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता के कारण सरकारी राजस्व की क्षति, फर्जी चालान के माध्यम से राजस्व की क्षति, लीज डीड का निबंधन गलत प्रतिवेदन के आधार पर करने एवं कोषागार से निकाली गयी राशि की प्रविष्टि नहीं करने के कारण राजस्व की क्षति, पॉच डिसमिल से कम रकवा वाली भूमि को आवासीय / वाणिज्यिक श्रेणी की जगह विकासशील श्रेणी में निबंधित करने के कारण राजस्व क्षति, बाहरी व्यक्तियों से राजस्व संबंधी कार्य करवाना, प्रशासनिक क्षमता एवं प्रभावकारी नियंत्रण का अभाव तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल आचरण करना आदि आरोप में विभागीय संकल्प सं०-2260 दिनांक 22.05.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी-सह-उप निबंधन महानिरीक्षक के गै०स०प्रे०सं०-20 दिनांक 12.01.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप संख्या-01, 07 को आंशिक प्रमाणित तथा आरोप संख्या-02, 03, 04, 05 एवं 06 को प्रमाणित निष्कर्षित किया गया है।

3. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-380 दिनांक 01.02.2018 द्वारा श्रीमती अग्रवाल से द्वितीय बचाव वयान की मांग की गयी। श्रीमती अग्रवाल द्वारा दिनांक 10.02.2018 को अपना बचाव वयान विभाग में समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेखित किया गया कि प्रशिक्षण का अभाव, बैंक के असहयोग, पर्यवेक्षण निरीक्षण के अभाव, कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से उत्पन्न जटिलता, लिपिकों की घोर कमी एवं जिला अवर निबंधक, सासाराम को अनेकों बार लिखित अनुरोध के बावजूद लिपिकों का पदस्थापन नहीं किया जाना, लिपिकों के गलत जॉच रिपोर्ट देने आदि से राजस्व क्षति हुई। उनके संज्ञान में आते ही बसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही की गयी एवं 10 (दस) साल से जालसाजी के षडयंत्र को पकड़ते हुए एफ०आई०आर० दर्ज कराया गया। उक्त के आलोक में सभी आरोपों से मुक्त करने हेतु उनके द्वारा अनुरोध किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं श्रीमती अग्रवाल से प्राप्त बचाव वयान के समीक्षोपरांत यह पाया गया है कि श्रीमती अग्रवाल से कार्य प्रणाली में चूक हुई है, जिसके कारण राजस्व की क्षति हुई है। अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 (vi) के तहत 03 (तीन) वार्षिक वेतन वृद्धियों संचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने का निर्णय लेते हुए विभागीय पत्रांक-1464 दिनांक 26.04.2018 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना का परामर्श प्राप्त किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-2095 दिनांक 02.11.2018 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी है।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्रीमती गायत्री अग्रवाल, तत्का० अवर निबंधक, बिक्रमगंज (रोहतास) सम्प्रति अवर निबंधक, बलिया के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 (vi) के तहत 03 (तीन) वार्षिक वेतन वृद्धियों संचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, संयुक्त सचिव।

Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya

Office Order

The 24th January 2019

No. XI L रा०.-31/2017-176—On the recommendation and performance report submitted by Collector, Nawadavide letter no. 363 dt. 28/12/2018 the power of certificate officer Shri Sanjiv Kumar Singh, District Cooperative Officer, Nawada has been extended for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dt. 16/01/2019

By Order,

Sd./Illegible, Secretary to Commissioner,

The 24th January 2019

No. VII-रा०-02/2018-177—In the light of proposal received from Collector, Arwal (letter no. 115 dt. 22.12.2018) power of certificate officer have been delegated to following officer for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914

Sl.	Name of Officer & Designation	Remarks
1	Smt Anju Singh, CO., Arwal	Arwal Circle
2	Sri Alok Kumar, CO, Kaler	Kaler Circle
3	Sri JagdishPaswan, CO, Karpi	Karpi Circle
4	Sri Manoj Kumar, CO, Kurtha	Kurtha and SonbhadraBanshiSuryapura Circle

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dt. 16/01/2019

By Order,

Sd./Illegible, Secretary to Commissioner,

The 4th February 2019

No. I-स्था०-71/2017-277—In the light of proposal received from Collector, Gaya (letter no. 44 dt.20.12.2018) power of certificate officer have been delegated to following officer for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914

Sl.	Name of Officer & Designation	Remarks
1	Md. Blaguddin, Additional Collector (Department Proceeding) Gaya.	Gaya District.
2	Sri Surendra Prasad Singh, Regional Manager, Co-operative Land Development Bank, Gaya	

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dt. 17/01/2019

By Order,

Sd./Illegible, Secretary to Commissioner,

The 8th October 2018

No. I-स्था०-72/2017-2902—In the light of proposal received from Collector, Jehanabad (letter no. 320dt.02/08/2018) power of certificate officer have been delegated to following officer for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914

Sl.	Name of Officer & Designation	Remarks
1	Sri Arun Kumar, Circle Officer, Hulashganj	Hulashganj
2	Sri Sanjeev Kumar Trivedi, Circle Officer, Modanganj	Modanganj
3	Sri IndraDeoPandit, Circle Officer, RatniFaridpur	RatniFaridpur
4	Smt. AlkaKumari, Circle Officer, Ghoshi	Ghoshi

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dt. 25/09/2018

By Order,

Sd./Illegible, Secretary to Commissioner,

The 12th February 2019

No. I-स्था०-71/2017-336—In the light of proposal received from Collector, Gaya (letter No. 14 dt.08.01.2019) power of certificate officer have been delegated to following officer for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914

Sl.No.	Name of Officer & Designation	Remarks
1	Sri Rameshwar Ram, CO, Tankuppa	Tankuppa Circle
2	Sri Rameshwar Ram, CO, Phatehpur	Phatehpur Circle (Add. charge)

3	Sri SatendraPratapMadhukar, CO, Belaganj	Belganj Circle
4	Sri SatendraChoudhary, CO, Wazirganj	Wazirganj Circle
5	Sri LodhoBaraik, CO, Sherghati	Sherghati Circle
6	Sri Sanjay Kumar Jha, CO, Dobhi	Dobhi Circle
7	Sri Kailash Mahto, CO, Barachatti	Barachatti Circle
8	Sri Raj Kumar, CO, Imamganj	Imamganj Circle
9	Md. Noman Ahmad, CO, Mohanpur	Mohanpur Circle
10	Sri Sanjay Kumar Prasad, CO, Bankebazar	Bankebazar Circle
11	Sri Arvind Kumar Choudhary, CO Dumariya	Dumariya Circle
12	Sri Vikesh Pandey, CO, Gurua	Gurua Circle
13	Sri Ram Kumar Raman, CO, Amas	Amas Circle
14	Sri Tara Prakash, CO, Conch	Conch Circle
15	Sri Nishant Kumar, CO, Guraru	Guraru Circle
16	Sri Nishant Kumar, CO, Paraiya	Paraiya Circle add. charge
17	Sri Pintu Kumar, CO, NimchakBathani	NimchakBathani Circle
18	Sri Anuj Kumar, CO, Atri	Atri Circle
19	Sri Anuj Kumar, CO, Mohra	Mohra Circle add. charge

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dt. 08/02//2019

By Order,

Sd./Illegible, Secretary to Commissioner,

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 1-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण
सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

सं० 359—मैं राजेश्वर द्विवेदी उर्फ राजेश्वर दुबे, पिता—स्व० गोपाल शरण द्विवेदी, ग्राम+पो०—दतियाना, थाना—बिक्रम, जिला—पटना का स्थायी निवासी हूँ। मेरा शपथ पूर्वक कहना है कि मैं राजेश्वर द्विवेदी उर्फ राजेश्वर दुबे दोनों नाम से जाना जाता हूँ तथा दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। आज से मैं राजेश्वर दुबे से जाना जाऊंगा। Affidavit No. 9088, dated 24.12.2018

राजेश्वर द्विवेदी।

No. 360—I, Rudrani, D/o Ravi Shankar Dvivedi, R/o 18 Sardar Patel Path, North S. K. Puri, Boring Road, Patna-13 shall be known as Rudrani Shankar Dvivedi & D.O.B. 07.09.1999.

Rudrani.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 1-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक (अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 08/अभि०-03-26/2014,सा०प्र०-3248
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
8 मार्च 2019

श्री राजेश कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-473/11 को उप सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के पदस्थापन काल में ऑडिटर एवं कनीय अभियंता की परीक्षा में षड्यंत्र पूर्वक चिन्हित अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर ओ०एम०आर०सीट में छेड़-छाड़ करने संबंधी आरोपों पर आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना द्वारा दर्ज कांड सं०-23/12, दिनांक 20.10.2012 में अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया। उक्त कांड के क्रम में विधि विभाग के आदेश सं०-67 दिनांक 22.04.2015 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति दी गयी। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित करते हुए श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। इस क्रम में श्री कुमार का स्पष्टीकरण (दिनांक 04.03.2016) प्राप्त हुआ। सम्यक् विचारोपरांत मामले के वृहद जाँच की आवश्यकता पायी गयी तथा संकल्प ज्ञापांक-7715 दिनांक 31.05.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को इस हेतु संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. कालान्तर में संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें श्री कुमार के विरुद्ध गठित बहुधा आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। विभागीय पत्रांक-2625 दिनांक 23.02.2018 द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए श्री कुमार से लिखित अभिकथन की मांग की गयी। इस क्रम में प्राप्त स्पष्टीकरण में उन्होंने प्रमाणित आरोपों के बचाव में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने यह उल्लेख किया कि विभागीय कार्यवाही की सुनवाई में उन्हें आरोपों के बचाव हेतु याचित कागजात/दस्तावेज विभाग एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। जबकि विभागीय पत्रांक 11458 दिनांक 24.08.2016 द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर संचालन पदाधिकारी को विभागीय मंतव्य उपलब्ध कराया गया। श्री कुमार द्वारा आरोपों के बचाव हेतु याचित सूचना, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के पत्रांक 1603/आ० दिनांक 21.07.2017 द्वारा उन्हें उपलब्ध कराया गया। इसके साथ संचालन पदाधिकारी/विभागीय स्तर पर श्री कुमार द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में निगरानी/बिहार कर्मचारी चयन आयोग के स्तर से प्राप्त सूचना/अभिलेख उन्हें क्रमशः पत्रांक-7720 दिनांक 23.06.2017, ज्ञापांक 12169 दिनांक 19.09.2017 एवं पत्रांक 15476 दिनांक 05.12.2017 द्वारा उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार सूचना/अभिलेख प्राप्त नहीं होने संबंधी श्री कुमार का कथन सत्य से परे है।

वस्तुतः आरोपित पदाधिकारी अंकेक्षक तथा कनीय अभियंता की परीक्षा से संबंधित आयोग के स्ट्रॉग रूम के प्रभार में थे, जिसमें परीक्षा की कॉपियाँ रखी गयी थी। उनका कार्यालय कक्ष स्ट्रॉग रूम के बिल्कुल नजदीक था। उन्हें स्ट्रॉग रूम के पेपर सील का नियमित निरीक्षण करना था, जो उन्होंने नहीं किया और पेपर सील पर उनके द्वारा पूर्व में किये गये हस्ताक्षर से भिन्न हस्ताक्षर होने (अर्थात् पेपर सील के साथ छेड़-छाड़ और कूटकरण होने) की सूचना उनके द्वारा आयोग के अध्यक्ष को नहीं दी गयी। उक्त कांड के अनुसंधान में पाया गया कि एक संगठित गिरोह के द्वारा देर रात्रि में स्ट्रॉग रूम में रखी गयी उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़-छाड़ कर कतिपय अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस कांड में उनकी संलिप्तता के कारण ही उन्हें अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया तथा कालान्तर में अभियोजन की स्वीकृति भी दी गयी। इस प्रकार श्री कुमार का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया तथा अत्यंत गंभीर प्रकृति के उक्त प्रमाणित आरोपों में उनकी संलिप्तता सिद्ध हुई। विदित हो कि पूर्व में भी आरोपित पदाधिकारी का सेवा इतिहास अच्छा नहीं रहा है और उनके पूर्व पदस्थापन प्रखंड विकास पदाधिकारी, चकिया (पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी) के पद पर बरती गयी वित्तीय अनियमितता के लिए तीन (03) वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड संसूचित किया गया है।

3. तत्पश्चात उक्त आरोपों की प्रमाणिकता के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर समीक्षोपरांत श्री कुमार के विरुद्ध 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' का दंड विनिश्चित किया गया। विभागीय पत्रांक-8656 दिनांक 29.06.2018 द्वारा उक्त

विनिश्चित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से मंतव्य की मांग की गयी। इस क्रम में आयोग की पूर्णपीठ द्वारा सहमति प्रदान की गयी, जो बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-2074 दिनांक 02.11.2018 द्वारा प्राप्त हुआ।

4. बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति प्राप्ति के उपरांत श्री राजेश कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-473/2011, तत्कालीन उप सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना (सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, खान एवं भूतत्व विभाग) के अनिवार्य सेवानिवृत्ति संबंधी संलेख/प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक-3182 दिनांक 07.03.2019 द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु भेजा गया। राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 08.03.2019 को सम्पन्न बैठक में मद सं०-02 के रूप में सम्मिलित करते हुए उक्त दंड प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

5. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14(ix) के प्रावधानों के तहत श्री राजेश कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-473/2011, तत्कालीन उप सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं० 08/आरोप-01-156/2014 सा0प्र0-2723

27 फरवरी 2019

श्री बाबू यादव, बि0प्र0से0, को0क्र0-926/2011 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मीनापुर, मुजफ्फरपुर (सम्प्रति विशेष कार्यपदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना) के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 2580 दिनांक 01.6.2007 द्वारा इन्दिरा आवास योजना के आवंटन में अनियमितता बरतने संबंधी गठित आरोप प्रपत्र 'क' ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3148 दिनांक 17.03.2008 द्वारा उपलब्ध कराया गया। प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में श्री यादव से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 10166 दिनांक 16.09.2008 द्वारा जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से मंतव्य की मांग की गयी। श्री यादव के विरुद्ध गठित आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी के मंतव्य की समीक्षा के उपरांत श्री यादव के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 14438 दिनांक 04.09.2013 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. जाँच पदाधिकारी, संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 4666 दिनांक 17.10.2014 द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी श्री बाबू यादव के विरुद्ध गठित कुल 11 आरोपों में से आरोप संख्या 3, 4, 10 एवं 11 को छोड़कर सभी आरोपों को प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 16583 दिनांक 02.12.2014 द्वारा श्री यादव से लिखित अभ्यावेदन/स्पष्टीकरण की मांग की गयी उक्त के आलोक में श्री यादव का स्पष्टीकरण (दिनांक 02.02.2015) प्राप्त हुआ।

3. श्री यादव के विरुद्ध मुख्य आरोप इंदिरा आवास योजना में बरती गयी अनियमितता से संबंधित है जिसमें संपन्न व्यक्तियों तथा एक ही परिवार के दो व्यक्तियों को इंदिरा आवास आवंटित करने का आरोप लगाया गया। श्री यादव से प्राप्त स्पष्टीकरण में जांच पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित आरोपों (यथा आरोप संख्या-01, 06 एवं 08) के संबंध में उनके द्वारा प्रतिकार करते हुए आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया। वर्णित तथ्यों के आलोक में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं श्री यादव द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन की समीक्षा के उपरांत पाया गया है कि:-

(I) आरोपी पदाधिकारी श्री यादव द्वारा पंचायत सचिव एवं राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन को आधार बनाते हुए वैसी सुविधा सम्पन्न व्यक्तियों को जिन्हें पूर्व से पक्का मकान है तथा एक ही परिवार के भिन्न भिन्न व्यक्तियों को भी इंदिरा आवास आवंटित किया गया है।

(II) इंदिरा आवास योजना गरीबी रेखा से नीचे के गृह विहीन व्यक्तियों के लिए है, परन्तु इसका लाभ अयोग्य व्यक्तियों को मिला तथा योजना राशि का अपव्यय हुआ।

(III) आरोपी पदाधिकारी के अनुश्रवण प्रणाली एवं कार्यपद्धति के पारदर्शी नहीं होने के कारण पंचायत सचिव अथवा राजस्व कर्मचारी द्वारा सुविधा सम्पन्न व्यक्तियों को इंदिरा आवास आवंटित करने की अनुशंसा की गयी।

उपर्युक्त के आलोक में संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 11182 दिनांक 04.08.2015 द्वारा "दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक" का दंड अधिरोपित/संसूचित किया गया।

4. उक्त दंडादेश के विरुद्ध श्री यादव द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित करते हुए दंड से मुक्त करने का अनुरोध किया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री यादव के पुनर्विचार अभ्यावेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि उनके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है जिसका उल्लेख पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण में किया गया है। इस प्रकार उनके अभ्यावेदन में किसी नये तथ्यों का उल्लेख नहीं रहने के कारण उनके अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 11182 दिनांक 04.08.2015 द्वारा अधिरोपित/संसूचित दंड "दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक" को यथावत रखा जाता है।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं० 08/था०का०—12—01/2017, सा०प्र०—3165

7 मार्च 2019

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा आयोजित प्रथम इन्टर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (प्रा०)—2014 के प्रश्न पत्र लीक करने के मामले की जांच हेतु दर्ज अगमकुओं थाना कांड संख्या—44/2017, दिनांक 04.02.2017 के अनुसंधान के क्रम में श्री परमेश्वर राम, बि०प्र०से० (कोटि क्रमांक—440/11) तत्कालीन सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाये जाने तथा दिनांक 08.02.2017 को उनकी गिरफ्तारी एवं न्यायायिक हिरासत में भेजे जाने की सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक 416 दिनांक 10.02.2017 द्वारा प्राप्त होने के उपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली—2005 के नियम—9(1)(ग) एवं 9(2)(क) के निहित प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक—1680 दिनांक 13.02.2017 द्वारा श्री राम को न्यायायिक हिरासत की तिथि 08.02.2017 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया था।

विषयगत मामले में विभागीय कार्यवाही सम्प्रति प्रक्रियाधीन है तथा इस बीच श्री राम दिनांक 28.02.2019 को वार्धक्य सेवानिवृत्त गये हैं।

अतएव सम्यक विचारोपरांत दिनांक 28.02.2019 (अपराहन) के प्रभाव से श्री राम को निलंबन मुक्त किया जाता है।

निलंबन अवधि का विनियमन विभागीय कार्यवाही के फलाफल पर निर्भर करेगा।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं० कारा/नि०(प्रोबेशन)—03/2017—2081

कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प

8 मार्च 2019

श्री विनोद कुमार सिंह, तत्कालीन जिला प्रोबेशन पदाधिकारी—सह—प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, सीवान (सम्प्रति प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, सासाराम) के विरुद्ध T.A No-13/2006 सूचित हलवाई बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय न्यायालय, सीवान के द्वारा पारित आदेश एवं डिक्री के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अपील दायर करने हेतु श्री दीप नारायण राय, जी०पी०, सीवान के पत्रांक 61 दिनांक 05.05.2011 द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला विधि शाखा को प्रेषित उक्त महत्वपूर्ण पत्र का पूरे पदस्थापन काल में पूर्ण रूपेण पर्यवेक्षण नहीं किये जाने एवं अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता बरतने के संबंध में जिलाधिकारी, सीवान के पत्रांक 538 दिनांक 20.07.2017 द्वारा प्रेषित प्रपत्र 'क' में गठित प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4035 दिनांक 25.07.2017 द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु आयुक्त, सारण प्रमंडल, सारण (छपरा) को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

2. आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा के पत्रांक 140/V दिनांक 05.06.2018 से प्राप्त आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा—सह—संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया। संचालन पदाधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में उल्लिखित किया है कि आरोप के परिप्रेक्ष्य में आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपस्थापन पदाधिकारी के लिखित मंतव्य के समुचित विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी पदाधिकारी के स्तर से माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के बिन्दु पर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई है। इतना ही नहीं यह भी अकनीय है कि यद्यपि जी०पी०, सीवान का पत्र कार्यालय में ससमय प्राप्त हुआ परन्तु उक्त पत्र को आरोपी पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित ही नहीं किया गया है जैसा कि अभिलेख में उपलब्ध कागजातों से स्पष्ट होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपी पदाधिकारी के स्थानांतरण से 5—6 महीने के पश्चात् ही पहली बार यह मामला प्रकाश में आया है। ऐसी स्थिति में आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध लगाया गया यह आरोप, कि पूर्णरूपेण पर्यवेक्षण नहीं किया गया है, प्रमाणित नहीं होता है।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में संचालन पदाधिकारी के उक्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में विभागीय पत्रांक 8318 दिनांक 27.11.2018 के द्वारा जिला पदाधिकारी, सीवान से कतिपय बिन्दुओं पर कृत कार्रवाई से संबंधित समंतव्य प्रतिवेदन की मांग की गई। तदालोक में जिला पदाधिकारी, सीवान द्वारा पत्रांक 100/स्था० दिनांक 28.01.2019 के माध्यम

से बिन्दुवार समंतव्य प्रतिवेदन विवरणी में अंकित कर उपलब्ध कराया गया है। जिला पदाधिकारी के मंतव्य के अनुसार आगत पंजी के प्रभारी सहायक, श्री शैलेश कुमार द्वारा कार्यालय प्रधान के समक्ष मूल पत्र डाक स्टेज में उपस्थापित नहीं किया गया। डाक स्टेज में पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप श्री सिंह द्वारा संबंधित सहायक को वर्णित पत्र पृष्ठांकित नहीं किया जा सका। प्रश्नगत पत्र का कार्यालय प्रधान के संज्ञान में लाये बिना सहायक द्वारा अपने स्तर से ही अनौपचारिक रूप से निष्पादन किये जाने का कथित प्रयास किया गया। स्पष्ट है कि पत्र कार्यालय में प्राप्त होने की जानकारी श्री सिंह को नहीं थी।

साथ ही प्रासंगिक मामले में दोषी श्री शैलेश कुमार, तत्कालीन लिपिक, जिला विधि शाखा, सीवान सम्प्रति अंचल कार्यालय, हुसैनगंज के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के उपरान्त जिला पदाधिकारी, सीवान के ज्ञापांक 10/स्था0 दिनांक 02.01.2019 द्वारा उन्हें “ दो वेतन वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध किये जाने ” संबंधी दण्डादेश संसूचित की गई है।

4. उपरोक्त के आलोक में श्री सिंह के विरुद्ध गठित आरोप की समीक्षा संचालन पदाधिकारी के अधिगम, उपलब्ध कागजातों एवं जिलाधिकारी, सीवान से प्राप्त उक्त प्रतिवेदन के आलोक में की गयी। समीक्षोपरान्त स्पष्ट होता है कि जी0पी0 सीवान का पत्र आरोपी पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित ही नहीं किया गया जिसके कारण ही मामले का संज्ञान नहीं हो पाने के कारण उनके स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। इस मामले में श्री शैलेश कुमार, तत्कालीन लिपिक, जिला विधि शाखा, सीवान के द्वारा ही पूर्णतः लापरवाही बरतते हुए संबंधित पत्र आरोपी पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित नहीं किया गया तथा मूल पत्र को तत्कालीन अंचलाधिकारी को हाथो-हाथ दे दिया गया जिसके लिए लिपिक, श्री शैलेश कुमार को जिलाधिकारी, सीवान द्वारा दण्डित करते हुए उनकी दो वेतनवृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध कर दी गयी है।

5. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में संचालन पदाधिकारी के अधिगम से सहमत होते हुए श्री विनोद कुमार सिंह, तत्कालीन जिला प्रोबेशन पदाधिकारी, सीवान-सह-प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, सीवान सम्प्रति प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, सासाराम को आरोप मुक्त करते हुए उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)।

सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-39/2016-1668

17 मई 2018

चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने के कारण है कि श्री सरोज कुमार सिन्हा, तत्का0 जिला अवर निबंधक, रोहतास, सासाराम सम्प्रति निलंबित मुख्यालय-निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार, पटना के विरुद्ध महालेखाकार के प्रतिवेदन पर कार्रवाई नहीं करने के परिणाम स्वरूप राजस्व क्षति, सरकारी निर्देश की अनदेखी कर भूमि का निबंधन करना, लिपिक से स्थल जाँच करवाना, कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतना तथा राजस्व संग्रहण में विफल होने के परिणाम स्वरूप राजस्व की क्षति होना, बिना स्थल जाँच के ही प्रतिवेदन समर्पित करना, प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण का अभाव एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन करना आदि आरोप विनिर्दिष्ट है। जैसा कि संलग्न आरोप पत्र प्रपत्र-‘क’ में वर्णित है।

2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री सरोज कुमार सिन्हा के विरुद्ध संलग्न प्रपत्र -‘क’ में विनिर्दिष्ट आरोपों के जाँच के लिए उनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 (2) में विहित रीति में विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के लिए श्री अयाज अहमद खाँ, सहायक निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री सरोज कुमार सिन्हा के विरुद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-8 ए को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री सरोज कुमार सिन्हा से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव वयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप प्रपत्र-‘क’ के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, विशेष सचिव।

सं० 8/आ० (राज० उ०)-2-10/2017-1644

16 मई 2018

चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने के कारण है कि श्री किशोर कुमार साह, तत्का० प्रभारी सहायक आयुक्त उत्पाद, रोहतास के विरुद्ध कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय से बाहर रहना आदि आरोप विनिर्दिष्ट है। जैसा कि संलग्न आरोप पत्र प्रपत्र-‘क’ में वर्णित है।

2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री किशोर कुमार साह के विरुद्ध संलग्न प्रपत्र -‘क’ में विनिर्दिष्ट आरोपों के जाँच के लिए उनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 (2) में विहित रीति में विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के लिए श्री श्रीकृष्ण पासवान, संयुक्त आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री किशोर कुमार साह के विरुद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-8 ए को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री किशोर कुमार साह से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव वयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप प्रपत्र-‘क’ के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, विशेष सचिव।

सं० 8/आ०(राज०उ०)-2-08/2017-2177

27 जून 2018

चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री अशोक कुमार, तत्कालीन निरीक्षक उत्पाद गया सम्प्रति निलंबित मुख्यालय उपायुक्त उत्पाद का कार्यालय, पटना -सह-मगध प्रमंडल पटना के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रावधानों के विरुद्ध शराब का अवैध कारोबार करना, पद का दुरुपयोग करना एवं बिहार सरकारी सेवा आचार नियमावली 1976 के प्रावधानों के प्रतिकूल काम करना आदि आरोप विनिर्दिष्ट है। जैसा कि संलग्न आरोप पत्र प्रपत्र ‘क’ में वर्णित है।

2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री अशोक कुमार के विरुद्ध संलग्न प्रपत्र ‘क’ में विनिर्दिष्ट आरोपों के जाँच के लिए उनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (2) में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के लिए, श्री श्रीकृष्ण पासवान, संयुक्त आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री अशोक कुमार के विरुद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में सहायक आयुक्त उत्पाद, गया को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री अशोक कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप पत्र प्रपत्र ‘क’ के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, विशेष सचिव।

सं० 8/आ० (राज० उ०)-02-31/2015-4015

7 दिसम्बर 2018

विभागीय संकल्प संख्या-3664 दिनांक 02.08.2016 एवं संकल्प सं०-5366 दिनांक 18.10.2016 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम- 43 (बी०) के तहत सम्परिवर्तिता श्री सरोज कुमार, तत्का० अधीक्षक उत्पाद, औरंगाबाद के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी श्री कृष्ण कुमार वर्मा, अवर सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के दिनांक 31.08.2018 को सेवा निवृत्त हो जाने कारण उनके स्थान पर प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-8 ए को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

2. संकल्प की अन्य शर्तें यथावत् रहेगी।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
देवकीनन्दन दास, उप—सचिव।

सं० 8/आ० (राज० उ०)—2-11/2017-1643

16 मई 2018

चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने के कारण है कि श्री राजकिशोर प्रसाद सिंह, तत्का० निरीक्षक उत्पाद, रोहतास के विरुद्ध कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय से बाहर रहना आदि आरोप विनिर्दिष्ट है। जैसा कि संलग्न आरोप पत्र प्रपत्र—'क' में वर्णित है।

2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री राजकिशोर प्रसाद सिंह के विरुद्ध संलग्न प्रपत्र—'क' में विनिर्दिष्ट आरोपों के जाँच के लिए उनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम—17 (2) में विहित रीति में विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के लिए श्री श्रीकृष्ण पासवान, संयुक्त आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री राजकिशोर प्रसाद सिंह के विरुद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—8 ए को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री राजकिशोर प्रसाद सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव वयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

आदेश :—आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप प्रपत्र—'क' के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज, विशेष सचिव।

सं० 8/आ० (राज० उ०)—02-30/2015-1932

7 जून 2018

चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने के कारण है कि श्री मनोज कुमार सिंह, तत्का० अधीक्षक उत्पाद, बेगुसराय सम्प्रति निलंबित मुख्यालय—उपायुक्त उत्पाद, तिरहुत—सह—सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध बक्सर पदस्थापन काल में अधीनस्थ कर्मियों पर अर्भ्यादित भाषा एवं जाति बोधक शब्द आदि का प्रयोग करना, बक्सर उत्पाद हाजत से अभियुक्त का फरार होना, कार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता तथा शिथिलता बरतने एवं सुरक्षा के मानकों की अनदेखी करना एवं प्रशासनिक क्षमता का अभाव, मद्य निषेध निति के विपरीत कार्य कर उत्पाद सिपाही श्री पंजियार से शराब की मांग करना तथा उनके अवकाश को अस्वीकृत करना एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के प्रावधान के प्रतिकूल आचरण तथा बेगुसराय पदस्थापन काल में सरकारी दायित्यों के निर्वाहन में लापरवाही एवं सरकारी दिशा निर्देशों की अवहेलना करना आदि आरोप विनिर्दिष्ट है। जैसा कि संलग्न आरोप पत्र प्रपत्र—'क' एवं पूरक आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में वर्णित है।

2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री मनोज कुमार सिंह के विरुद्ध संलग्न प्रपत्र—'क' में विनिर्दिष्ट आरोपों के जाँच के लिए उनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम—17 (2) में विहित रीति में विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के लिए श्री अभय राज, विशेष सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री मनोज कुमार सिंह के विरुद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री कुमार अमित, विशेष अधीक्षक (मुख्यालय) को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री मनोज कुमार सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव वयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप प्रपत्र—'क' के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
देवकीनन्दन दास, उप—सचिव।

सं० 6 एस०एस० (11)14/2018-837

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

संकल्प

13 मार्च 2019

विषय :-राज्य में स्थापित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना एवं इनके अधीन सभी अंगीभूत संस्थानों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को क्रमशः **I.C.A.R** एवं राज्य कर्मियों के अनुरूप पुनरीक्षित वेतन स्तर लागू करने की औपबंधिक स्वीकृति के संबंध में।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के, असाधारण राजपत्र में प्रकाशित गजट के आधार पर देश के अधिकांश कृषि एवं पशुपालन विश्वविद्यालयों में सातवाँ वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर पुनरीक्षित वेतन मान लागू किया जा चुका है, जिसके पश्चात् भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (ICAR), नई दिल्ली द्वारा अपने अधिसूचना संख्या-F.No.-1(4)/2017 Per.IV, दिनांक-27.03.2018 द्वारा अंगीकृत किया गया है। राज्य में स्थापित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना एवं इनके अधीन सभी अंगीभूत संस्थानों के शिक्षकों को ICAR के अनुरूप दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से औपबंधिक रूप से पुनरीक्षित वेतन स्तर तथा इस विश्वविद्यालय के अधीन सभी अंगीभूत संस्थानों शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को राज्य कर्मियों के अनुरूप दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से वैचारिक एवं दिनांक 01/04/2017 से वास्तविक लाभ औपबंधिकरूप से दिया जाना है।

2. बिहार राज्य में पशु विज्ञान, पशुपालन, गव्य तकनीकी, मत्स्य एवं सहवृद्ध विज्ञान के विकास के लिए एक विश्वविद्यालय को स्थापित करने और निगमित करने हेतु बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-699, दिनांक-29.08.2016 द्वारा राज्य में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इस विश्वविद्यालय के अंगीभूत संस्थान यथा बिहार पशुचिकित्सा महाविद्यालय, पटना, संजय गाँधी डेयरी तकनीकी संस्थान, पटना एवं डॉ. कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज के परिसर पर अवस्थित मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना एवं इनके अंगीभूत संस्थानों में शिक्षकों-शिक्षकेत्तर कर्मियों का पद सृजित/स्वीकृत है (सूची संलग्न)। इन स्वीकृत/सृजित पदों पर कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के द्वारा पशु विज्ञान, पशुपालन, पशु चिकित्सा, गव्य प्रौद्योगिकी, मत्स्य तकनीकी, मुर्गी पालन तथा ज्ञान एवं स्कॉलरशिप की अन्य सहवृद्ध शाखाओं में शिक्षा के विस्तार एवं प्रसार का कार्य किया जा रहा है। यह विश्वविद्यालय राज्य का एक मात्र एकलौता विश्वविद्यालय है जिसमें पशु विज्ञान, पशुपालन, पशु चिकित्सा, गव्य प्रौद्योगिकी, मत्स्य तकनीकी, मुर्गी पालन आदि पर शोध, अनुसंधान एवं शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाता है।

3. बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के शिक्षकों/वैज्ञानिकों को पुनरीक्षित वेतन स्तर स्वीकृत किये जाने के पश्चात् बकाया राशि के भुगतान हेतु ICAR द्वारा कुल बकाया राशि का 50 प्रतिशत राशि ग्रांट के रूप में विश्वविद्यालय को विमुक्त किया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार को वहन करनी होगी (अनुलग्नक-1) तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन स्तर की स्वीकृति के उपरान्त मिलने वाली बकाया राशि दिनांक-01.04.2017 के प्रभाव से शत-प्रतिशत वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना एवं इसके अधीन सभी अंगीभूत संस्थानों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को नवीन वेतन संरचना राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार पर शिक्षकों के बकाया राशि के भुगतान पर रुपये 315.714 लाख एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के बकाया राशि के भुगतान पर रुपये 510.00 लाख अर्थात् कुल रुपये 815.714 लाख (आठ करोड़ पन्द्रह लाख एकहत्तर हजार चार सौ) मात्र का अतिरिक्त वित्तीय भार बकाया राशि के भुगतान पर पड़ने की संभावना है।

4. **अतः उपरोक्त के आलोक में प्रस्ताव है कि-**

- राज्य में स्थापित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना एवं इनके अधीन सभी अंगीभूत संस्थानों के शिक्षकों को ICAR द्वारा कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन स्तर की अनुशंसा के अनुरूप दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से औपबंधिक रूप से पुनरीक्षित वेतन स्तर लागू करने की स्वीकृति प्रदान की जाय,
- उसी विश्वविद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मियों को दिनांक-01/01/2016 के प्रभाव से राज्य कर्मियों की भाँति वैचारिक रूप से एवं दिनांक-01/04/2017 के प्रभाव से वास्तविक आर्थिक लाभ के साथ वेतन पुनरीक्षण का लाभ देने की औपबंधिक रूप से स्वीकृति प्रदान की जाय, साथ ही
- पदवार विस्तृत आदेश तीन माह के अन्दर वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कर दिया जायेगा। वित्त विभाग से अंतिम रूप से परामर्शित एवं पुनरीक्षित वेतन स्तर के आधार पर यदि औपबंधिक रूप से भुगतान की गयी राशि अधिक/कम होती है तो तदनुसार वसूली/प्रतिपूर्ति की जा सकेगी। बकाया भुगतान के संबंध में वित्त विभाग के परामर्श से किस्तों में व्यवस्था की जाएगी।

5. दिनांक 08.03.2019 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-24 के रूप में सम्मिलित करते हुये मंत्रिपरिषद् द्वारा राज्य में स्थापित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना एवं इनके अधीन सभी अंगीभूत संस्थानों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को क्रमशः **I.C.A.R** एवं राज्य कर्मियों के अनुरूप पुनरीक्षित वेतन स्तर लागू करने की औपबंधिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जनसाधारण की सूचना हेतु अगले अंक में प्रकाशित किया जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डा० एन० विजयलक्ष्मी, सचिव।

औपबधिक BIHAR ANIMAL SCIENCES UNIVERSITY, PATNA Revised 7th pay Structure of Teaching Post, Bihar Animal Sciences University (BASU), Patna									
Sr No.	Sanctioned Post	No. of Sanction Post	Pay Band & Grade Pay	Pay Band	Basic pay with GP from 01.01.2016	Multiply 2.57 as per guide line	Pay Band 7th CPC	Level as per guide line	Revised Basic Pay 7th CPC as per guide line
1	Director Resident Instruction-cum-Dean PGS	1	37400-67000+GP 10000	PB-4	47400	121818	144200-218200	14	144200
2	Director Research	1	37400-67000+GP 10000	PB-4	47400	121818	144200-218200	14	144200
3	Director Ext. Education	1	37400-67000+GP 10000	PB-4	47400	121818	144200-218200	14	144200
4	Registrar	1	37400-67000+GP 10000	PB-4	47400	121818	144200-218200	14	144200
5	Student Welfare Officer cum Placement Officer	1	37400-67000+GP 10000	PB-4	47400	121818	144200-218200	14	144200
6	University Librarian cum Information Officer	1	37400-67000+GP 9000	PB-4	46400	119248	131100-216600	13 A	131100
7	Dy. Director Resident Instruction	1	37400-67000+GP 8700	PB-4	46100	118477	118500-214100	13	118500
8	Dy. Director Research	3	37400-67000+GP 8700	PB-4	46100	118477	118500-214100	13	118500
9	Dy. Director (Training Information)	2	37400-67000+GP 8700	PB-4	46100	118477	118500-214100	13	118500
10	Dy. Librarian	1	15600-39100+GP 7600	PB-3	23200	59624	78800-209200	12	78800
11	Asstt. Librarian	2	15600-39100+GP 5400	PB-3	21000	53970	56100-177500	10	56100
	Total =	15							

औपबधिक BIHAR ANIMAL SCIENCES UNIVERSITY, PATNA Revised 7th pay Structure of Teaching Post, Bihar Veterinary College, Patna									
Sr No.	Sanctioned Post	No. of Sanction Post	Pay Band & Grade Pay	Pay Band	Basic pay with GP from 01.01.2016	Multiply 2.57 as per guide line	Pay Band 7th CPC	Level as per guide line	Revised Basic Pay 7th CPC as per guide line
1	Dean	1	37400-67000+10000	PB-4	47400	121818	144200-218200	14	144200
2	University Professor	27	37400-67000+10000	PB-4	47400	121818	144200-218200	14	144200
3	Associate Professor	39	37400-67000+9000	PB-4	46400	119248	131400-217100	13A	131400
4	Assistant Professor	74	15600-39100+6000	PB-3	21600	55512	57700-182400	10	57700
	Total =	141							

औपबधिक BIHAR ANIMAL SCIENCES UNIVERSITY, PATNA Revised 7th pay Structure of Teaching Post, Sanjay Gandhi Institute of Dairy Technology, Patna									
Sr No.	Sanctioned Post	No. of Sanction Post	Pay Band & Grade Pay	Pay Band	Basic pay with GP from 01.01.2016	Multiply 2.57 as per guide line	Pay Band 7th CPC	Level as per guide line	Revised Basic Pay 7th CPC as per guide line
1	Dean	1	37400-67000+ 10000	PB-4	47400	121818	144200-218200	14	144200
2	University Professor	3	37400-67000+ 10000	PB-4	47400	121818	144200-218200	14	144200
3	Associate Professor	21	37400-67000+ 9000	PB-4	46400	119248	131400-217100	13A	131400
4	Assistant Professor	23	15600-39100 + 6000	PB-3	21600	55512	57700-182400	10	57700
	Total =	48							

औपबन्धिक BIHAR ANIMAL SCIENCES UNIVERSITY, PATNA Revised 7th pay Structure of Teaching Post, College of Fisheries, Kishanganj									
Sr No.	Sanctioned Post	No. of Sanction Post	Pay Band & Grade Pay	Pay Band	Basic pay with GP from 01.01.2016	Multiply 2.57 as per guide line	Pay Band 7th CPC	Level as per guide line	Revised Basic Pay 7th CPC as per guide line
1	Dean	1	37400-67000+10000	PB-4	47400	121818	144200-218200	14	144200
2	University Professor	15	37400-67000+10000	PB-4	47400	121818	144200-218200	14	144200
3	Associate Professor	27	37400-67000+9000	PB-4	46400	119248	131400-217100	13A	131400
4	Assistant Professor	42	15600-39100 + 6000	PB-3	21600	55512	57700-182400	10	57700
5	Assistant Librarian	1	15600-39100+GP 6600	PB-3	22200	57054	67700-208700	11	67700
	Total =	86							

औपबन्धिक BIHAR ANIMAL SCIENCES UNIVERSITY (BASU), PATNA Revised 7th pay structure of BASU, Patna									
Administrative Post (A)									
Sl. No.	Sanction Post	No. of Sanction Post	Pay Band & Grade Pay	Pay Band	Basic pay with GP from 01.01.2016	Multiply 2.57 as per guide line	Pay Band 7th CPC	Level as per guide line	Revised Basic Pay 7th CPC as per guide line
1	Vice-Chancellor	1	75000-80000	HAG +	75000	192750	205400-224100	16	205400
2	Comptroller	1	37400-67000+GP 10000	PB-4	47400	121818	144200-218200	14	144200
3	Dy. Registrar (Acad. Exam. Adm. & Recruit)	3	37400-67000+GP 8700	PB-4	46100	118477	118500-214100	13	118500
4	Dy. Comptroller	2	37400-67000+GP 8700	PB-4	46100	118477	118500-214100	13	118500
5	Sr. Instrumentation Officer (CIF)	1	37400-67000+GP 8700	PB-4	46100	118477	118500-214100	13	118500
6	Estate Officer	1	37400-67000+GP 8700	PB-4	46100	118477	118500-214100	13	118500
7	Sr. System Analyst	1	37400-67000+GP 8700	PB-4	46100	118477	118500-214100	13	118500
8	Director Works and Plant (DWP)	1	37400-67000+GP 8700	PB-4	46100	118477	118500-214100	13	118500
9	System Analyst	1	15600-39100+GP 7600	PB-3	23200	59624	78800-209200	12	78800

10	Public Relation Officer	1	15600-39100+GP 7600	PB-3	23200	59624	78800-209200	12	78800
11	Dy. Estate Officer (Civil)	1	15600-39100+GP 7600	PB-3	23200	59624	78800-209200	12	78800
12	Dy. Estate Officer Electrical/Mech)	1	15600-39100+GP 7600	PB-3	23200	59624	78800-209200	12	78800
13	Secretary to Vice-Chancellor	1	15600-39100+GP 6600	PB-3	22200	57054	67700-208700	11	67700
14	Central Purchase Officer	1	15600-39100+GP 6600	PB-3	22200	57054	67700-208700	11	67700
15	Asstt. Registrar (Acad. Exam & ADM Recruit	4	15600-39100+GP 5400	PB-3	21000	53970	56100-177500	10	56100
16	Asstt. Comptroller (Operation, Plan & Budget, Central Purchase, Farm Operation, Audit	5	15600-39100+GP 5400	PB-3	21000	53970	56100-177500	10	56100
17	Jr. Instrumenttation Officer (CIF)	2	15600-39100+GP 5400	PB-3	21000	53970	56100-177500	10	56100
18	Asstt. Estate Officer (Civil)	2	15600-39100+GP 5400	PB-3	21000	53970	56100-177500	10	56100
19	Asstt. Estate Officer (Electrical/Mech.)	1	15600-39100+GP 5400	PB-3	21000	53970	56100-177500	10	56100
20	Law Officer	1	15600-39100+GP 5400	PB-3	21000	53970	56100-177500	10	56100
21	Estate Cum Security Officer	1	15600-39100+GP 5400	PB-3	21000	53970	56100-177500	10	56100
Total Administrative Post =		33							

Supporting Staff (B)

Sl. No.	Sanction Post	No. of Sanction Post	Pay Band & Grade Pay	Pay Band	Basic pay with GP from 01.01.2016	Multiply 2.57 as per guide line	Pay Band 7th CPC	Level as per guide line	Revised Basic Pay 7th CPC as per guide line
1	Security Officer	1	9300-34800+GP 4600	PB-2	13900	35723	44900-142400	7	44900
2	Accounts Asstt./Accounting Technician	25	9300-34800+GP 4600	PB-2	13900	35723	44900-142400	7	44900
3	Multy task Officer Asstt.	44	9300-34800+GP 4600	PB-2	13900	35723	44900-142400	7	44900
4	Section Officer Accounts	3	9300-34800+GP 4600	PB-2	13900	35723	44900-142400	7	44900

5	P.A.	9	9300-34800+GP 4600	PB-2	13900	35723	44900-142400	7	44900
6	Jr. Enginner (Civil)	8	9300-34800+GP 4600	PB-2	13900	35723	44900-142400	7	44900
7	Jr. Enginner (Electrical)	4	9300-34800+GP 4600	PB-2	13900	35723	44900-142400	7	44900
8	Receptionist care Taker	2	9300-34800+GP 4200	PB-2	13500	34695	35400-112400	6	35400
9	Security Supervisor	4	9300-34800+GP 4200	PB-2	13500	34695	35400-112400	6	35400
10	Artist	1	9300-34800+GP 4200	PB-2	13500	34695	35400-112400	6	35400
11	Electrician	3	5200-20200+GP 2400	PB-1	7600	19532	25500-81100	4	25500
12	Heavy Duty Vehicle Driver	2	5200-20200+GP 2400	PB-1	7600	19532	25500-81100	4	25500
13	Photographer	2	5200-20200+GP 2000	PB-1	7200	18504	21700-69100	3	21700
14	Mechanic	2	5200-20200+GP 2000	PB-1	7200	18504	21700-69100	3	21700
15	Light Vehicle Driver	6	5200-20200+GP 2000	PB-1	7200	18504	21700-69100	3	21700
16	Carpenter	1	5200-20200+GP 2000	PB-1	7200	18504	21700-69100	3	21700
17	Plumber	1	5200-20200+GP 2000	PB-1	7200	18504	21700-69100	3	21700
18	Multi Task Worker	52	5200-20200+GP 1800	PB-1	7000	17990	18000-56900	1	18000
Total Supporting Officer/Staff		170							
Grand Total (A+B) =		203							

<p style="text-align: center;">औपबधिक BIHAR ANIMAL SCIENCES UNIVERSITY, PATNA Revised 7th pay structure of Non- Teaching Staff, Bihar Veterinary College, Patna</p>									
Sl. No.	Sanction Post	No. of Sanction Post	Pay Band & Grade Pay	Pay Band	Basic pay with GP from 01.01.2016	Multipl y 2.57 as per guide line	Pay Band 7th CPC	Level as per guide line	Revised basic Pay 7th CPC as per guide line
Academic cum Administrative Post									
1	Research and Information Officer	1	15600-39200+GP 6600	PB-3	22200	57054	67700-208700	11	67700
3	Procurement Officer	1	15600-39200+GP 6600	PB-3	22200	57054	67700-208700	11	67700
4	Commercial Production Manager	1	9300-34800+GP 5600/5400	PB-2	14900	38293	56100-177500	9	53100
5	Quality Control Manager	1	9300-34800+GP 5600/5400	PB-2	14900	38293	56100-177500	9	53100
6	Meat Testing Assistant	1	9300-34800+GP 5400	PB-2	14700	37779	56100-177500	9	53100

7	Farm Manager Operation	2	9300-34800+GP 5400	PB-2	14700	37779	56100-177500	9	53100
8	O.T. Master/O.T. Technician	1	9300-34800+GP 5400	PB-2	14700	37779	56100-177500	9	53100
9	Assistant Registrar	1	9300-34800+GP 4800	PB-2	14100	36237	47600-151100	8	47600
10	Assistant Comptroller	1	9300-34800+GP 4800	PB-2	14100	36237	47600-151100	8	47600
11	P.S.	1	9300-34800+GP 4800	PB-2	14100	36237	47600-151100	8	47600
12	Assistant	12	9300-34800+GP 5400	PB-2	14700	37779	56100-177500	9	53100
13	Artist cum Photographer	3	9300-34800+GP 4200	PB-2	13500	34695	35400-112400	6	35400
14	Audio Visual Technician	1	9300-34800+GP 4200	PB-2	13500	34695	35400-112400	6	35400
15	Head Clerk	1	9300-34800+GP 4200	PB-2	13500	34695	35400-112400	6	35400
16	Office Superintendant	1	9300-34800+GP 4200	PB-2	13500	34695	35400-112400	6	35400
17	Accountant	1	9300-34800+GP 4200	PB-2	13500	34695	35400-112400	6	35400
18	Librarian	2	9300-34800+GP 4200	PB-2	13500	34695	35400-112400	6	35400
19	JRA	1	9300-34800+GP 4200	PB-2	13500	34695	35400-112400	6	35400
20	Administrative Assistant/A.A.O	3	9300-34800+GP 4200	PB-2	13500	34695	35400-112400	6	35400
21	Junior Enginner	1	9300-34800+GP 4200	PB-2	13500	34695	35400-112400	6	35400
22	Molecular Lab. Assitant	1	9300-34800+GP 4200	PB-2	13500	34695	35400-112400	6	35400
23	Cyto-imuno La. Assistant	1	9300-34800+GP 4200	PB-2	13500	34695	35400-112400	6	35400
24	Cashier	2	5200-20200+GP 2800	PB-1	8000	20560	29200-92300	5	29200
25	Imaging Technician	1	5200-20200+GP 2800	PB-1	8000	20560	29200-92300	5	29200
26	Feed Plant Technician	1	5200-20200+GP 2800	PB-1	8000	20560	29200-92300	5	29200
27	Laboratory Technician	26	5200-20200+GP 2800	PB-1	8000	20560	29200-92300	5	29200
28	In-charge Medical Store	1	5200-20200+GP 2800	PB-1	8000	20560	29200-92300	5	29200
29	Mechanic	1	5200-20200+GP 2800	PB-1	8000	20560	29200-92300	5	29200
30	UDC	17	5200-20200+GP 2400	PB-1	7600	19532	25500-81100	4	25500
31	Typist cum Clerk	5	5200-20200+GP 2400	PB-1	7600	19532	25500-81100	4	25500
32	Assistant to Artist	1	5200-20200+GP 2400	PB-1	7600	19532	25500-81100	4	25500
33	Dairy Overssers	1	5200-20200+GP 2400	PB-1	7600	19532	25500-81100	4	25500
34	Record Keeper	2	5200-20200+GP 2400	PB-1	7600	19532	25500-81100	4	25500
35	Data and Console Operator	1	5200-20200+GP 2400	PB-1	7600	19532	25500-81100	4	25500
36	Data Analyst	2	5200-20200+GP 2400	PB-1	7600	19532	25500-81100	4	25500
37	Store Keeper (ILFC)	1	5200-20200+GP 2400	PB-1	7600	19532	25500-81100	4	25500
38	Store Keeper cum Store Assistant	1	5200-20200+GP 2400	PB-1	7600	19532	25500-81100	4	25500
39	Talkie Operator	1	5200-20200+GP 2400	PB-1	7600	19532	25500-81100	4	25500
40	Lab. Assistant	12	5200-20200+GP 2400	PB-1	7600	19532	25500-81100	4	25500

41	Postmortem Technician	1	5200-20200+GP 2000	PB-1	7200	18504	21700-69100	3	21700
42	Technical Assistant	1	5200-20200+GP 1900	PB-1	7100	18247	19900-63200	2	19900
43	Registration Assistant	1	5200-20200+GP 1900	PB-1	7100	18247	19900-63200	2	19900
44	Driver	4	5200-20200+GP 1900	PB-1	7100	18247	19900-63200	2	19900
45	Carpenter	2	5200-20200+GP 1900	PB-1	7100	18247	19900-63200	2	19900
46	Human Compounder	1	5200-20200+GP 1900	PB-1	7100	18247	19900-63200	2	19900
47	Riding Master	1	5200-20200+GP 1900	PB-1	7100	18247	19900-63200	2	19900
48	Sawar Subedar	1	5200-20200+GP 1900	PB-1	7100	18247	19900-63200	2	19900
49	Plumber	1	5200-20200+GP 1900	PB-1	7100	18247	19900-63200	2	19900
50	Livestock Assistant cum Compounder	1	5200-20200+GP 1900	PB-1	7100	18247	19900-63200	2	19900
51	Compounder	1	5200-20200+GP 1900	PB-1	7100	18247	19900-63200	2	19900
52	P.T.I.	1	5200-20200+GP 1900	PB-1	7100	18247	19900-63200	2	19900
53	OT Assistant	1	5200-20200+GP 1900	PB-1	7100	18247	19900-63200	2	19900
54	Curator-cum-Museum/Speciman Technician	1	5200-20200+GP 1900	PB-1	7100	18247	19900-63200	2	19900
55	Andrology Lab Technician	1	5200-20200+GP 1900	PB-1	7100	18247	19900-63200	2	19900
56	Pharmacist/Compounder	2	5200-20200+GP 1900	PB-1	7100	18247	19900-63200	2	19900
57	Ward Overseer	1	5200-20200+GP 1650/1800	PB-1	7000	17990	18000-56900	1	18000
58	Head Mali	1	5200-20200+GP 1650/1800	PB-1	7000	17990	18000-56900	1	18000
59	Gardener	2	5200-20200+GP 1650/1800	PB-1	7000	17990	18000-56900	1	18000
60	Incubation Assistant	4	5200-20200+GP 1650/1800	PB-1	7000	17990	18000-56900	1	18000
63	Lab. Attendant	17	5200-20200+GP 1650/1800	PB-1	7000	17990	18000-56900	1	18000
64	Ward Boy cum Room Attendant	4	5200-20200+GP 1650/1800	PB-1	7000	17990	18000-56900	1	18000
65	Durban	7	5200-20200+GP 1650/1800	PB-1	7000	17990	18000-56900	1	18000
66	Security guard	4	5200-20200+GP 1650/1800	PB-1	7000	17990	18000-56900	1	18000
67	Daftary	1	5200-20200+GP 1650/1800	PB-1	7000	17990	18000-56900	1	18000
68	Sweeper cum Attendant	35	5200-20200+GP 1650/1800	PB-1	7000	17990	18000-56900	1	18000
69	Head Dom	1	5200-20200+GP 1650/1800	PB-1	7000	17990	18000-56900	1	18000
70	Milk Recorder	1	5200-20200+GP 1650/1800	PB-1	7000	17990	18000-56900	1	18000
71	Gwala	5	5200-20200+GP 1650/1800	PB-1	7000	17990	18000-56900	1	18000
72	Animal Attendant	9	5200-20200+GP 1650/1800	PB-1	7000	17990	18000-56900	1	18000
73	Cleaner	1	5200-20200+GP 1650/1800	PB-1	7000	17990	18000-56900	1	18000
74	Sycc	10	5200-20200+GP 1650/1800	PB-1	7000	17990	18000-56900	1	18000
75	Library Attendant	1	5200-20200+GP 1650/1800	PB-1	7000	17990	18000-56900	1	18000
76	Dog Ward Overseer	1	5200-20200+GP 1650/1800	PB-1	7000	17990	18000-56900	1	18000

77	Computer Programmer	1	9300-34800+GP 5400	PB-1	14700	37779	56100-177500	9	53100
78	Computer Operator	24	5200-20200+GP 2400	PB-1	7600	19532	25500-81100	4	25500
79	Driver	7	5200-20200+GP 1900	PB-1	7100	18247	19900-63200	2	19900
80	Tractor Driver	1	5200-20200+GP 1900	PB-1	7100	18247	19900-63200	2	19900
Total =		274							

औपबधिक BIHAR ANIMAL SCIENCES UNIVERSITY, PATNA Revised 7th pay Structure of Non- Teaching Staff, Sanjay Gandhi Institute of Dairy Technology (SGIDT), Patna									
Sl. No.	Sanction Post	No. of Sanction Post	Pay Band & Grade Pay	Pay Band	Basic pay with GP from 01.01.2016	Multiply 2.57 as per guide line	Pay Band 7th CPC	Level as per guide line	Revised basic Pay 7th CPC as per guide line
Academic cum Administrative Post									
1	Assistant Comptroller	1	9300-34800+GP 4800	PB-2	14100	36237	47600-151100	8	47600
2	Technical Assistant	19	9300-34800+GP 4200	PB-2	13500	34695	35400-112400	6	35400
3	Steno Grapher	9	5200-20200+GP 2400	PB-1	7600	19532	25500-81100	4	25500
4	Head Clerk	2	5200-20200+GP 2800	PB-1	8000	20560	29200-92300	5	29200
5	Office Clerk	2	5200-20200+GP 2400	PB-1	7600	19532	25500-81100	4	25500
6	Typist Clerk	4	5200-20200+GP 2400	PB-1	7600	19532	25500-81100	4	25500
7	Cashier	1	5200-20200+GP 2400	PB-1	7600	19532	25500-81100	4	25500
8	Store Clerk	9	5200-20200+GP 2400	PB-1	7600	19532	25500-81100	4	25500
9	Duplicating Operator	1	5200-20200+GP 1900	PB-1	7100	18247	19900-63200	2	19900
10	Daftari	1	4440-7440+GP 1400	PB-1	5840	15009	18000-56900	1	18000
11	Peon	4	4440-7440+GP 1650	PB-1	6090	15651	18000-56900	1	18000
12	Choukidaar	4	4440-7440+GP 1300	PB-1	5740	14752	18000-56900	1	18000
13	Driver	3	5200-20200+GP 1900	PB-1	7100	18247	19900-63200	2	19900
14	Sweeper	4	4440-7440+GP 1300	PB-1	5740	14752	18000-56900	1	18000
15	Machenic	3	5200-20200+GP 2800	PB-1	8000	20560	29200-92300	5	29200
16	Helper Cleener	3	4440-7440+GP 1650	PB-1	6090	15651	18000-56900	1	18000
17	Lab. Attendant	40	4440-7440+GP 1650	PB-1	6090	15651	18000-56900	1	18000
Total =		110							

<p style="text-align: center;">औपबधिक BIHAR ANIMAL SCIENCES UNIVERSITY, PATNA Revised 7th pay Non- Teaching Staff, College of Fisheries, Kisanganj</p>									
Sl. No.	Sanction Post	No. of Sanction Post	Pay Band & Grade Pay	Pay Band	Basic pay with GP from 01.01.2016	Multiply 2.57 as per guide line	Pay Band 7th CPC	Level as per guide line	Revised basic Pay 7th CPC as per guide line
Academic cum Administrative Post									
1	Assistant Enginner	1	15600-39100+GP 6600	PB-3	22200	57054	67700-208700	11	67700
2	Student Welfare Officer	1	15600-39100+GP 6600	PB-3	22200	57054	67700-208700	11	67700
3	Medical Officer	1	15600-39100+GP 5400	PB-3	21000	53970	56100-177500	10	56100
4	Assistant Comptroller	1	15600-39100+GP 5400	PB-3	21000	53970	56100-177500	10	56100
5	P.S to Dean	1	9300-34800+GP 4800	PB-2	14100	36237	47600+151100	8	47600
6	Junior Engineer	1	9300-34800+GP 4600	PB-2	13900	35723	44900-142400	7	44900
7	Accountant	2	9300-34800+GP 4600	PB-2	13900	35723	44900-142400	7	44900
8	Multi Task Office Assistant	24	9300-34800+GP 4200	PB-2	13500	34695	37400-112400	6	35400
9	Library Assistant	1	9300-34800+GP 4200	PB-2	13500	34695	37400-112400	6	35400
10	Farm Manager	1	9300-34800+GP 4200	PB-2	13500	34695	37400-112400	6	35400
11	Hatchery Manager	2	9300-34800+GP 4200	PB-2	13500	34695	37400-112400	6	35400
12	IT Technician-cum-Website Manager	2	9300-34800+GP 4200	PB-2	13500	34695	37400-112400	6	35400
13	Lab Equipment Maintenance Technician	1	9300-34800+GP 4200	PB-2	13500	34695	37400-112400	6	35400
14	Wet Lab Supervisor	2	9300-34800+GP 4200	PB-2	13500	34695	37400-112400	6	35400
15	Cashier	1	5200-20200+GP 2800	PB-1	8000	20560	29200-92300	5	29200
16	Livestock/Farm/Lab Assistant	24	5200-20200+GP 1900	PB-1	7100	18247	19900-63200	2	19900
17	Audio Visual Technician-cum-Photographer	1	5200-20200+GP 2400	PB-1	7600	19532	25500-81100	4	25500
18	Physical Training Instructor (PTI)-cum-Hostel Care Taker	4	5200-20200+GP 2400	PB-1	7600	19532	25500-81100	4	25500

19	Plumber	2	5200-20200+GP 2000	PB-1	7200	18504	21700-69100	3	21700
20	Medical Lab Attendant	3	5200-20200+GP 2000	PB-1	7200	18504	21700-69100	3	21700
21	Carpenter	2	5200-20200+GP 2000	PB-1	7200	18504	21700-69100	2	21700
22	Clerk-cum-Storekeeper	3	5200-20200+GP 1900	PB-1	7100	18247	19900-63200	2	19900
23	Electrician	3	5200-20200+GP 1900	PB-1	7100	18247	19900-63200	2	19900
24	Compounder	1	5200-20200+GP 1900	PB-1	7100	18247	19900-63200	2	19900
25	Driver	6	5200-20200+GP 1900	PB-1	7100	18247	19900-63200	2	19900
26	Lab. Attendant	12	5200-20200+GP 1900	PB-1	7100	18247	19900-63200	2	19900
27	Pump Operator	3	5200-20200+GP 1900	PB-1	7100	18247	19900-63200	2	19900
28	Library Attendant	2	5200-20200+GP 1800	PB-1	7000	17990	18000-56900	1	18000
29	Security Guard	16	5200-20200+GP 1800	PB-1	7000	17990	18000-56900	1	18000
30	Multi Tasking Staff	50	5200-20200+GP 1800	PB-1	7000	17990	18000-56900	1	18000
31	Fisherman	10	5200-20200+GP 1800	PB-1	7000	17990	18000-56900	1	18000
	Total =	184							

सं० 15/एम 1-105/2017-505

शिक्षा विभाग

संकल्प

24 फरवरी 2019

विषय :- बिहार राज्यान्तर्गत कुल 09 सरकारी महाविद्यालयों कमशः अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय राजगीर (नालन्दा), अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, बेनीपुर (दरभंगा), अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, वायसी (पूर्णियाँ), अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, पकडीदयाल (पूर्वी चम्पारण), अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, शिवहर (शिवहर), अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, बगहा (पश्चिम चम्पारण), अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, धमदाहा (पूर्णियाँ), अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, नौहट्टा, डेहरी (रोहतास) तथा अरवल जिला मुख्यालय में सरकारी डिग्री महाविद्यालय, अरवल के शैक्षणिक सत्र 2019-20 से संचालन की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

राज्य में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि किया जाना आवश्यक है। इसके लिए राज्य में नये महाविद्यालयों की स्थापना किया जाना अपेक्षित है। उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णय के अनुसार वैसे अनुमण्डल जहाँ पूर्व से अंगीभूत महाविद्यालय संचालित नहीं है, वहाँ एक-एक सरकारी डिग्री महाविद्यालय खोलने की योजना है।

2. पूर्व में मंत्रिपरिषद के निर्णय से विशेष परिस्थिति में रोहतास जिलान्तर्गत सुदूर अवस्थित नौहट्टा प्रखण्ड मुख्यालय में तथा पूर्णियाँ के धमदाहा अनुमण्डल में एक-एक अनुमण्डलीय सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिन्हें कमशः अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, नौहट्टा, डेहरी, (रोहतास) तथा अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, धमदाहा (पूर्णियाँ) के नाम से संचालित किया जाना है।

3. नवस्थापित अरवल जिला मुख्यालय में पूर्व से कोई अंगीभूत महाविद्यालय संचालित नहीं होने के कारण वहाँ पर भी एक सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित किया जाना आवश्यक है।

4. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रथम चरण में राज्य में कुल 09 सरकारी महाविद्यालयों कमशः (1). अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय राजगीर (नालन्दा) (2). अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, बेनीपुर (दरभंगा) (3). अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, वायसी (पूर्णियाँ) (4). अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, पकड़ीदयाल (पूर्वी चम्पारण) (5). अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, शिवहर (शिवहर) (6). अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, बगहा (पश्चिम चम्पारण) (7). अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, धमदाहा (पूर्णियाँ) (8). अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, नौहट्टा, डेहरी (रोहतास) तथा (9). अरवल जिला मुख्यालय में सरकारी डिग्री महाविद्यालय, अरवल को शैक्षणिक सत्र 2019-20 से संचालन की अनुमति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है।

5. उपरोक्त वर्णित 09 सरकारी महाविद्यालय का संचालन संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा चयनित भूखण्डों पर की जाएगी, जिनकी विवरणी निम्नवत् है :-

क्र०	प्रस्तावित सरकारी डिग्री महाविद्यालय	अंचल	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	राजगीर (नालन्दा)	राजगीर	474	27	288	4.66 एकड
2	वायसी (पूर्णियाँ)	वायसी	414	456	282, 283, 284	11.92 एकड
3	पकड़ी दयाल (पूर्वी चम्पारण)	मधुबन	81	78	175, 179	8.15 एकड
4	बेनीपुर (दरभंगा)	बेनीपुर	154	946	815, 817, 818	5 एकड
5	बगहा (प० चम्पारण)	बगहा -1	239	728 / 01	384 / 1	5 एकड
6	शिवहर (शिवहर)	पिपराही	155	315	218	12.13 एकड
7	अरवल जिला मुख्यालय (अरवल)	करपी	112	283, 261	392, 112	5.86 एकड
8	धमदाहा (पूर्णियाँ)	धमदाहा	120	1183, 1184	2852, 2791, 2293	10 एकड
9	नौहट्टा प्रखण्ड मुख्यालय (रोहतास)	नौहट्टा	648	121	693	10 एकड

6. ये सभी महाविद्यालय पूर्णतः सरकारी महाविद्यालय होंगे, परंतु उनमें नामांकित छात्रों के पंजीकरण एवं परीक्षा के लिए ये राज्य में जिस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में अवस्थित होंगे, उस विश्वविद्यालय से उनका संबंधन (Affiliation) होगा।

7. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जनसाधारण की सूचना हेतु अगले अंक में प्रकाशित किया जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा, विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 1-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>